अप्रैल-मई-जून, 2023 (संयुक्तांक), वर्ष 32, अंक 46-48

उत्तर प्रदेश संदेश

"हम लोग केवल उन लोगों को रोकना चाहते हैं,
जो लोग देश को रोकना चाहते हैं।
ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है
और इसी के आधार पर देश की नींव बनती है।"

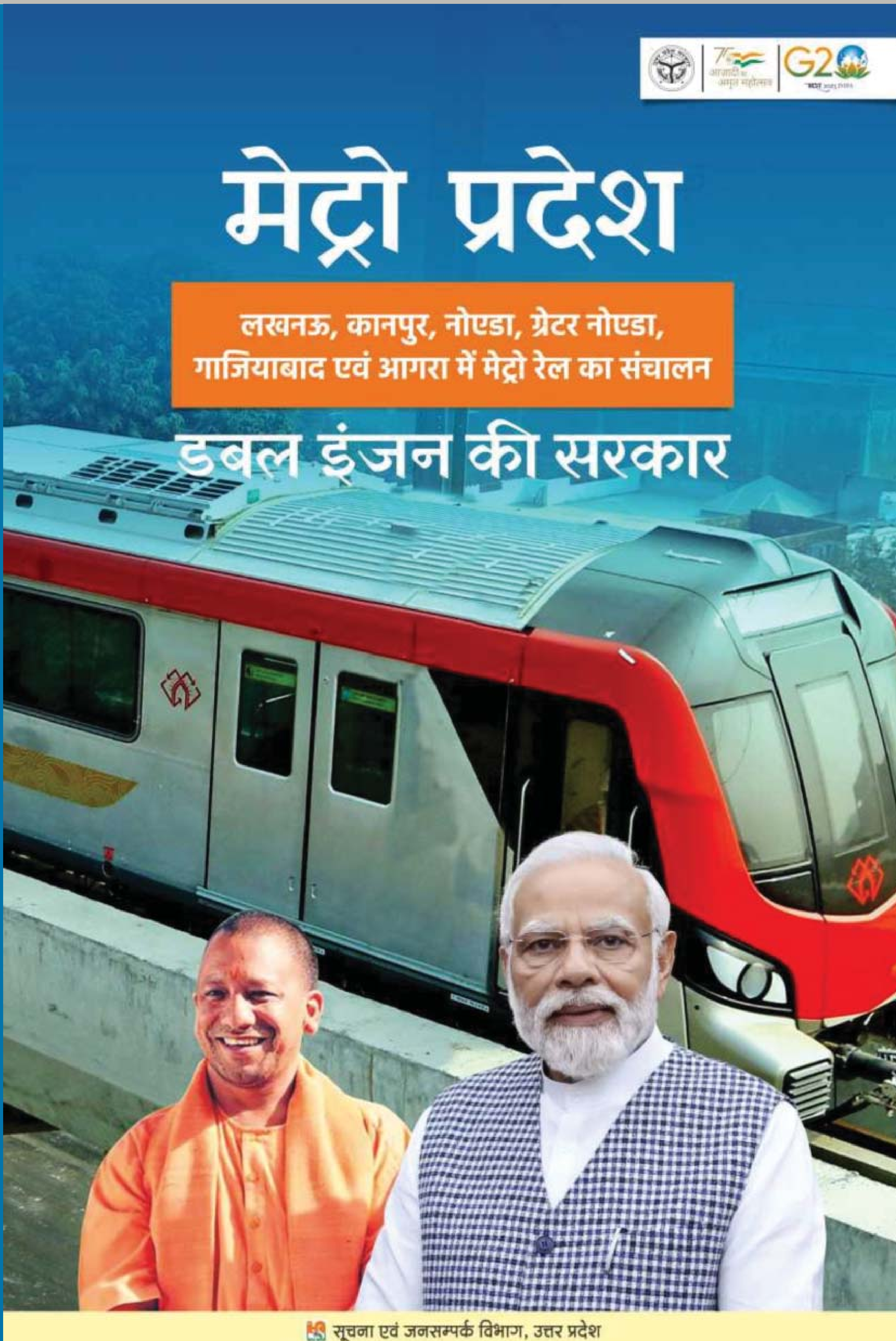
मेट्रो प्रदेश
लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा,
गाजियाबाद एवं आगरा में मेट्रो रेल का संचालन
डबल इंजन की सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

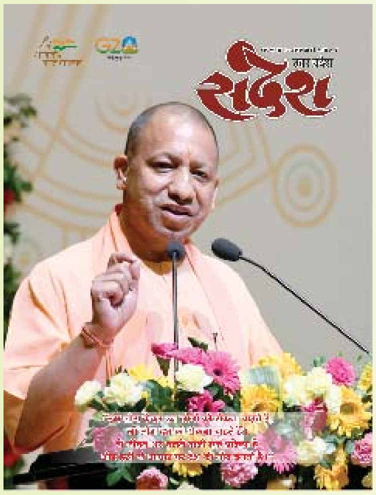

अप्रैल, मई, जून, 2023 तक (संयुक्तांक), वर्ष 32, अंक 46, 47, 48

उत्तर प्रदेश
संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :
संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव, सूचना

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
शिशिर
सूचना निदेशक

सम्पादकीय परामर्श :
अंशुमान राम त्रिपाठी
अपर निदेशक, सूचना

सम्पादक :
कुमकुम शर्मा
उपनिदेशक, सूचना

सम्पादकीय सहयोग :
दिनेश कुमार गुप्ता
उपसम्पादक
महेन्द्र कुमार
सूचना अधिकारी

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ
ईमेल : upsandesh20@gmail.com
दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522–2239132–33, 2236198, 2239011

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं हैं। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

एक विरल व्यक्तित्व को याद करते हुए	- नरेन्द्र मोदी	3
स्वस्थ भारत का संकल्प	- मनसुख मांडविया	6
निवेश और रोजगार का केंद्र बनेगा प्लास्टिक पार्क	- प्रद्युम्न तिवारी	10
गरीबी के मकड़जाल से मुक्त होता प्रदेश	- डॉ. रविशंकर पाण्डेय	13
कुशल नेतृत्व से विकास की ऊँचाइयों को छूता प्रदेश	- अंजुम इलाही	18
चौपालों में होती कुछ काम की बातें और निरन्तर...	- सियाराम पाण्डेय 'शान्त'	22
श्रीअन्न से समृद्ध होता प्रदेश	- डॉ. शिवराम पाण्डेय	26
साकार होते सपनों का शहर : गोरखपुर	- यशोदा श्रीवास्तव	30
भूजल संरक्षण को बढ़ावा	- डॉ. बलकार सिंह	33
विकास और पारदर्शिता का अद्भुत योग	- गोलेश स्वामी	36
कानून-व्यवस्था बनी नज़ीर	- जितेन्द्र शुक्ला	39
महिलाओं का सर्वांगीण विकास	- डॉ. अजय कुमार मिश्रा	42
सांस्कृतिक पुनरुत्थान से समृद्ध विरासत को संरक्षण	- सुरेन्द्र अग्निहोत्री	45
हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध	- राघवेन्द्र प्रताप सिंह	48
ऐतिहासिक इमारतों व किलों के जीर्णोद्धार से खुले...	- केवलराम	52
स्मार्ट सिटी के तेज प्रयास, नगरवासियों के लिए ख़ास	- अंजु अग्निहोत्री	54
ट्रांसफॉर्म हो रहा है उत्तर प्रदेश	- डॉ. ए.के. मिश्रा	57
न्यायिक सुधार की अहम कड़ी ग्राम न्यायालय	- एस.आर. पाण्डेय	61
वर्ल्ड क्लास सड़कों से सुरक्षित हुआ सफर	- सुयश मिश्रा	66
आत्मनिर्भर बनती महिलाएं	- मुकुल मिश्रा	69
शिक्षा से बदली यूपी की सूरत	- विमल किशोर पाठक	73
गन्ना किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्य	- रजनीश वैश्य	77
विकास के नए सोपान रचती यूपी सरकार	- एम. मिश्रा	81
ग्रामीण पर्यटन : मनोरंजन के साथ रोज़गार भी	- प्रदीप श्रीवास्तव	85
हर घर जल योजना से स्वच्छ जल की सौगात	- विदर्भ कुमार	90
खेलो इंडिया से खिलाड़ियों ने दिखाया दमख़म	- सरिता त्रिपाठी	92

सम्पादकीय

इतिहास के निर्माण में किसी न किसी इतिहास पुरुष का सक्रिय योगदान होता है, ऐसे लोग सदियों में जन्म लेते हैं। उत्तर प्रदेश इन दिनों ऐसे ही अभूतपूर्व सृजन का साक्षी है जो इससे पहले कभी नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश सरकार के साढ़े छः साल पूरे होने में कुछ ही महीने शेष रह गये हैं। बीते इन सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में सरकार द्वारा अनेक बड़े फैसले लिए गये। इनमें से अनेक बहुत चर्चित हुये जैसे लव जेहाद के खिलाफ कानून लाना सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान करने वालों की सम्पत्ति कुर्क कर नुकसान की भरपाई का अध्यादेश लाना और सूबे के माफियाओं की सम्पत्ति ज़ब्त करना आदि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत अधिकतम शौचालयों का निर्माण करते हुये प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कराया गया है।

कोविड में कुशल स्वास्थ्य प्रबन्धन से लेकर आज तक सरकार गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर शान्ति व्यवस्था और दंगा मुक्त राज्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को देश भर में चमका दिया है। यही वजह कि 36 सालों के रिकार्ड को तोड़ते हुये एक बार फिर वे सरकार बनाने में सफल रहे और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व एक बार पुनः सफल हाथों में आ गया। मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स को गुंडा टैक्स की वसूली से मुक्ति दिलाई। आज ऐसे लोगों के हौसले पस्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ ने पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत लोगों के खाते में सीधे ऋण ट्रांसफर किया है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में अकेले उत्तर प्रदेश के 15 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पी. एम. स्वनिधि योजना का लाभ उठा रहे हैं जो हमारे लिए गर्व की बात है इन्हीं वेन्डर्स को पहले अपना काम शुरू करने के लिए साहूकार से उधार लेना होता था जो बाद में इनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे। आज आत्मसम्मान के साथ लोग अपना रोज़गार शुरू कर पा रहे हैं।

इस अंक में अविस्मरणीय व्यक्तित्व मदन दासदेवी जी को याद करते हुये प्रधानमंत्री के सुन्दर लेख के साथ मनसुख मांडविया, प्रद्युम्न तिवारी, डॉ. रवि शंकर पाण्डेय, अंजुम इलाही, सियाराम पाण्डेय शान्त, डॉ. शिवराम पाण्डेय, यशोदा श्रीवास्तव, डॉ. बलकार सिंह आदि के महत्वपूर्ण लेख हैं।

अंक आपको कैसे लग रहे हैं अवश्य बताइयेगा।

सम्पादक

मदन दास देवी

एक विरल व्यक्तित्व को याद करते हुए

—नरेन्द्र मोदी

देश ने हाल ही में मदन दास देवी जी जैसी महान विभूति को खोया है। उनके जाने से मेरे साथ ही लाखों कार्यकर्ताओं को जो गहरा दुःख हुआ, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आज मन को समझाना मुश्किल है कि मदन दास जी हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन मदन दास जी जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के विचार और मूल्य सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।

मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मदन दास जी के साथ वर्षों तक करीब से काम करने का अवसर मिला। मैंने उनकी सादगी और मृदुभाषी स्वभाव को भी बहुत नज़दीक से जाना। उनका जीवन बहुत सहज था। वह पूरी तरह से संगठन को समर्पित व्यक्ति थे और मेरे पास भी लंबे समय तक संगठन के कार्यों का दायित्व रहा है। इसलिए अधिकतर समय हमारे बीच की बातचीत संगठन का विस्तार, व्यक्तित्व निर्माण जैसे पहलुओं पर केंद्रित रहती थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि वह मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वह तो महाराष्ट्र के सोलापुर के पास के एक गांव से आते हैं, लेकिन उनके पूर्वज गुजरात के थे। वैसे यह उन्हें पता नहीं था कि गुजरात में कहां से थे। मैंने उन्हें बताया कि देवी उपनाम से मेरे एक शिक्षक थे, जो विसनगर के रहने वाले थे। बाद में मदन दास जी विसनगर गए और मेरे गांव वडनगर भी गए। वह मुझसे अधिकतर समय गुजराती में ही बातचीत करते थे।

आज जब हमारा लोकतंत्र जीवंत है, युवा आत्मविश्वास से भरे हैं और देश उम्मीदों, आशाओं और आकांक्षाओं से भरा है, तब मदन दास देवी जी जैसी विभूतियों को याद करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका पूरा जीवन समाज की सेवा और राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित रहा।

मदन दास जी धैर्यपूर्वक कार्यकर्ताओं की बातों को सुना

करते थे और घंटों तक चली चर्चा को वह बहुत कम वाक्यों में संक्षेप में समेट लेते थे। उनकी एक विशेषता थी कि वह शब्दों से परे जाकर कार्यकर्ता की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ लेते थे।

मदन दास जी की जीवन यात्रा दर्शाती है कि कैसे उन्होंने स्वयं को पीछे रखकर और सामान्य कार्यकर्ताओं को जोड़कर बड़ी–बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग थी, इसलिए वह चाहते तो आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य कुछ और ही था। उन्होंने राष्ट्रनिर्माण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया।

मदन दास जी की जीवन यात्रा दर्शाती है कि कैसे उन्होंने स्वयं को पीछे रखकर और सामान्य कार्यकर्ताओं को जोड़कर बड़ी–बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग थी, इसलिए वह चाहते तो आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य कुछ और ही था। उन्होंने राष्ट्रनिर्माण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। भारत के युवाओं पर मदन दास जी को अटूट भरोसा था। वह देश भर के युवाओं को आपस में जोड़ने की क्षमता रखते थे। उन्होंने अपने जीवन का लंबा कार्यकाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। मदन दास जी अपनी इस यात्रा में यशवंत राव केलकर जी से प्रभावित रहे, जिनके बारे में वह अक्सर बातें किया करते थे। मदन दास जी का हमेशा जोर रहता था कि एबीवीपी के कामों में अधिक से अधिक छात्राओं की भागीदारी हो, और न सिर्फ ये भागीदारी तक सीमित रहे, बल्कि छात्राएं गतिविधियों का नेतृत्व करें। वह अक्सर कहते थे कि जब छात्राएं किसी सामूहिक गतिविधि में शामिल होती हैं तो वह प्रयास और ज्यादा संवेदनशील बन जाता है। विद्यार्थियों से मदन दास जी का गहरा लगाव था और वह अक्सर छात्रावासों में विद्यार्थियों के बीच घुल–मिल जाते थे। आयु में फर्क होने के बावजूद वह नई पीढ़ी के साथ बहुत सहजता से तालमेल बिठा लेते थे। वह विद्यार्थियों के बीच हमेशा ऐसे काम करते रहे, जैसे जल

मदन दास जी के साथ प्रधानमंत्री

में कमल। विद्यार्थियों के बीच रहकर भी वह कभी छात्र राजनीति का हिस्सा नहीं बने।

सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कई ऐसे लोग हैं, जिनके जीवन को गढ़ने में मदन दास जी ने कभी यह प्रकट नहीं किया, क्योंकि यह उनके स्वभाव में ही नहीं था।

आजकल लोगों, प्रतिभाओं और कौशल के प्रबंधन के विचार काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। मदन दास जी यह बखूबी समझ लेते थे कि किस व्यक्ति में किस तरह का कौशल है और उसकी प्रतिभा संगठन के हित में कैसे काम आ सकती है। उनमें यह ख़ासियत थी कि वे लोगों का उनकी क्षमताओं और प्रतिभा के अनुरूप ही दायित्व सौंपते थे। जब भी किसी कार्यकर्ता के पास कोई नया विचार होता था, तो उसकी हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वह मदन दास जी के साथ साझा करे। इसकी एक वजह यह थी कि मदन दास जी नए विचारों को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके साथ काम करने वाले लोग खुद ही प्रेरित होते थे, इस कारण से उनके नेतृत्व में न सिर्फ संगठनों का बहुत तेजी से विकास और विस्तार हुआ, बल्कि संगठन कहीं अधिक प्रभावी और सशक्त बने।

मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मदन दास जी के साथ वर्षों तक करीब से काम करने का अवसर मिला। मैंने उनकी सादगी और मृदुभाषी स्वभाव को भी बहुत नज़दीक से जाना। उनका जीवन बहुत सहज था। वह पूरी तरह से संगठन को समर्पित व्यक्ति थे और मेरे पास भी लंबे समय तक संगठन के कार्यों का दायित्व रहा है। इसलिए अधिकतर समय हमारे बीच की बातचीत संगठन का विस्तार, व्यक्ति निर्माण जैसे पहलुओं पर केंद्रित रहती थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि वह मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वह तो महाराष्ट्र के सोलापुर के पास के एक गांव से आते हैं, लेकिन उनके पूर्वज गुजरात के थे। वैसे यह उन्हें पता नहीं था कि गुजरात में कहां से थे। मैंने उन्हें बताया कि देवी उपनाम से मेरे एक शिक्षक थे, जो विसनगर के रहने वाले थे। बाद में मदन दास जी विसनगर गए और मेरे गांव वडनगर भी गए। वह मुझसे अधिकतर समय गुजराती में ही बातचीत करते थे।

मदन दास जी संपर्क को लेकर बहुत सेलेक्टिव थे। किससे मिलना, कब मिलना और जब मिलूंगा तो उससे क्या बात करना और इसमें कितना समय जाएगा, इन सबकी वह योजना बनाते थे। मदन दास जी के जो प्रवास और कार्यक्रम होते थे, उनमें वह कभी भी कार्यकर्ताओं पर बोझ नहीं बनते थे।

मैं अंतिम समय तक सतत उनके संपर्क में रहा। मैं हाल में जब भी उनको फोन करता था तो वह चार बार पूछने के बाद ही अपनी बीमारी के बारे में बात करते थे। अन्यथा वह हंसकर टाल जाते थे। बीमारी में भी उनके मन में हमेशा यह भाव रहता था कि मैं समाज के लिए, देश के लिए क्या करूं।

मदन दास जी का अकादमिक रिकॉर्ड काफी शानदार था। जब भी वह कुछ अच्छा पढ़ते थे, तो उसे उस विषय से संबंधित लोगों को भेज देते थे। मुझे अक्सर ऐसी चीजें उनसे प्राप्त होती थीं। अर्थशास्त्र और नीतिगत मामलों की वह बहुत गहरी समझ रखते थे। मदन दास जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी, जिसके प्रत्येक नागरिक के लिए आत्मनिर्भरता जीवन की वास्तविकता हो। एक ऐसे समाज का निर्माण हो, जहां सम्मान, सशक्तीकरण और सामूहिक समृद्धि की भावना हो। आज भारत एक के बाद एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, इसे देखकर उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता।

आज जब हमारा लोकतंत्र जीवंत है, युवा आत्मविश्वास से भरे हैं और देश उम्मीदों, आशाओं और आकांक्षाओं से भरा है, तब मदन दास देवी जी जैसी विभूतियों को याद करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका पूरा जीवन समाज की सेवा और राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित रहा। •

साभार– (अमर उजाला 6 अगस्त, 2023)

स्वस्थ भारत का संकल्प

प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सकारात्मक भाव से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर तेज गति से बढ़ रहा है।

–मनसुख मांडविया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि 'अच्छा स्वास्थ्य मानव प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। आने वाला भविष्य उन्हीं समाजों का होगा, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन लगाएंगे।' 'पीएम के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार का दृष्टिकोण देश के सबसे असहाय और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को किफायती एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक आयुष्मान भारत कार्यक्रम की घोषणा की। इस कड़ी में आयुष्मान भारत–हेल्थ एंड प्रति वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का एक अनूठा संगम है। देश में लगभग 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इनमें वेलनेस सत्र का आयोजन किया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को 2.38 करोड़ के अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। वे पूरे भारत में 28,351 सूचीबद्ध अस्पतालों में पाँच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 5.3 करोड़ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उन्हें 61,501 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। इससे देश में स्वास्थ्य पर जेब से किए गए खर्च में भारी कमी आई है, जो पहले परिवारों को गरीबी में धकेल दिया करता था। ये आंकड़े दिखाते हैं कि देश यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर तेज गति से बढ़ रहा है।

वर्ष 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति स्पष्ट रूप से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मार्ग निर्धारित करती है। यह नीति स्वास्थ्य पर जेब से किए गए खर्च को कम करके स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर देती है। भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी खर्च को बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में

सुधार के महत्व को समझता है। उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के अनुसार वित्त वर्ष 2013–14 से 2019–20 तक के आंकड़ों पर आधारित सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि और जेब से किए गए खर्च में कमी दिखती है। भारत में सरकारी स्वास्थ्य व्यय में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है जिसमें वित्त वर्ष 2013–14 और 2019–20 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत में 28.6 प्रतिशत से 41.4 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति के संदर्भ में बात की जाए तो इसी अवधि के दौरान सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1,042 रुपये से बढ़कर 2,014 रुपये हो गया। इस व्यय को यदि सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के संदर्भ में व्यक्त किया जाए तो इसी अवधि के दौरान यह 1.15 प्रतिशत से बढ़कर 1.35 प्रतिशत हो गया। कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किए व्यय की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013–14 में 64.2 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 47.1 प्रतिशत हो गई। यह सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किए गए व्यय की वृद्धि से संभव हुआ है। स्वास्थ्य पर जेब से होने वाले खर्च में लगातार गिरावट से यही संकेत मिलता है कि हम देश

'पीएम के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार का दृष्टिकोण देश के सबसे असहाय और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को किफायती एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक आयुष्मान भारत कार्यक्रम की घोषणा की। इस कड़ी में आयुष्मान भारत–हेल्थ एंड प्रति वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का एक अनूठा संगम है। देश में लगभग 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इनमें वेलनेस सत्र का आयोजन किया जाता है।

में एक सुदृढ़ एवं प्रगतिशील स्वास्थ्य प्रणाली को साकार रूप देने के करीब हैं।

सरकारी स्वास्थ्य व्यय में यह वृद्धि लोगों की देखभाल के लिए सार्वजनिक सुविधाओं के बढ़ते उपयोग में भी परिलक्षित होती है। जनजातीय स्वास्थ्य पहल सहित निःशुल्क औषधि सेवा पहल, निःशुल्क निदान पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, उन्नत स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन आवंटन, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं, राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम इत्यादि जैसे विभिन्न अद्वितीय कार्यक्रमों ने समाज द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख प्रासंगिक हो जाता है कि स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही व्यय की दिशा व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर है। वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय का हिस्सा वित्त वर्ष 2013–14 में 51.1 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 55.9 प्रतिशत हो गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में भी जितना अधिक निवेश होगा, उतनी ही उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता कम होगी, जिससे निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा और लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलेंगे। इसके अतिरिक्त भारत में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय वित्त वर्ष 2013–14 में छह प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 9.3 में प्रतिशत हो गया, क्योंकि वेलनेस सेंटर देश में लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में भी जितना अधिक निवेश होगा, उतनी ही उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता कम होगी, जिससे निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा और लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलेंगे। इसके अतिरिक्त भारत में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय वित्त वर्ष 2013–14 में छह प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 9.3 में प्रतिशत हो गया, क्योंकि वेलनेस सेंटर देश में लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। देश की

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का यह विकसित उल्लेख रूप दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि सरकार ने स्वास्थ्य प्रणालियों को अधिक लचीला बनाने के लिए विभिन्न चैनलों के माध्यम से अतिरिक्त धन आवंटित किया है, जिनमें स्वास्थ्य अनुदान आयोग, प्रधानमंत्री–आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य पहल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आदि शामिल हैं। पूरी तरह से लागू हो जाने पर ये सभी पहल एक सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में सामने आएंगी।

इनके साथ केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान, जल जीवन मिशन, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस पहल, फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट इत्यादि का सूत्रपात कर स्वास्थ्य के निकटतम निर्धारकों को प्रमुख महत्व दिया है। वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 के बीच स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजटीय आवंटन में 3,000 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 10,000 करोड़ और पोषण अभियान के लिए 291 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। बीमारी की रोकथाम और समुदाय के सदस्यों के बीच स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण निश्चित रूप से देश को 'सबका साथ, सबका विकास, सबका स्वास्थ्य' की सच्ची भावना में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने में मदद करेगा। •

(लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हैं)

साभार–(दैनिक जागरण 5 अगस्त, 2023)

निवेश और रोजगार का केंद्र बनेगा प्लास्टिक पार्क

—प्रद्युम्न तिवारी

वर्ष 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की बागडोर संभाली, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का संकल्प लिया था। उनकी नेकनीयती, दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प से किए गये कार्यों का सकारात्मक परिणाम भी सामने आया। यूपी में कानून–व्यवस्था बेहतर हुई, तो देश–दुनिया के निवेशकों ने भी यहां का रुख किया। नतीजतन यूपी आज निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। आज यूपी उद्योगों का हब बन रहा है। यहां आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, डेटा सेन्टर आदि तो स्थापित हो ही रहें हैं, अब उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क के परिकल्पना भी साकार होने जा रही है। इस प्लास्टिक पार्क से प्रदेश में जहां अरबों रुपये का निवेश होगा, वहीं हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

यह तो सर्वविदित है कि दुनिया भर में प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स की मांग दिनों–दिन बढ़ रही है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश इसे पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार ने राज्य में प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें एक प्लास्टिक प्रॉसेसिंग पार्क यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र (यीडा) में निर्मित होना है। इसके लिए यीडा के बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब नियोजन विभाग पार्क की रूपरेखा पर काम कर रहा है। वहां से अप्रूवल के बाद प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू होगा और इंडस्ट्रीज को स्थापित करने की कार्यवाही को तेज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार की प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क, लेदर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक पार्क की तर्ज पर ही प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है। प्लास्टिक पार्क में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की प्रॉसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य संबंधित तकनीक वाली यूनिट्स लगाई जाएंगी, जो न सिर्फ उत्तर

प्रदेश, बल्कि देश और दुनिया की प्लास्टिक की जरूरतों को पूरा करेगी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होगा।

जानकारी के अनुसार यीडा में पार्क 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला होगा। इसमें सैकड़ों प्लास्टिक यूनिट्स स्थापित होंगी। यीडा के एक अधिकारी के अनुसार, अखिल भारतीय प्लास्टिक उद्योग संघ ने पहले इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यीडा के सेक्टर 10 में प्लास्टिक प्रॉसेसिंग पार्क विकसित करने के लिए राज्य सरकार सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति दे चुकी है। यीडा के बोर्ड से भी इस प्रस्ताव को पारित करके नियोजन में भेज दिया गया है। नियोजन से इसकी रूपरेखा बनने के बाद इस पर विस्तृत कार्यवाही की योजना पर काम होगा। अधिकारी के अनुसार 20 से अधिक निवेशकों ने यीडा क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले प्लास्टिक प्रॉसेसिंग पार्क में निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। निवेशक यहां चिकित्सा और कृषि उपकरण, पीवीसी पाइप, पैकेजिंग और प्लास्टिक फर्नीचर बनाना चाहते हैं। प्राधिकरण ने इन निवेशकों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी है। जल्द ही, प्लास्टिक उद्योग के कई दिग्गज इस पार्क में अपने संयंत्र स्थापित करेंगे। इससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

यूपी सरकार के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में जब प्लास्टिक उद्योग संघ के दीपक बलानी से बात की, उनका कहना था कि प्लास्टिक पार्क भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल की एक स्कीम का हिस्सा है। इसी के तहत प्रदेश सरकार पार्क के लिए भूमि उपलब्ध करा रही है। इस भूमि पर यूपी सरकार कॉमन फैसिलिटी सेंटर समेत इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी सुविधाएं देगी, जहां प्लास्टिक यूनिट्स की स्थापना होगी। उनके अनुसार, भारत सरकार के डाटा के अनुसार 10 हजार से अधिक प्लास्टिक कंपनियां यूपी में रजिस्टर्ड हैं। भारत में पर कैपिटा प्लास्टिक कंजंप्शन लगभग 15 किलो है, जबकि पूरी दुनिया का पर कैपिटा प्लास्टिक कंजंप्शन लगभग 36 किलो है। इस लिहाज से हम उसके 50 प्रतिशत भी नहीं हैं। भारत एक कंजंप्शन कंट्री है, इस लिहाज से यहां प्लास्टिक ग्रोथ की काफी संभावना है। यूपी भी पॉपुलेटेड स्टेट होने के साथ बड़ा कंजंप्शन स्टेट भी है। अभी यूपी में जितने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, उतने ही बाहर से भी आते हैं। यूपी में प्लास्टिक पार्क बनने से हम न सिर्फ यहां इसकी खपत की मांग पूरी कर पाएंगे, बल्कि आसपास के राज्यों और विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान सभी ने प्लास्टिक का योगदान देखा है। हेल्थकेयर, फार्मा, फूड पैकेजिंग, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट समेत कई प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। एक तरह से प्लास्टिक ने ही लाखों जानें बचाई हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का इस्तेमाल पैकेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग में लगने वाले पाइप्स में भी काफी होता

है। अधिकारियों के अनुसार, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास यीडा क्षेत्र में आने वाले कई समर्पित औद्योगिक पार्कों के साथ, क्षेत्र में उद्योगों की प्रगति में तेजी देखने को मिली थी। राजस्व के मामले में राज्य को लाभ पहुंचाने के अलावा, इस तरह के पार्क हजारों स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। यीडा क्षेत्र में कुल 1,942 निवेशक 17,272.74 करोड़ रुपये की लागत से अपनी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं, जिससे 2,65,718 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) भी इस पार्क में प्लास्टिक पर शोध और प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए 5 एकड़ जमीन पर एक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने को तैयार है। वहीं गोरखपुर में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क में 100 से अधिक प्लास्टिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना है। •

योगी सरकार ने राज्य में प्लास्टिक प्रॉसेसिंग पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें एक प्लास्टिक प्रॉसेसिंग पार्क यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र (यीडा) में निर्मित होना है। इसके लिए यीडा के बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब नियोजन विभाग पार्क की रूपरेखा पर काम कर रहा है। वहां से अप्रूवल के बाद प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू होगा और इंडस्ट्रीज को स्थापित करने की कार्यवाही को तेज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार की प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क, लेदर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक पार्क की तर्ज पर ही प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है।

मो. : 9935097419

गरीबी के मकड़जाल से मुक्त होता प्रदेश

—डॉ. रविशंकर पांडेय

हमारा देश वर्तमान में चीन को पछाड़कर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। वहीं देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहां इसकी जनसंख्या वर्ष 2011 में 19.80 करोड़ थी, वह अब वर्ष 2023 में बढ़कर लगभग 25 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंच गई है। मोटे तौर पर कहें तो देश के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है और देश की कुल जनसंख्या में प्रदेश का हिस्सा 16.50 प्रतिशत के लगभग है। स्वाभाविक है, देश के सर्वाधिक आबादी वाले इस राज्य में गरीबों की आबादी भी अधिक होगी, किन्तु उत्तर प्रदेश में विगत पांच वर्षों के बीते कालखंड में गरीबी में पर्याप्त रूप में कमी आई है।

नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक हालिया रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2015–2016 से 2019–2021 के मध्य देश में बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या आशातीत रूप से कम हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अव्वल है। यह रिपोर्ट वास्तव में प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। इस दौरान पूरे देश में 13.50 करोड़ लोग न केवल बहुआयामी गरीबी के मकड़जाल से मुक्त हुए बल्कि विकास की दौड़ में फिसड्डी व बीमारू कहे जाने वाले राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सबको चौंकाने का काम किया है।

नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक हालिया रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2015–2016 से 2019–2021 के मध्य देश में बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या आशातीत रूप से कम हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अव्वल है। यह रिपोर्ट वास्तव में प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। इस दौरान पूरे देश में 13.50 करोड़ लोग न केवल बहुआयामी गरीबी के मकड़जाल से मुक्त हुए बल्कि विकास की दौड़ में फिसड्डी व बीमारू कहे जाने वाले राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सबको चौंकाने का काम किया है। संख्यात्मक दृष्टिकोण से अकेले उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से इस दौरान ऊपर उठे हैं जो सभी राज्यों की तुलना में

सबसे ज्यादा है। गरीबों की संख्या घटाने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्य रहे हैं। विगत दिनों नीति आयोग ने राज्यों सहित पूरे देश की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार अपने देश में गरीबों की संख्या में एक बड़ी गिरावट सामने आई है। इस रिपोर्ट में गरीबों का प्रतिशत वर्ष 2015–2016 के 24.85 से घटकर 2019–2021 में 14.96ः पर आ गया है। यह रिपोर्ट आने के लगभग एक सप्ताह बाद ही 'यू एनडी पी' की जारी एक अध्ययन आख्या ने भी बताया कि विगत पंद्रह सालों में लगभग 41.5 करोड़ भारतवासियों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में भारत कामयाब रहा है, जो उल्लेखनीय है। ज्ञातव्य है कि भारतीय नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी के सर्वेक्षण में 'यूएनडी पी' के बताए सूचकांकों को ही आधार बनाया है, जिससे दोनों रिपोर्टों में कोई विरोधाभास नहीं है। नीति आयोग ने इनसे अलग दो संकेतकों को और जोड़ कर अपने मानक तैयार किए हैं।

बहुआयामी गरीबी और इसके संकेतक–इधर के वर्षों में अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बहुआयामी गरीबी की एक नई अवधारणा पर लगातार बल दिया जा रहा है। इसलिए बहुआयामी गरीबी के आशय को पहले समझना जरूरी है। विश्व के अधिकांश देश गरीबी को धन की कमी के रूप में परिभाषित करते हैं। किन्तु गरीबी का जीवन जी रहे लोग अपने अनुभवों को कुछ अधिक व्यापक रूप से व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति जो गरीब है वह एक ही समय में कई कठिनाइयों और परेशानियों से गुजरता है तथा उसे इन कठिनाइयों के कारण जीवन में अन्य लोगों के बराबर उन्नति के अवसर नहीं मिलते और इस नुकसान की भरपाई भविष्य में कभी नहीं हो सकती। जरुरत के समय धन की कमी से वह स्वास्थ्य, शिक्षा, समुचित पोषण और जीविका के साधनों से वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि किसी व्यक्ति की गरीबी में कई तरह के आर्थिक और सामाजिक कारक जिम्मेदार होते हैं तथा अलग–अलग व्यक्तियों के लिए इन कारणों का महत्व अलग–अलग होता है। मोटे तौर पर इन कारकों को स्वास्थ्य,

शिक्षा, पोषण और जीवन स्तर के विभिन्न मानकों के रूप में विभक्त किया गया है। इन्हीं कारकों के कारण किसी व्यक्ति के जीवन में जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लगातार कई वर्षों तक बनी रहती है उसी को बहुआयामी गरीबी की संज्ञा दी जा सकती है। उपर्युक्त कारकों के आधार पर बहुआयामी गरीबी को मापने के लिए कुछ संकेतकों का निर्माण किया गया है और इनके महत्व के आधार पर इन्हें अलग–अलग भारांक (weightage) भी प्रदान किया गया है। संक्षेप में इन बहुआयामी गरीबी के संकेतकों, मानदंडों और इनके तय किए गए भारांकों का विवरण निम्न सारणी में दृष्टव्य है –

सारणी–बहुआयामी गरीबी के कारक, संकेतक, उनके मानदंड और भारांक

कारक	संकेतक	निर्धारित मापदंड	भारांक
1. स्वास्थ्य (1/3)	(1) पोषण	– यदि जन्म से 59 माह तक का कोई बच्चा या 15 –49 साल की आयु वर्ग की महिला या 15–54 आयु वर्ग का कोई पुरुष परिवार में कुपोषित हो।	1/6
	(2) मृत्यु दर	– यदि परिवार में सर्वे से पांच वर्ष पूर्व तक कोई बच्चा या किशोर 15 वर्ष की आयु पूरी किएबिना मर गया हो।	1/12
	(3) मातृ स्वास्थ्य	– सर्वे से पांच वर्ष पूर्व तक परिवार में यदि कोई महिला मां बनी हो और कम से कम चार बार कोई स्वास्थ्य कर्मी उसकी देखभाल करने न आया हो।	1/12
2. शिक्षा (1/3)	(1) स्कूल अवधि	– परिवार में 10 साल तक की आयु का कोई सदस्य यदि कम से कम 6 साल की अवधि तक स्कूल न गया हो।	1/6
	(2) स्कूल उपस्थिति	– परिवार में स्कूल जाने लायक कोई बच्चा यदि कक्षा 8 तक नहीं पढ़ सका।	1/6
3.जीवन स्तर (1/3)	(1) ईंधन	– यदि अब भी कोई परिवार परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी या उपले आदि से खाना पकाता है।	1/21
	(2) शौच	– यदि किसी परिवार के पास कोई शौचालय नहीं है।	1/21
	(3) पेयजल	– यदि कोई परिवार तीस मिनट चलकर शुद्ध पेयजल नहीं प्राप्त कर पाता।	1/21
	(4) बिजली	– यदि किसी परिवार के पास घरेलू विद्युत कनेक्शन नहीं है।	1/21
	(5) बैंक खाता	– परिवार के किसी सदस्य का बैंक में कोई खाता न हो।	1/21
	(6) घर	– परिवार के पास मिट्टी व प्राकृतिक सामग्री से बने घर के अलावा कोई अन्य आवास न हो।	1/21
	(7) साधन	– परिवार में टीवी, फ्रिज, फोन, साइकिल, मोटरबाइक, बैलगाड़ी, बुग्गी आदि में से केवल एक साधन उपलब्ध हो।	1/21

गरीबी में कमी– उपर्युक्त कारकों, संकेतकों और निर्धारित मापदंडों के आधार पर नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी और उसकी तीव्रता का सर्वेक्षण कराकर प्रदेशवार व जिलेवार गरीबी का सूचकांक (Index) तैयार कराया था। इस सर्वेक्षण का आधार वर्ष था 2015–2016 माना गया और पांच वर्ष बाद वर्ष 2019–21 के सर्वेक्षण में जो तथ्य सामने आए उससे पता चलता है कि इन पांच वर्षों के मध्य पूरे देश में बहुआयामी गरीबी में लगभग दस प्रतिशत की कमी आई है और 13.50 करोड़ लोग इस गरीबी से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की करें तो अकेले यहां पर 3.43 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं जो सभी राज्यों से अधिक हैं। नीति आयोग की इस

रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि बीते पांच वर्षों में शहरों की तुलना में ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में अधिक तेजी से सुधार हुआ है और पूर्वांचल के जिलों में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी परिलक्षित हुई है। आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और शौचालय आदि की मूलभूत सुविधाओं में उत्साहवर्धक सुधार हुआ है। इस क्षेत्र के महाराजगंज जिले में 29.64%, गोंडा में 29.55%, बलरामपुर में 27.90% और श्रावस्ती में 24.72% लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। प्रदेश का एक और पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड भी है जहां चित्रकूट जिला गरीबी उन्मूलन में सबसे आगे है। यहां प्रश्नगत पांच वर्षों में 21.45% लोग गरीबी से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर डालें तो यहां पर गरीबों की संख्या कुछ धीमी गति से कम हुई है। निःसंदेह यह एक सुचिंतित आर्थिक नीतियों की उपलब्धि कही जाएगी। नीति आयोग ने पांच वर्षों के दौरान बहुआयामी गरीबी से मुक्ति के जो आंकड़े पेश किए हैं उन्हें देखते हुए शेष आबादी को ऊपर उठाने में अब अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में अब शनैः शनैः कई आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 में वित्तीय संस्थानों से फंड आकर्षित करने के लिहाज से 16.20: हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। एक समय में बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला यह राज्य आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन गया है।

ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार– नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में विगत पांच वर्षों में शहरी आबादी की तुलना में ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में अधिक तेजी से सुधार हुआ है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गरीबों की आबादी में 18% की गिरावट आई है वहीं शहरी इलाकों में इसका आंकड़ा महज 6% ही है। इस दौरान पूर्वांचल के जिलों में लोगों का जीवन स्तर तेजी से सुधरा है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी रफ्तार कुछ धीमी है। पश्चिम में रामपुर जिले की आबादी में अन्य जिलों की अपेक्षा गरीबी में कमी आने के साथ वहां के निवासियों में जीवन स्तर को लेकर सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों रामपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और बरेली के लोगों का जीवन स्तर पहले से बेहतर हुआ है। प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले के निवासियों का जीवन स्तर अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे अच्छा है।

जीडीपी में सुधार– एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आमजन की सुखसुविधा में भी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। यह तथ्य जिलों में खेती बाड़ी से लेकर उद्योग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा समेत अठारह मानकों के आधार पर प्रदेश की जीडीपी के आकलन में सामने आया है। इस अध्ययन के आधार पर अब सरकार कम जीडीपी वाले जिलों के समग्र विकास पर और अधिक अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगी। प्रदेश की जीडीपी वृद्धि में जिलों के हिस्सेदारी की बात करें तो स्वाभाविक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले सबसे आगे हैं। उधर पूर्वांचल के जिले मध्य यूपी से किंचित बेहतर स्थिति में हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की स्थिति कमजोर है। यदि आंकड़ों के आधार पर देखें तो प्रदेश की जीडीपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग आधा, 49.26%, पूर्वी प्रदेश का हिस्सा 28.03%, मध्य यूपी का हिस्सा 17.54% और बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा महज 05.17% है। आमजन को उपलब्ध सुख सुविधा के पैमाने पर यदि संपन्नता की बात करें तो गौतमबुद्धनगर जिले में रहने वाले लोग प्रदेश में सबसे ज्यादा संपन्न कहे जा सकते हैं। सुविधाओं के पैमाने पर लखनऊ प्रदेश में दूसरे स्थान पर आता है।

वर्ष 2021 से 2022 के मध्य उत्तर प्रदेश की जीडीपी 1181361 करोड़ रुपए से बढ़कर 1916913.42 करोड़ रुपए

हो गई है। आगरा, प्रयागराज, बुलंदशहर और लखनऊ की जीडीपी में इस दौरान किंचित गिरावट का रुख देखने को मिला है, लेकिन मेरठ जिले ने अपनी जीडीपी में बढ़ोत्तरी दर्ज किया है। जीडीपी की बढ़ोत्तरी और घटोत्तरी से यह पता चलता है कि किस जिले में आर्थिक विकास की संभावनाएं कितनी हैं और कहां कितने निवेश से तय समय में कितना विकास संभव हो सकता है।

किसी जिले की जीडीपी से तात्पर्य है एक साल के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का कुल योग। जिलों में फसल, पशुधन, वनोपज, मत्स्य, खनन, निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति आदि के साथ उपयोगी सेवाओं, कारोबार, वाणिज्य, संपदा, वाहन, यातायात, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रम आदि को निर्धारित मानक के आधार पर जोड़कर जीडीपी का निर्धारण किया जाता है

मांग, व्यय और अर्थव्यवस्था में वृद्धि– एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री योगी जी की कोशिशें अब रंग दिखाने लगी हैं। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ बृद्धि के स्तर और गति कोबनाए रखने में सफल रही है। इसी कारण बहुआयामी गरीबी में सबसे तेज गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के निवासियों की क्रयशक्ति में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। प्रदेश के लोगों की खरीद क्षमता में वृद्धि के साथ हर व्यवसायिक क्षेत्र में मांग बढ़ी है, ऐसी स्थिति में खाने, पीने, संपत्ति खरीद व निर्माण, घूमने फिरने, विद्युत उपभोग और विलासिता पूर्ण जीवनशैली में अब यहां के निवासी खुले हाथों से खर्च करना सीख गए हैं। उपभोग और मांग में वृद्धि के फलस्वरुप वस्तुओं व सेवाओं के क्रय में वसूले जाने वाले अप्रत्यक्ष कर संग्रह में भी प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी है। यही नहीं आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में भी प्रदेश में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और यह देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में अब शनैः शनैः कई आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 में वित्तीय संस्थानों से फंड आकर्षित करने के लिहाज से 16.20% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। एक समय में बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला यह राज्य आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन गया है।

ऊपर दिखाई गई खुशनुमा तस्वीर के साथ उत्तर प्रदेश राज्य की कुछ चुनौतियां भी सामने दिखाई दे रही हैं। बेशक लोकलुभावन नीतियों का लाभ अंततोगत्वा गरीबों व मध्य वर्ग के लोगों को मिल रहा है, मगर इस लाभ की सार्थकता भी लंबे समय तक दिखाई देना चाहिए। आधारभूत संरचनाओं के विस्तार और संकटकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश को अपने खजाने की चिंता लगातार करते रहना चाहिए। प्रदेशवासियों के शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति भी प्रदेश के योजनाकारों को सतत सतर्क दृष्टि रखना पड़ेगा तभी हम गरीबी का समूल नाशकर प्रदेश वासियों के समग्र उज्ज्वल भविष्य की कामना कर सकते हैं। •

मो. : 8004867521

कुशल नेतृत्व से विकास की ऊँचाइयों को छूता प्रदेश

—अंजुम इलाही

देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश, दुनिया में अपनी जनसंख्या के आधार पर छठे नंबर वाला 'देश', भारत की संसद में 80 सांसद भेजने वाला प्रदेश और कुछ समय पहले तक 'प्रश्न प्रदेश' कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसके विकास का श्रेय पिछले लगभग साढ़े छः साल से कार्यरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को जाता है। उसे 2014 से केन्द्र में सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि 2017 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम राजनीतिक कयासों को झुठलाते हुए सत्ता में वापसी की। यह योगी सरकार के कामकाज को जनता से मिलने वाले प्रबल समर्थन का प्रतीक रहा है। योगी सरकार की सबसे कठिन परीक्षा पहले से चली आ रही ज़मीनी स्तर पर नौकरशाही में व्याप्त 'जातिवाद', 'पक्षपात', 'भ्रष्टाचार' तथा 'अकर्मण्यता' का मुकाबला करना रहा है। वह इस परीक्षा में काफी सीमा तक सफल हुई है, पर परीक्षा अभी जारी है। प्रदेश के विकास के लिए बने–बनाये सरकारी ढांचों को तोड़ने तथा उसे तेजी से जन–कल्याण हेतु काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए योगी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इसी दृष्टिकोण से हाल में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षकों के चयन हेतु अलग–अलग व्यवस्थाओं को समाप्त कर 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' बनाने का निर्णय किया गया है। इससे सरकार बड़े पैमाने पर सभी स्तरों पर शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती कर सकेगी। यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार व जातिवाद के आरोप राज्य लोक सेवा आयोग तक पहुंचे थे तथा लगभग सभी विभागों में भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व अनियमितताएं व्याप्त रहती थीं। इसके कारण अनेक मामलों में न्यायालयों के माध्यम से भर्तियां रद्द कर दी जाती थीं तथा भ्रष्ट लोगों को अपनी मेहनत की कमाई के लाखों रुपये देने वाले उम्मीदवारों के परिवार वर्षों तक ठगा महसूस करते थे। योगी सरकार में भर्तियों, परीक्षाओं, नियुक्तियों व स्थानान्तरणों में पूर्णतः पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी नौकरियों में आने की उम्मीद छोड़ चुके सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक गरीब परिवारों की उम्मीदें फिर से जगी हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न परियोजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के भी नये सिरे से अथक प्रयास कर रही है। इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभिन्न विभागों की अनेक परियोजनाओं की स्वयं निगरानी का निर्णय भी किया है और इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक डैशबोर्ड लगाया गया है। इनमें से

अनेक परियोजनायें 'आकांक्षी जिलों' या अनेक मानकों पर पिछड़े जिलों में हैं जिनकी निगरानी प्रतिदिन स्वयं मुख्यमंत्री या उनके संबंधित मंत्री व विभागीय सचिव करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनके मंत्रियों की लगातार सक्रियता, निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप उच्च स्तर पर नौकरशाही अब अधिक प्रेरित अनुभव कर रही है।

इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश आर्थिक रूप से उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अनेक मामलों में देश के सर्वाधिक विकसित प्रदेशों की कतार में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार भारत जो 2014 में दसवें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, पिछले नौ साल में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी ने 'गारंटी' दी है कि राजग के अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का इसमें उल्लेखनीय योगदान है और वह एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इतना ही नहीं, देश में तेजी से बदलती अपनी सकारात्मक पहचान के बीच उत्तर प्रदेश देश के विकसित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े निर्यातक प्रदेशों की कतार में शामिल है तथा उसके निर्यात में बड़ा हिस्सा 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) का है। इससे ज़मीनी स्तर पर कारीगरों, दस्तकारों, किसानों व अन्य हुनरमंद लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश अनेक स्टार्टअप का केन्द्र बनने के साथ रक्षा उत्पादन में 'डिफेंस कॉरीडोर' के माध्यम से भी उल्लेखनीय योगदान कर रहा है।

जिन जिलों में पहले अपराधियों के लिए तमंचे व चाकू बनते थे, वहां आज मिसाइलें व सेना के लिए हथियार बन रहे हैं। प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) की प्रगति में भी उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। इसके चलते जहां प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पड़ता है, वहीं प्रदेश को भारी मात्रा में राजस्व भी प्राप्त होता है। यह तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि प्रदेश आज 'राजस्व सरप्लस' राज्य बन गया है, जबकि पूर्व सरकारों में वह भयंकर घाटे व वित्तीय अनियमितताओं का शिकार था तथा हमेशा 'आर्थिक सहायता' के लिए केन्द्र का मुंह देखा करता था। उत्तर प्रदेश का राज्य जीएसटी संग्रह 65,000 करोड़ रुपये से आगे निकल गया है तथा इसे निकट भविष्य में एक लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तर प्रदेश की प्रगति का सर्वाधिक उल्लेखनीय कारण यहां की 'कानून–व्यवस्था' है, जिसके उदाहरण न

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न परियोजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के भी नये सिरे से अथक प्रयास कर रही है। इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभिन्न विभागों की अनेक परियोजनाओं की स्वयं निगरानी का निर्णय भी किया है और इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक डैशबोर्ड लगाया गया है। इनमें से अनेक परियोजनायें 'आकांक्षी जिलों' या अनेक मानकों पर पिछड़े जिलों में हैं जिनकी निगरानी प्रतिदिन स्वयं मुख्यमंत्री या उनके संबंधित मंत्री व विभागीय सचिव करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनके मंत्रियों की लगातार सक्रियता, निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप उच्च स्तर पर नौकरशाही अब अधिक प्रेरित अनुभव कर रही है।

केवल देश में बल्कि विदेशों में भी दिए जाते हैं। इसके चलते आज प्रदेश में दंगे, रोड होल्डअप, फिरौती, अपहरण, माफियाओं की दबंगई जैसी बातें अतीत बन गई हैं। प्रदेश में कानून–व्यवस्था की बेहतर स्थिति, भूमि व जल संसाधनों के साथ बिजली की पर्याप्त आपूर्ति तथा पारदर्शी व सक्षम प्रशासन के कारण बड़ी संख्या में देशी–विदेशी निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पहले पंजाब को देश में औद्योगीकरण में अग्रणी माना जाता था, पर विगत कुछ साल से वहां राजनीतिक अस्थिरता व प्रतिगामी आर्थिक नीतियों के कारण अनेक उद्योगपति अब उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कुछ महीने पहले पंजाब के साइकिल व मशीनों के हिस्से पुर्ज़े बनाने वाले कई प्रमुख उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रदेश में उद्योग लगाने की इच्छा जताई थी। प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बनाने में यहां कार्यरत वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा शोध संस्थानों की भी प्रमुख भूमिका रही है। आईआईटी व आईआईएम के साथ सीएसआईआर व अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशालाओं ने प्रदेश में इंजीनियरिंग व चिकित्सा क्षेत्र में अत्यन्त कुशल व विशिष्ट श्रमशक्ति तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान किया है। प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करते हुए हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा है जिनमें से अनेक काम करने लगे हैं तथा बाकी का निर्माण तेजी से चल रहा है।

राजधानी लखनऊ के केजीएमयू तथा कई अन्य विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों का विस्तार करने का निर्णय उल्लेखनीय है। डॉ. सोनिया नित्यानंद को केजीएमयू का कुलपति बना कर सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। उल्लेखनीय है कि उनके पिता डॉ. नित्यानंद न केवल सीडीआरआई के निदेशक रहे हैं, बल्कि विज्ञान–प्रसार में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉ. नित्यानंद ने नौजवानों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उम्मीद है कि उनकी योग्य पुत्री के नेतृत्व में केजीएमयू प्रगति की नई ऊंचाइयां छुएगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने एलोपैथी के साथ ही आयुष पद्धतियों को काफी बढ़ावा दिया है। गोरखपुर लंबे समय से प्राकृतिक चिकित्सा, योग व आयुर्वेद का केन्द्र रहा है। अब एम्स के स्तर का एक संस्थान बना कर यहां

देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का इसमें उल्लेखनीय योगदान है और वह एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इतना ही नहीं, देश में तेजी से बदलती अपनी सकारात्मक पहचान के बीच उत्तर प्रदेश देश के विकसित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े निर्यातक प्रदेशों की कतार में शामिल है तथा उसके निर्यात में बड़ा हिस्सा 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) का है। इससे ज़मीनी स्तर पर कारीगरों, दस्तकारों, किसानों व अन्य हुनरमंद लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश अनेक स्टार्टअप का केन्द्र बनने के साथ रक्षा उत्पादन में 'डिफेंस कॉरीडोर' के माध्यम से भी उल्लेखनीय योगदान कर रहा है।

आयुष पद्धतियों को और गति दी जा रही है। प्रदेश में 'वेलनेस सेंटरों', 'जनौषधि केन्द्रों' तथा 'स्वास्थ्य एटीएम' को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की प्रगति में 'पर्यटन' ख़ासकर 'धार्मिक पर्यटन' का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा व योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से काशी का बहुआयामी विकास हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरीडोर की स्थापना के बाद से काशी ने पर्यटकों की संख्या में गोवा को पीछे छोड़ दिया है और यहां गोवा से दस गुना अधिक पर्यटक देश–विदेश से आ रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत विश्व पर्यटन, ख़ासकर विश्व धार्मिक पर्यटन में उल्लेखनीय व अभूतपूर्व स्थान प्राप्त करेगा। दुनिया भर के प्रवासी एक बार अयोध्या आने के इच्छुक हैं। अगले वर्ष जनवरी में रामलला की भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्रदेश के सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में नया चरण शुरू होगा। अयोध्या के साथ ही मथुरा एवं ब्रज क्षेत्र तथा सभी क्षेत्रों के प्रमुख मंदिरों व तीर्थस्थलों का व्यापक सौंदर्यीकरण व विस्तार किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के मोतीमहल हनुमान मंदिर क्षेत्र के विकास की नई योजना ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है। इसके साथ ही राजधानी के हनुमत धाम व थोड़ी दूर स्थिति नैमिषारण्य आज इंटरनेट के माध्यम से युवाओं में भी आकर्षण पैदा कर रहे हैं। इस तथ्य को भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि 'अन्ना पशु' जैसी समस्याओं के बावजूद प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति में अपने भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान गर्व के साथ देश–विदेश में इस धरती का मान बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज 'सबका साथ, सबका विकास' के रास्ते पर तेजी से प्रगति कर रहा है। इससे योगी सरकार को 'सबका विश्वास' मिल रहा है तथा प्रगति के विकास में 'सबका प्रयास' लगातार बढ़ता जा रहा है।

यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभावी नेतृत्व प्रदेश के इस सराहनीय विकास में अतुलनीय भूमिका निभा रहा है और उनके समक्ष प्रदेश और प्रदेश की जनता के कल्याण की भावना सर्वोपरि है। वह स्वयं विभिन्न विकास परियोजनाओं और जनकल्याण कार्यक्रमों के समयबद्ध निर्वहन में विश्वास करते हैं और उसे व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश की इस प्रगति में खेलों को भी पर्याप्त महत्व मिल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक ही कहा है कि 'खेलो इण्डिया' और 'फिट इण्डिया' अभियान के जरिए खेल क्षेत्र में नयी क्रांति आयी है। युवा खिलाड़ियों को नया मंच मिला है। प्रदेश सरकार ने खेलों के विकास के लिए भी तमाम कदम उठाये हैं। इसका नतीजा है कि युवा और महिलाएं खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। •

मो. : 9335922887

चौपालों में होती कुछ काम की बातें और निरन्तर स्मार्ट होते गांव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश गांवों को उत्तर प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने की है और इस निमित्त वे चिंतन—मनन तो कर ही रहे हैं। गांवों की आय बढ़ाने के लिए अनेक शासकीय योजनाएं भी सामने ला रहे हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ विकास योजनाएं लाने और उनके लिए राशि स्वीकृत करा देने भर से विकास नहीं होना है। विकास परियोजनाएं शत—प्रतिशत धरातल पर उतरीं या नहीं, यह पता लगाना भी जरूरी है। यह परस्पर संवाद से ही संभव है। जनप्रतिनिधि, अफसर और लाभार्थी समुदाय जब तक आमने—सामने नहीं होगा तब तक न तो वास्तविकता सामने आएगी और न ही कार्य व्यवहार पारदर्शी हो सकेगा।

—सियाराम पांडेय 'शांत'

गांवों में चौपाल का लगना बहुत सामान्य बात है। वहां सदियों से चौपाल लगती रही हैं। जहां कुछ लोग बैठ गए, वहीं चौपाल। कौड़ा तापते हुए चौपाल लगते देखने का अनुभव तो बेहद रोमांचकारी है। गांव की पुलिया पर बैठे चौपाल लगाने का तो आनंद ही अलहदा है। इसमें काम की बातें तो कम होती थीं। गपशप ज्यादा होती थीं लेकिन इसके बीच भी कुछ काम की बातें हो जाती थी। गांव—ज़वार की बातें हो जाती थीं। किसी की निंदा और किसी की प्रशंसा सुनने का अलग ही रोमांच हुआ करता था। बुजुर्गों की अपनी जमात लगती थी। युवाओं और बच्चों की अपनी जमात यानी चौपाल लगा करती थी महिलाएं भी टोलीबद्ध होकर विचार मंथन किया करती थीं। मतलब अपने दु:ख—सुख साझा किया करती थीं लेकिन इसमें कोई वैचारिक रणनीति नहीं होती थी। यह सहज स्वतःस्फूर्त प्रक्रिया थी। इसमें कोई योजना नहीं थी। यही वजह है कि इस तरह की बैठकें बहुधा विवाद की वजह बन जाती थीं। विकास का लक्ष्य तो सध नहीं पाता था, अभिव्यक्ति की निरंकुशता बवालेजान जरूर हो जाती थी।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौपाल में न केवल नई दिशा और दशा दी बल्कि उसे गांवों के विकास से जोड़ने का काम भी किया है। गांवों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का रात्रि प्रवास होए वे आम ग्रामीण से

संवाद करें और उनकी परेशानियों को नज़दीक से जानें। जो परेशानियां तुरंत हल हो सकती हों, उन्हें समय पर निपटाएं और दुष्कर समस्याओं के समाधान की व्यापक योजना बनाएं। कहना न होगा कि मुख्यमंत्री की यह परिकल्पना अब साकार रूप लेने लगी हैं। गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं विकसित होने लगी हैं और ग्रामीण अपनी प्रतिभाएं क्षमताएं दक्षताएं ईमानदारी, जिम्मेदारी, नैतिकता और बहादुरी की बदौलत शहरों को भी पीछे छोड़ने की दिशा में सोचने लगे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश गांवों को उत्तर प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने की है और इस निमित्त वे चिंतन–मनन तो कर ही रहे हैं। गांवों की आय बढ़ाने के लिए अनेक शासकीय योजनाएं भी सामने ला रहे हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ विकास योजनाएं लाने और उनके लिए राशि स्वीकृत करा देने भर से विकास नहीं होना है। विकास परियोजनाएं शत–प्रतिशत धरातल पर उतरीं या नहीं, यह पता लगाना भी जरूरी है। यह परस्पर संवाद से ही संभव है। जनप्रतिनिधि, अफसर और लाभार्थी समुदाय जब तक आमने–सामने नहीं होगा तब तक न तो वास्तविकता सामने आएगी और न ही कार्य व्यवहार पारदर्शी हो सकेगा।

वैसे भी उत्तर प्रदेश के विकास को गति देनी है तो शहरों की तरह ही गांवों को भी विकसित करना होगा। सदियों से शहर और गांव एक दूसरे के पूरक रहे हैं। गांव शहर की ओर न देखें और शहर गांव की ओर न देखें तो दोनों की ही अर्थव्यवस्था का चरमराना तय है। सच तो यह है कि शहर और गांव एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों को एक दूसरे से ऑक्सीजन मिलती है, संबल मिलता है। अगर योगी सरकार ने हर सप्ताह गांवों में चौपाल लगाने का अभियान शुरू किया है तो उसके मूल में गांवों के सम्यक विकास की भावभूमि ही प्रमुख है।

गांवों के विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग जनवरी 2023 से हर शुक्रवार को ग्राम चौपाल लगा रहा है और उसमें वह ग्रामीणों की समस्याओं का यथासंभव समाधान भी कर रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गांव की चौपाल लगाई जा रही है और संबंधित गांव के लोगों की वास्तविक समस्याओं को जाना–समझा जा रहा है। उन समस्याओं से शासन और प्रशासन भी सीधे तौर पर अवगत हो रहा है।

राजतंत्र में राजा अपनी प्रजा का दुःख दर्द जानने के लिए खुद वेश बदलकर रात में निकलते थे और उन समस्याओं के निदान की कोशिश करते थे। लोकतंत्र में वह परंपरा लगभग विलुप्त–सी हो गई थी। सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों की नज़रों से गांव ओझल होते चले गए। यही वजह थी कि विकास की दौड़ में गांव पिछड़ते गए। शहर व ग्राम के बीच असमानता की खाई बढ़ती गई।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांवों की पीड़ा को समझा और गांव की समस्या का गांव में ही समाधान करने का निर्णय लिया। ग्राम चौपाल इसी की परिणिति है और इसका व्यापक असर दिखाई भी दे रहा है। ग्राम चौपाल की सफलता के लिए न केवल उसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है बल्कि बड़ी तादाद में ग्रामीणों को इस कार्यक्रम का सहभागी बनाने की भी हर संभव कोशिश की जा रही है। ग्राम चौपाल के पांच दिन पूर्व हर ग्राम पंचायत में

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांवों की पीड़ा को समझा और गांव की समस्या का गांव में ही समाधान करने का निर्णय लिया। ग्राम चौपाल इसी की परिणिति है और इसका व्यापक असर दिखाई भी दे रहा है। ग्राम चौपाल की सफलता के लिए न केवल उसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है बल्कि बड़ी तादाद में ग्रामीणों को इस कार्यक्रम का सहभागी बनाने की भी हर संभव कोशिश की जा रही है। ग्राम चौपाल के पांच दिन पूर्व हर ग्राम पंचायत में जनभागीदारी से व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के गांवों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य के विकास इंजन के रूप में गांवों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं, जिसका असर धरातल पर दिखाई दे रहा है। ग्राम चौपाल के जरिये मौजूदा सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पहल कर रही है। जनवरी से हर शुक्रवार को हर विकास खंड की तीन ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है

जनभागीदारी से व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के गांवों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य के विकास इंजन के रूप में गांवों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं, जिसका असर धरातल पर दिखाई दे रहा है। ग्राम चौपाल के ज़रिये मौजूदा सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पहल कर रही है। जनवरी से हर शुक्रवार को हर विकास खंड की तीन ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है और इसकी कमान जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और उपायुक्त संभाल रहे हैं। इसे बड़े पैमाने पर आयोजित करने के लिए सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पूर्व प्रमुखए वर्तमान और पूर्व चौपाल में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया जा रहा है।

ग्राम चौपाल की शुरुआत ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों, मजदूरी भुगतान, महिला सहेलियों, समूह गठन, बीओ, सीएलएफ, बीसी सखी, विद्युत सखी, लखपति महिला सहित किए गए कार्यों के निरीक्षण और उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों की समीक्षा के साथ हो रही है। पंचायतीराज विभाग वित्त आयोग के फंड का उपयोग कर रहा है। हर सरकारी योजना की गांवों तक पहुंच बनाने की कवायद ग्राम चौपाल के दौरान ग्राम पंचायत रोशनी, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, जल निकासी चैनल, सड़क, लिंक रोड, गौ आश्रय, विद्यालय भवन, विद्यालय संचालन, एमडीएमण् सिंचाई व्यवस्था (नहर/नलकूप), संचारी रोग, टीकाकरण, चौपाल में राशन वितरण, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर घर में नल से जलापूर्ति, आंगनबाड़ी व एएनएम केंद्रों का निरीक्षण, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन व छात्रवृत्ति का सत्यापन भी किया जा रहा है।

हर चौपाल की सरकार तैयार डिजिटल डायरी बनवा रही है। इसमें एजेंडा बिंदुओं के साथ कार्यक्रम की तस्वीरें शामिल की जा रही हैं। डायरी को जिला स्तर पर संरक्षित किया जा रहा है ताकि वक्त जरूरत पर उसका उपयोग किया जा सके। ग्रामीणों के साथ आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, कृषि और कृषि संरक्षण, प्राकृतिक और जैविक खेती और हर घर नल जैसी योजनाओं पर गहन चर्चा हो रही है। चौपाल में ग्रामीण विकास विभाग के अलावा पंचायतीराज, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन, समाज कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप अच्छा कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों (संविदा कर्मियों सहित) को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। इसके पीछे सरकार की मंशा अपनी पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए भी प्रेरित करने की है। चौपाल में महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़े विषयों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 19 माह में एक बार राज्य स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री एवं मंत्री की

ओर से ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित की जानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनेक अवसरों पर प्रदेश के गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने पर जोर दे चुके हैं। हर गांव में विश्वकर्मा संकुल के निर्माण की उनकी अपील यह बताने के लिए काफी है कि गांव और किसान के विकास के लिए मौजूदा सरकार कितनी प्रतिबद्ध है।

ज़ाहिर है, सरकार की इस पहल से ग्राम्य अर्थव्यवस्था को जहां आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है, वहीं ग्रामीण श्रमिकों को अपनी मेधा का प्रदर्शन करने और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं भी कमोवेश मिलने लगी है। सरकार की योजना हर जिले में एक जिला–एक उत्पाद मेला और प्रदर्शनियां लगाने की है और इस दिशा में वह पहल कर भी रही है। कहना न होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे प्रगति के पंख भी लग रहे हैं और ग्रामीणों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, गोरखपुर और यूपी के सभी बड़े रेलवे स्टेशन, गांधी आश्रम, पर्यटन विभाग के होटलों और आवास गृह सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ओडीओपी का डिस्प्ले लगाने और वहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को खरीदने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे रखे हैं। सरकार की योजना प्रदेश के हर जिले में एक–एक सप्ताह के लिए ओडीओपी की प्रदर्शनियां और मेले लगाने की है। वह चाहती है कि फ्लिपकार्ट एवं अमेजॉन जैसे ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लूलू ग्रुप के साथ मिलकर ओडीओपी का प्रमोशन किया जाए। इस दिशा में काम चल भी रहा है। सरकार की यह योजना अगर अंजाम तक पहुंची तो इससे न केवल ओडीओपी की सप्लाई चेन और मजबूत होगी बल्कि मांग के अनुरूप प्रोडक्ट की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी के लिए निर्धारित बजट का शत–प्रतिशत उपयोग करने के अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सरकार की योजना अन्य परंपरागत ट्रेड्स को भी चिह्नित करने और अतिशीघ्र उन्हें योजना का हिस्सा बनाने की है। लाभार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने और उन्हें उत्पादों से जुड़े बाजार की जानकारी देने की दिशा में भी सरकार ने कार्य आरंभ कर दिया है। सरकार की सोच है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े लाभार्थियों को जिस दिन टूलकिट बांटे जाएं, उसी दिन उन्हें ऋण भी उपलब्ध करा दिया जाए जिससे उन्हें आगे बढ़ने और अपना लक्ष्य साधने के बीच किसी भी तरह की दुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े। विश्वकर्मा श्रम सम्मान से संबद्ध लाभार्थियों को ऑनलाइन पेमेंट सेवाओं से जोड़ दिया जाए। सरकार की सक्रिय पहल का ही तकाज़ा है, कि उत्तर प्रदेश के सात जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र

(सीएफसी) परिचालन में आ गए हैं। सात सीएफसी के अक्टूबर एवं सात सीएफसी के फरवरी 2024 तक क्रियाशील हो जाने को लेकर सरकार पूरी तरह आश्वस्त है जबकि पाँच अन्य जिलों में सीएफसी की स्थापना के लिए तेज गति से कार्य हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जिलों में अतिशीघ्र सीएफसी विकसित हो जाएँ। कुल मिलाकर सरकार गांवों के चहुंमुखी विकास को लेकर गंभीर है और इस निमित्त चौपालों की जो श्रृंखला उसने शुरू की है, उसके दूरगामी और प्रगतिकामी नतीजों का पूरे प्रदेश को बेसब्री से इंतजार है। •

मो. : 7459998968

श्रीअन्न से समृद्ध होता प्रदेश

–डॉ. शिव राम पाण्डेय

भारत दुनिया में मिलेट्स या श्रीअन्न के उत्पादन और विपणन सरताज है। किसी ज़माने में मिलेट्स की खेती पूरे भारत में होती थी लेकिन हरित क्रांति के बाद धान गेहूँ ने ऐसा पाँव पसारा कि मोटे अनाजों की खेती आदिवासी बहुल राज्यों तक सिमट कर रह गई। देश में मिलेट्स की अधिकतम खेती आजकल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और राजस्थान राज्यों में हो रही है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों में भी मोटे अनाजों की खेती हो रही है मगर प्राथमिकता में नहीं है।

उत्तर प्रदेश की गणना अभी तक मोटे अनाज उत्पादक राज्यों में है किंतु उम्मीद की जा सकती है कि शीघ्र ही इस राज्य की गणना देष के प्रमुख मिलेट्स उत्पादक राज्यों में की जाने लगेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मिलेट्स यानी श्री अन्न का उत्पादन और क्षेत्रफल बढ़ाने, उसके प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक बृहद दीर्घकालिक, सामयिक और व्यवहारिक कार्य योजना बना कर मिलेट्स इयर में उसका अनुपालन शुरू कर दिया है जिसके शुभ संकेत अभी से मिलने लगे हैं। कार्य योजना के मुताबिक हर साल 72,500 किसानों को मिलेट्स की बेहतर खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह चार वर्ष में कुल 2.9 लाख किसान मिलेट्स और प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभान्वित होंगे। सरकार मिलेट्स फसलों की मूल्य संवर्धन एवं प्रचार–प्रसार पर 4 साल में 111.50 करोड़ रुपये का व्यय करेगी।

इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मोटे अनाज यानी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया है। इसी कार्यक्रम के तहत योगी सरकार प्रदेश के किसानों को मोटे अनाज के बीज किसानों को निःशुल्क वितरित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 4 साल में प्रदेश के 2.5 लाख किसानों को मिलेट्स यानि श्री अन्न के बीज निःशुल्क देने

का लक्ष्य तय किया है। श्री अन्ना बीज मिनीकिट वितरण पर सरकार 11.86 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रदेश में श्री अन्न के प्रसंस्करण के लिए इकाइयों की स्थापना पर राज्य सरकार विशेष प्रोत्साहन और ज़ोर दे रही है। श्री अन्न के बीज उत्पादन पर सरकार 7.20 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सरकार की ओर से कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कृषि विभाग ने मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के तहत बनाई गई कार्य योजना के लिए विभिन्न लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने अधिकारियों से कहा है कि पूरी दुनिया भारत की पहल पर, इस साल अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मना रही है और यूपी के तमाम क्षेत्रों में मिलेट्स की खेती के लिए बेहतर हैं, इसलिए मिलेट्स वर्ष को सफल बनाने में यूपी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

श्री अन्न की खपत और विपणन के लिए इसके उत्पादों पर सरकार की विशेष नज़र है। इसी क्रम में काशी के विश्वनाथ धाम में अब श्री अन्न से बने लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया जाएगा इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

इसके अलावा कृषि विभाग सहित अन्य सभी सरकारी आयोजनों में मिलेट्स के व्यंजन परोसने को प्राथमिकता दी जा रही है। सेना समेत तमाम कैन्टीनों में भी मिलेट्स के व्यंजनों का प्रचार और उपलब्धता एवं खपत बढ़ी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मोटे अनाज यानी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया है। इसी कार्यक्रम के तहत योगी सरकार प्रदेश के किसानों को मोटे अनाज के बीज किसानों को निःशुल्क वितरित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 4 साल में प्रदेश के 2.5 लाख किसानों को मिलेट्स यानि श्री अन्न के बीज निःशुल्क देने का लक्ष्य तय किया है। श्री अन्न बीज मिनीकिट वितरण पर सरकार 11.86 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रदेश में श्री अन्न के प्रसंस्करण के लिए इकाइयों की स्थापना पर राज्य सरकार विशेष प्रोत्साहन और जोर दे रही है। श्री अन्न के बीज उत्पादन पर सरकार 7.20 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

यही नहीं कृषि विभाग द्वारा आयोजित मेलों और प्रदर्शनियों एवं किसान गोष्ठियों में किसान और निजी संस्थानों तथा किसान उत्पादक संगठनों द्वारा मिलेट्स के व्यंजनों का स्टाल लगाकर वाहवाही, और अर्थ दोनों अर्जित किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने जनवरी 2023 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम पर 186. 27 करोड़ रुपये खर्च कर मोटे अनाजों की उपज का दायरा एवं उत्पादन बढ़ाने के साथ इनके प्रसंस्करण पर पर्याप्त राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है। योजना के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक संचालन ढांचे की व्यवस्था की गई है। राज्य स्तर स्वीकृति समिति और स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। स्वीकृति समिति का गठन अपर मुख्य सचिव कृषि की अध्यक्षता में गठित की गई है अपर कृषि निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र इसके सदस्य सचिव हैं जबकि

निदेशक कृषि निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विशेष सचिव कृषि, मुख्य महा प्रबंधक नाबार्ड इसके पदेन सदस्य बनाये गये हैं इसी प्रकार राजय स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी के सदस्य सचिव अपर कृषि निदेशक बीज प्रक्षेत्र को बनाया गया है। वित्त नियंत्रक कृषि, मुख्य महाप्रबंधक नावार्ड, संयुक्त निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि विश्वविद्यालयों एवं मिलेट्स अनुसंधान संस्थान और एफ.टी.आर. द्वारा नामित वैज्ञानिक इस कमेटी के सदस्य होंगे।

राज्य सरकार ने प्रदेश में मोटे अनाज या श्री अन्न का रकबा 25 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके विपरीत राज्य में वर्ष 2021–22 तक कुल 10.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रमुख मिलेट्स फसलों खासतौर से ज्वार–बाजरा का उत्पादन होता रहा था। वह भी मुख्य रूप से पशुओं के चारे के लिए, इसमें बाजरा का रकबा 9.05 लाख हेक्टेयर, ज्वार का रकबा 1.71 लाख हेक्टेयर, कोदों का रकबा 0.02 लाख हेक्टेयर एवं सांवाँ का रकबा 0.05 लाख हेक्टेयर ही रहा है। सरकार ने अब नयी कार्ययोजना के तहत 2026–27 तक इनकी बुआई का रकबा बढ़ाकर 25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य तय कर उस पर अमल शुरू कर दिया है। इस वर्ष के खरीफ सीजन में मोटे अनाजों का आच्छादन क्षेत्र 0.77 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा है। राज्य में मिलेट्स के उत्पादन में 15–20 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है। उत्पादन 0.88 मिलियन टन होने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में मोटे अनाज या श्री अन्न का रकबा 25 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके विपरीत राज्य में वर्ष 2021–22 तक कुल 10.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रमुख मिलेट्स फसलों खासतौर से ज्वार–बाजरा का उत्पादन होता रहा था। वह भी मुख्य रूप से पशुओं के चारे के लिए, इसमें बाजरा का रकबा 9.05 लाख हेक्टेयर, ज्वार का रकबा 1.71 लाख हेक्टेयर, कोदों का रकबा 0.02 लाख हेक्टेयर एवं सांवाँ का रकबा 0.05 लाख हेक्टेयर ही रहा है। सरकार ने अब नयी कार्ययोजना के तहत 2026–27 तक इनकी बुआई का रकबा बढ़ाकर 25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य तय कर उस पर अमल शुरू कर दिया है। इस वर्ष के खरीफ सीजन में मोटे अनाजों का आच्छादन क्षेत्र 0.77 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा है। राज्य में मिलेट्स के उत्पादन में 15–20 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है। उत्पादन 0.88 मिलियन टन होने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने अगले 4 वर्षों में मिलेट्स के बीज की 2.5 लाख मिनीकिट किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। इस पर राज्य सरकार 11.86 करोड़ रुपये खर्च करेगी। किस जिले में कितने किसानों को मुफ्त मिनीकिट वितरित की जाएगी, इसका खाका भी कृषि विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है।

इसके अलावा सरकार बीज के उत्पादन पर 7.20 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके लिए अगले 4 साल में कुल 180 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 4 लाख रुपये प्रति संगठन की दर से सीड मनी के रूपमें उपलब्ध कराया जाएगा। इससे भविष्य में मिलेट्स की विभिन्न फसलों के बीज स्थानीय स्तर पर किसानों को उपलब्ध हो सकेंगे।

मिलेट्स का रकबा एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाएगी। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ ही विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम ब्लाक स्तर पर चलाए जाएंगे। कार्य योजना के मुताबिक हर साल 72,500 किसानों को मिलेट्स की बेहतर खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार चार साल में कुल 2.9 लाख किसानों को मिलेट्स और प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण से लाभान्वित किया जाएगा। सरकार मिलेट्स फसलों की मूल्य संवर्धन एवं प्रचार–प्रसार पर 4 साल में 111.50 करोड़ रुपये का व्यय करेगी।

इसके अलावा वर्ष 2023–24 से वर्ष 2026–27 तक मिलेट्स के मूल्य संवर्धन के लिए प्रदेश में प्रति इकाई लगभग

एक करोड़ रुपए की लागत से कुल 55 मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन इकाइयों की स्थापना की जाएगी । इनमें से 25 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों को शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रति इकाई लागत रुपये 95 लाख तय की गई है। 30 पैकिंग इकाइयों की स्थापना एफपीओ एवं उद्यमियों के जरिए की जाएगी जिस पर कुल निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। पैकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए प्रति इकाई 14.25 लाख रुपये लागत निर्धारित की गई है। योजना अवधि में सरकार की ओर से इस मद में लगभग 38 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। मिलेट्स प्रसंस्करण की इकाइयां उन क्षेत्रों में लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर मिलेट्स की खेती बहुलता से होती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य में मिलेट्स की खेती का विवरण इस प्रकार है। •

मो. : 6387257161

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार योजना के तहत होने वाले कार्यों और वर्षवार होने वाले व्यय का विवरण लाख रुपये में-

		जनवरी 2023 तक	वर्ष 2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	योग
1.	मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु बीज मिनी किट वितरण	0.00	165.75	249.10	338.30	433.35	1186.50
2.	उत्पादन में वृद्धि हेतु मिलेट्स का बीज उत्पादन	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00
3.	मिलेट्स की खेती और उत्पाद निर्माण हेतु प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन कार्यक्रम	905.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	882500
4.	मिलेट्स की खेती और उत्पाद निर्माण हेतु प्रचार प्रसार के माध्यम के प्रयोग की वित्तीय उपाशयता	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	232500
5.	मिलेट्स प्रसंस्करण पैकिंग सह विपणन केन्द्र की स्थापना	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	3800.00
6.	मिलेट्स संबंधी अनुसंधान एवं नवाचार हेतु प्रोत्साहन	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	560.00
7.	विपणन हेतु मिलेट्स आउटलेट्स/स्टोर की स्थापना हेतु प्रोत्साहन	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00
8.	परियोजना प्रबंधन इकाई का संचालन	10.00	50.00	50.00	50.00	50.00	210.00
9.	योग	.00	4180.75	4264.10	4353.30	4445.35	18626.50

साकार होते सपनों का शहर : गोरखपुर

—यशोदा श्रीवास्तव

गोरखपुर की सूरत बदल रही है। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण किसी भी छोर से इस शहर में प्रवेश करते ही लग जाता है कि हम सुसभ्य, व्यवस्थित और खूबरसूरत शहर में प्रवेश कर रहे हैं। यह शहर कुछ ही सालों में ऐसा बदला कि पूरी दुनिया में न सही, संपूर्ण भारत में इसकी शिनाख्त चमचमाते शहर का हो गया। विकास के जिस भी पैमाने से मापना चाहें, यह अव्वल साबित होगा। निःसंदेह गोरखपुर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से सुंदरतम शहर की मिसाल बन गया। कहना न होगा कि यह योगी जी के सपनों का गोरखपुर है जो तेजी से बदल रहा है। लोग कहते हैं कि क्यों न गोरखपुर को यूपी के विकास का पैमाना माना जाय!

और जब हम पूर्वांचल के इस शहर के बदलते स्वरूप की बात कर रहे हैं तब यह कैसे न कहें कि इस सबका श्रेय गोरक्षपीठ के युवा महंत और लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम की कुर्सी पर बैठे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ही है। करीब 25 करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम गोरखपुर तक नहीं सीमित रखना चाहते, उनके नेतृत्व में बदलाव की तेज गति पूरे यूपी की है, हम गोरखपुर को यूपी के बदलाव की एक बानगी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब हम गोरखपुर को बदलता हुआ देख रहे हैं तो ज़ाहिर है संपूर्ण यूपी के बदलाव की सुंदरतम तस्वीर की कल्पना हम आसानी से कर पा रहे हैं।

सबसे पहले हम सड़कों की बात कर लें। चाहे नेपाल की ओर से गोरखपुर आना हो, लखनऊ की ओर आना हो बिहार और बनारस की ओर से आना हो, कभी यहां तक पहुंच पाने में लोगों के पसीने छूट जाते थे। सड़कों की ऐसी खस्ता हालत थी कि गोरखपुर जाने के नाम से लोग कांप उठते थे। स्वास्थ्य के मामले में यहां ले देकर एक मेडिकल कॉलेज था जहां इलाज के लिए आना दूर दराज़ के लोगों की मजबूरी थी। दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ तो अपने बीमार परिजनों को लेकर शायद ही यहां तक पहुंच पाते रहे हों। आज गोरखपुर शहर से लेकर गोरखपुर पहुंचने की चारों

दिशाओं के मार्ग ऐसे हैं कि सौ किमी दूरी तक के लोग सवा से डेढ़ घंटे में गोरखपुर पहुंच जा रहे हैं। माना कि फोर लेन सिक्स लेन सड़कों का जाल केंद्र सरकार की योजना से साकार हो रहा है जिसकी परिकल्पना भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की है। लेकिन केंद्रीय योजना के अंतर्गत बन रही ये सड़कें आज गोरखपुर तक पहुंच पाई हैं तो यह योगी जी के बदौलत ही संभव हो पाया वरना इसके पहले केंद्र की तमाम सारी योजनाएं पूर्वांचल के जिलों तक आते–आते हांफने लगती थीं या दम तोड़ देती थीं।

अभी 6–7 साल पहले की ही बात है जब हम गोरखपुर में गोलघर तक पंहुचने में घोर कठिनाइयों से गुजरकर वहां तक पहुंच पाते थे, आज हम कब गोरखपुर में प्रवेश किए और कब अपने गंतव्य तक पहुंच गए, पता ही नहीं चलता। गोरखपुर में गोरक्ष नाथ मंदिर से लेकर गोलघर और देवरिया बाई पास तक सड़कों की सजावट आपको लखनऊ के गोमतीनगर की सुंदर छटा का एहसास कराते हैं। सड़कों की लाइटिंग और हरियाली हर किसी का मन मोह लेती है। इन रास्तों से गुजर रहे लोगों के मुंह से बरबस निकल उठता है 'धन्यवाद योगी जी'!

गोरखपुर की सूरत बदल रही है। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण किसी भी छोर से इस शहर में प्रवेश करते ही लग जाता है कि हम सुसभ्य, व्यवस्थित और खूबसूरत शहर में प्रवेश कर रहे हैं। यह शहर कुछ ही सालों में ऐसा बदला कि पूरी दुनिया में न सही, संपूर्ण भारत में इसकी शिनाख़्त चमचमाते शहर की हो गयी है। विकास के जिस भी पैमाने से मापना चाहें, यह अव्वल साबित होगा। निःसंदेह गोरखपुर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से सुंदरतम शहर की मिसाल बन गया है। कहना न होगा कि यह योगी जी के सपनों का गोरखपुर है जो तेजी से बदल रहा है।

अंग्रेजी काल का बसा इस शहर का बड़ा क्षेत्रफल संकरा और घना है। इसे आधुनिक और नए डिजाइन में परिवर्तित कर पाना संभव नहीं है। शायद इसीलिए योगी जी ने नए गोरखपुर की कल्पना की है। इसके लिए भू क्षेत्र का चयन तेजी से हो रहा है। गोरखपुर के बरगदवा से फर्टिलाइजर होते हुए नवीन बाईपास का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। एक वक्त था जब लोग मऊ में बना ओवर ब्रिज देखकर अचंभित होते थे, योगी जी ने गोरखपुर में ओवर ब्रिज की श्रृंखला तैयार कर दी है। मानीराम रेलवे क्रासिंग के ओवर ब्रिज से गुजरते वक्त किसी विदेशी ओवर ब्रिज का एहसास होता है। महेसरा पुल से बालापार तक का ओवर ब्रिज बस कुछ ही दिनों में बनकर तैयार होने वाला है। गोरखपुर बस्ती मार्ग पर कालेसर पर बना सोनौली और देवरिया बाई पास की डिजाइन सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। जब आप गोरखपुर शहर के भीतर से लखनऊ या देवरिया जा रहे होते हैं तो पैडलेगंज के समीप विशालकाय रामगढ़ ताल जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ था, जहां नगरनिगम का कूड़ा गिरता था, आज उसकी सुंदरता कश्मीर के डलझील से कम नहीं है। पक्षी विहार और नौकायन यहां का ख़ास आकर्षण है।

शिक्षा की बात करें तो गोरक्षपीठ पहले से ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बैनर तले कई एक शिक्षण संस्थाओं का संचालन करता आ रहा है। यहां का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल में उच्च शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। इस विश्वविद्यालय को राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता है जहां से प्रदेश और केंद्र की राजनीति में दखल रखने वाले तमाम राजनेता पैदा हुए हैं। आज यह शहर चार–चार विश्वविद्यालयों के रूप में जाना जाता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल जिसे सदर अस्पताल भी कहते हैं, से बड़ा कोई दूसरा स्वास्थ्य संस्थान नहीं था। यहां नेपाल, बिहार तक के मरीजों का तांता लगा रहता था। चिकित्सीय सेवाएं भी अपूर्ण थीं। गोरक्ष पीठ के महंत जिसे बड़े महाराज के संबोधन से भी जाना जाता है, परम पूज्य अवैद्य नाथ जो खुद भी लंबे समय तक संसद सदस्य रहे हैं, ने सर्वसुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मंदिर परिसर में ही गुरू गोरखनाथ चिकित्सालय की स्थापना की जिसका उद्घाटन उस वक्त उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के बाद यह दूसरा बड़ा अस्पताल था। जहां आज भी मरीजों खास कर गरीबों को निहायत सस्ते में दवा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। यह अस्पताल इस मायने में भी एक नज़ीर है कि यहां सभी वर्ग के लोग आकर पूरे इत्मीनान से इलाज कराते हैं। गोरखपुर के इस अस्पताल की शिनाख्त गोरखपुर और बस्ती मंडल के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बाबा के अस्पताल के रूप में है जहां वे लोग भी इस अस्पताल की दिल से सराहना करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी का ही प्रयास था कि आज यहां एम्स है और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी है। यदि हम मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो कहा जा सकता है कि वह अब यूपी के लगभग हर जिलों में है। यूपी के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते ही योगी जी का जोर कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहा है। कहना न होगा कि योगी के प्रयास का असर गोरखपुर से लेकर यूपी के कोने कोने तक दिखने लगा है। •

मो. : 9918955583

भूजल संरक्षण को बढ़ावा

–डॉ. बलकार सिंह

भूगर्भ जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जन–जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 16 से 22 जुलाई, 2023 के मध्य भूजल सप्ताह के दौरान प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न जन–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका आरम्भ मा. जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा दिनांक 16.07.2023 को भूगर्भ जल विभाग, उ.प्र., स्वप्न फाउन्डेशन (गैर सरकारी संस्था) एवं लखनऊ शहरी क्षेत्र के कुछ स्कूलों के छात्र–छात्राओं/शिक्षकों के सहयोग से 1090 चौराहा, लखनऊ पर मानव श्रृंखला का आयोजन तथा वाटर ऐड फाउन्डेशन (गैर सरकारी संस्था) के सहयोग से जल–मैराथन, नुक्कड़–नाटक आदि कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया। जल–मैराथन लखनऊ शहर से आरम्भ होकर जनपद रायबरेली, फतेहपुर से गुजरते हुए दिनांक 20.07.2023 को जनपद बांदा में समाप्त हुई, जिसमें धावक एवं सायक्लिस्टों द्वारा लगभग 195 कि.मी. की दूरी तय करते हुए भूगर्भ जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश पहुँचाया गया। भूजल सप्ताह के दौरान सम्पूर्ण प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों यथा रैली, नुक्कड़–नाटक, कठपुतली कार्यक्रम, विविध प्रतियोगिताओं, जन–चौपाल, गोष्ठियों आदि के माध्यम से जन–सामान्य तक भूजल संरक्षण का संदेश पहुँचाते हुए इस वर्ष के मुख्य विचार बिन्दु ''यह संकल्प निभाना है, हर एक बूँद बचाना है'' को साकार करने का प्रयास किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 21.07.2023 को लोक भवन सभागार, लखनऊ में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मा. मुख्यमंत्री जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मा. मंत्री जल शक्ति श्री स्वतन्त्र देव सिंह उपस्थित रहे, साथ ही मा. राज्य मंत्री जल शक्ति श्री दिनेश खटिक, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग श्री अनुराग श्रीवास्तव, सचिव नमामि गंगे श्री बलकार सिंह, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग के संग विभिन्न विभागों,

गैर सरकारी संगठनों, जल पुरस्कृत माननीयों तथा प्रगतिशील कृषकों आदि ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं, जिसे प्रकृति ने भरपूर मात्रा में पानी के स्रोत दिये हैं, लेकिन जैसे–जैसे हमारी जरूरत बढ़ी है, इस संसाधन का अनियंत्रित दोहन किया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर में काफी गिरावट आयी है। विगत 20 वर्षों में समस्याग्रस्त विकास खण्डों की संख्या में पाँच गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जल के इस संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और इसी के दृष्टिगत सरकार ने गत वर्षों में वर्षा जल संचयन हेतु तालाबों, चेकडैम, खेत तालाब, मेड़ बन्दी इत्यादि के अनेक कार्य कराएं हैं। साथ ही कृषि दक्ष तकनीकों जैसे कि ड्रिप एवम् स्प्रिन्कलर इरीगेशन को भी अपनाने पर जोर दिया गया। गत वर्षों में सरकार के इन्हीं सतत प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के 36 जनपदों के औसत भूजल स्तर में सुधार हुआ है एवम् 29 विकास खण्ड संकटग्रस्त श्रेणी से बाहर भी आये हैं। ये प्रयास निरन्तर जारी रहेंगे और हम प्रदेश को पानीदार बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। भूजल के विवेकपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण हेतु जन– सहभागिता भी अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए 'भूजल सप्ताह' जैसे आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 'भूजल सप्ताह' जैसे आयोजनों के द्वारा हमको जल–आन्दोलन को जन–आन्दोलन का रूप देना होगा। जल शक्ति मंत्री श्री स्वतन्त्र देव सिंह ने जीवन में भूजल की महत्ता के विषय में बताते हुए कार्यक्रम में उपस्थित समस्त लोगों से अपनी दिनचर्या में पानी का दुरूपयोग रोकने एवं भूजल संचयन का अहवान किया। कार्यक्रम के अन्त में प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव ने सभी माननीयों एवम् आगन्तुकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भूगर्भ जल विभाग को इस सफल आयोजन की बधाई दी।

प्रदेश को पानीदार बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। भूजल के विवेकपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण हेतु जन–सहभागिता भी अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए 'भूजल सप्ताह' जैसे आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 'भूजल सप्ताह' जैसे आयोजनों के द्वारा हमको जल–आन्दोलन को जन–आन्दोलन का रूप देना होगा। जल शक्ति मंत्री श्री स्वतन्त्र देव सिंह ने जीवन में भूजल की महत्ता के विषय में बताते हुए कार्यक्रम में उपस्थित समस्त लोगों से अपनी दिनचर्या में पानी का दुरूपयोग रोकने एवं भूजल संचयन का आहवान किया।

नवीनतम भूजल संसाधनों के आंकलन के अनुसार

प्रदेश के समस्त 75 जनपदो के 826 विकासखण्ड में से 54 विकास खण्ड अतिदोहित श्रेणी में, 46 विकास खण्ड क्रिटिकल श्रेणी में, 169 विकास खण्ड सेमीक्रिटिकल श्रेणी में तथा 557 विकास खण्ड सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं।

वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु भूगर्भ जल विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों को चयनित करते हुए लगभग 2.40 लाख वर्ग मीटर छत के क्षेत्रफल को आच्छादित करते हुए भवनों पर मॉडल स्ट्रक्चर के रूप में रुफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना करायी गयी है। भूजल गुणवत्ता की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन करते हुए भूजल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जा रहा है, वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में घाघरा बेसिन के अन्तर्गत समस्त जनपदों को चयनित करते हुए प्री–मानसून एवं पोस्ट मानसून के नमूनों के अध्ययन के उपरान्त भूजल गुणवत्ता का समग्र आंकलन कराया गया है तथा वर्ष 2023–24 में यमुना बेसिन क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित जनपदों में भूजल नमूनों को एकत्रीकरण करते हुए रासायनिक विश्लेषण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में गिरते हुए भूजल स्तर तथा भूजल गुणवत्ता के समाधान के लिये उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवम् नियोजन) अधिनियम–2019 लागू किया गया है, इसमें सरकारी/अर्द्धसरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालयों एवं निजी क्षेत्रों की संस्थाओं को भी अपने परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रुप से स्थापित करने के प्राविधान किये गये हैं।

नवीनतम भूजल संसाधनों के आंकलन के अनुसार प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के 826 विकासखण्ड में से 54 विकास खण्ड अतिदोहित श्रेणी में, 46 विकास खण्ड क्रिटिकल श्रेणी में, 169 विकास खण्ड सेमीक्रिटिकल श्रेणी में तथा 557 विकास खण्ड सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं।

भूजल स्तर मापन के क्षेत्र में अभिनव प्रयास करते हुए विभागीय पीजोमीटर को डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर से युक्त करने का निर्णय लिया गया है। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत इन पीजोमीटर को उच्चीकृत किया जा रहा है। इन चयनित पीजोमीटर पर डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर स्थापित किए जा रहे हैं। इन डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर से टेलीमेट्री के माध्यम से प्रत्येक 12 घण्टे के अन्तराल पर रियल–टाइम भूजल स्तर प्राप्त किए जा रहे हैं। प्राप्त सटीक भूजल स्तर से भूजल संसाधनों का आंकलन और अधिक प्रामाणिक रुप से किया जा सकेगा।

'अटल भूजल योजना' जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसकी अवधि 2024–25 तक है। परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के महोबा, झाँसी, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर तथा ललितपुर जनपदों के 20 विकास खण्ड तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ जनपद के 06 विकास खण्ड इस प्रकार कुल 26 विकास खण्डों को भूजल प्रबन्धन में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से चयनित किया गया है। इन 26 विकास खण्डों की कुल चयनित 550 ग्राम्य पंचायतों में वाटर सिक्योरिटी प्लान का विकास करते हुए क्षेत्र विशेष की हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न डिमाण्ड साइड इन्टरवेन्शन यथा माइक्रो इरीगेशन पद्यति (ड्रिप एवम् स्प्रिन्कलर प्रणाली द्वारा सिंचाई) सिंचाई हेतु जल का पुनर्प्रयोग, फसल चक्र में परिवर्तन, कम जल खपत वाली फसलों का चयन, कैनाल कमाण्ड एरिया में प्रेशराइज्ड इरीगेशन पद्यति एवम् अन्य जल बचत के उपाय तथा सप्लाई साइड इन्टरवेन्शन यथा चेकडैम परकोलेशन पांण्ड, कन्टूर बडिंग/ट्रेन्चेस, रिचार्ज ट्रेन्च/शाफ्ट/बेल का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। प्रदेश के अवशेष 65 जनपदों में भी अटल भूजल योजना के समान उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना वर्ष 2023–24 से संचालित की गयी है। •

मो. : 8814001155

विकास और पारदर्शिता का अद्भुत योग

मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि उन्होंने धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन से जोड़कर विकास करना शुरू किया है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करके और फैजाबाद का नाम अयोध्या करके वही प्राचीन प्रयागराज और अयोध्या की गरिमा लौटाने में जुटे हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या का जिस तरह से विकास हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि अयोध्या निश्चित रूप से एक दिन विश्व का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल होगा। यहां विश्व के सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री आएगें। काशी विश्वनाथ कॉरीडोर बनने के बाद वहां अब करोड़ों दर्शनार्थी आने लगे हैं। इससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है। प्रयागराज में भी भविष्य में होने वाले महाकुंभ के मद्देनजर योगी सरकार विकास कार्य करा रही हैं। मथुरा–वृंदावन, चित्रकूट और विंध्यांचल धाम का भी तेजी से विकास हो रहा है। इस तरह के विकास से जहां लोगों में सनातन के प्रति श्रद्धा विकसित होगी, वहीं लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे।

–गोलेश स्वामी

योग इंसान के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास और पारदर्शिता का योग चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसका पूरा श्रेय यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। जनता में उनकी छवि एक ईमानदार, मेहनती और दूरदर्शी राजनेता की है। कहने का सार यह है कि योगी जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में वो हर कदम उठा रहे हैं जिससे देश में यूपी नंबर वन की पोजिशन में हो। यही वजह है कि उनकी गिनती देश के नंबर वन मुख्यमंत्री के रूप में होने लगी है। यही नहीं, उनका राष्ट्रीय महत्व भी बढ़ चला है।

पहले की बात करें तो पहले उनकी छवि विशुद्ध धर्म गुरु के रूप में थी यानी लोग उनको गोरक्षनाथ पीठ के महंत और योगी के रूप में जानते और पहचानते थे। बाद में वे गोरखपुर से कई बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और अपने धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों व कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करके लोकप्रिय राजनेता बने। ख़ास बात यह है कि उनकी यह लोकप्रियता गोरखपुर तक ही सीमित न होकर पूरे पूर्वांचल में फैली। उनकी लोकप्रियता का ही परिणाम था कि उन्हें हाईकमान ने देश के सबसे बड़े राज्य की कमान सौंपी। जिस उस समय मुख्यमंत्री ने यूपी की गद्दी संभाली। राज्य की कानून व्यवस्था सहित कई मोर्चों पर उनको जूझना पड़ा। लेकिन उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के चलते गुंडे माफिया या तो जेल में हैं या यूपी छोड़ गए। उनके कार्यकाल में ही कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को पहली बार सजा हुई। दूसरे कुख्यात माफिया अतीक को तो मिट्टी में ही मिला दिया गया। माफिया के अवैध कब्जे वाली जमीनों को खाली कराकर वहां गरीबों के आवास बनाकर दिए गए। यह अपने आप में देश में एक अनूठी मिसाल है जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। सरकारी संपत्तियों की तोड़फोड़ करने वालों से वसूली कराने वाले भी योगी ही हैं। यही वजह रही है कि योगी सरकार के करीब छह साल के कार्यकाल में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था सुधरने और उद्योगपतियों के लिए अनेक

सहूलियतें दिए जाने से देश विदेश के उद्योगपति यूपी में निवेश में रुचि ले रहे हैं। कई लाख के निवेश से युवाओं को रोजगार के मौके भी बढ़ रहे हैं।

सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता कल्याण सिंह सरकार के बाद पहली बार दिखाई दे रही है। युवा इस पारदर्शिता से खुश हैं। बिना किसी सिफारिश और लेनदेन के प्रतिभाशाली युवा नौकरियां पा रहे हैं। यही नहीं नौकरी पाने वालों को मुख्यमंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपते हैं और उन्हें यह नसीहत देना नहीं भूलते कि वे फाइल नहीं लटकाएंगे। जनता से अच्छा व्यवहार करेंगे और ईमानदारी से सेवा करेंगे। राज्य और समाज हित में यह एक अच्छी नसीहत है। विकास की दृष्टि से भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे रिकार्ड समय में बनकर तैयार हुए हैं। इससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास को बढ़ावा मिला है। बीस हजार करोड़ का डिफेंस कोरिडोर के निर्माण से जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं राज्य के अनेक जिलों के विकास का भाग्य खुल जाएगा। दिल्ली से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे भी राज्य के विकास में एक और मील का पत्थर साबित होगा। योगी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में एक परिपक्व राजनेता की छवि विकसित की है। यही वजह है कि जब देश में कहीं चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी की सबसे ज्यादा मांग होती है। यह उनकी देशव्यापी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। इसमें भी कोई शक नहीं कि योगी स्टेट फारवर्ड राजनेता हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। लोगों में उनकी बातों की विश्वसनीयता घर कर गई है, इसलिए यूपी की जनता ने उन्हें सीएम की कुर्सी पर दोबारा भारी बहुमत से आसीन करके इतिहास बनाया। योगी जी भी यूपी की जनता की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं।

मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि उन्होंने धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन से जोड़कर विकास करना शुरू किया है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करके और फैजाबाद का नाम अयोध्या करके वही प्राचीन प्रयागराज और अयोध्या की गरिमा लौटाने में जुटे हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या का जिस तरह से विकास हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि अयोध्या निश्चित रूप से एक दिन विश्व का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल होगा। यहां विश्व का सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री आएगा। काशी विश्वनाथ कारीडोर बनने के बाद वहां अब करोड़ों दर्शनार्थी आने लगे हैं। इससे

वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है। प्रयागराज में भी भविष्य में होने वाले महाकुंभ के मद्देनजर योगी सरकार विकास कार्य करा रही हैं। मथुरा–वृंदावन, चित्रकूट और विंध्यांचल धाम का विकास भी तेजी से विकास हो रहा है। इस तरह के विकास से जहां लोगों में सनातन के प्रति श्रद्धा विकसित होगी, वहीं लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे।

ऐसा नहीं है कि योगी जी केवल विकास, पारदर्शिता और कानून व्यवस्था को ही चाकचौबंद कर रहे हैं बल्कि वे कल्याणकारी फैसले लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने गरीबों के मकान के लिए ग्राम समाज की ज़मीन मुफ्त देने की घोषणा की है। यही नहीं मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीबों के लिए मल्टी स्टोरी पक्के मकान बनाने के लिए अफसरों से कहा है। राज्य के लोगों के कल्याण के लिए योगी जी का दिल कितना बड़ा है यह तो उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही दिखा दिया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी संभालते ही राज्य के करीब 85 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ का कर्ज़ माफ कर दिया था। ऐसा करके जहां उन्होंने किसानों के कल्याण की ओर कदम बढ़ाया, वहीं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को भी प्रदर्शित किया कि वे जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। इसी तरह उन्होंने जंगलों में निवास करने वाले वनटांगिया परिवारों को भी आवास और रोजगार देकर उनके अंधेरे धरों को रोशन किया। आज़ादी के बाद से विकास इन परिवारों से कोसों दूर था। योगी जी की दरियादिली इंसानों तक ही सीमित नहीं रही, वे बेजुबान गोवंश के कल्याण के लिए भी आगे आए। गोवंश के लिए जहां गोशालाएँ स्थापित कराईं और अफसरों को इसके लिए जिम्मेदार बनाया, वहीं गोवंश पालने वालों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की। यही नहीं, उन्होंने अवैध रूप से चल रहे स्लाटर हाउसेस को बंद कराकर एक नई नज़ीर पेश की। सर्वविदित है कि इन अवैध स्लाटर हाउसेस में पूर्व में चोरी छिपे गोवंश की कटान होती थी। लेकिन अब गोवंश की ओर देखने तक की किसी की हिम्मत नहीं है। यह खौफ अवैध कारोबारियों में पैदा करने का श्रेय भी योगी जी को ही जाता है। योगी जी की दूसरी पारी के दो साल बीतने को हैं। वे दिन दूर नहीं जब वाकई योगी जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सफल होंगे। •

मो. : 9415003798

कानून–व्यवस्था बनी नज़ीर

–जितेन्द्र शुक्ला

यह ना तो कोई चमत्कार है और ना ही कोई टोना–टोटका, यह विशुद्ध रुप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छाशक्ति और संकल्प ही है कि दिनों दिन उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। योगी सरकार द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन रही है। अभी हाल ही में 43 साल पहले उप्र के मुरादाबाद में ईद के मौके पर हुई साम्प्रदायिक हिंसा की न्यायिक जांच की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गयी और फिर वह सार्वजनिक हुई। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की साहस इस दौरान आयी–गयी कई सरकारें नहीं दिखा सकीं। लेकिन योगी सरकार ने ना सिर्फ इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया बल्कि यह जताने में भी देर नहीं की कि पूर्व में प्रदेश का शासन किस प्रकार से होता था। वहीं वर्तमान में उत्तर प्रदेश दंगों के दंश से आजाद हुआ है। माफियाओं का दुस्साहस बुल्डोजर तले रौंदा जा रहा है। दिग्गज माफियाओं का हश्र देख अपराध को पेशा बनाने की सोच रखने वाले आज थरथर कांप ही नहीं रहे हैं बल्कि जरायम की दुनिया में जाने से तौबा भी करते देखे जा सकते हैं। योगी सरकार ने ना सिर्फ अपराधियों को पकड़ जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है बल्कि अपराधों की द्रुतगति से विवेचना कर अपराधियों को सज़ा भी दिलायी है। सरकार की इच्छाशक्ति इसी बात से प्रदर्शित होती है कि उसने प्रदेश में बकायदा 'ऑपरेशन कन्विक्शन' चलाया और बीते 40 दिनों में 471 मामलों में अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी। इनमें चार मामले माफिया और उनके करीबियों से संबंधित हैं। वहीं पाक्सो और महिला अपराध के 242 मामले भी शामिल हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध हुई कार्रवाई के पीछे खड़ी जीरो टालरेंस की नीति व मनोबल को साझा कर चुके हैं।

देश के सभी राज्यों में अपराध और अपराधियों का ब्यौरा जुटाने वाली संस्था राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के बीते साढ़े छह साल के आंकड़ों पर यदि गौर किया जाये तो यह स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है कि आज उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है। एक ओर जहां देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज़ हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसे केवल एक। अन्य राज्यों से तुलना की जाए तो झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा के 100, बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77 तथा हरियाणा में 40 घटनाएं दर्ज़ की गईं। इसे योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा

है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीते साढ़े छह वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा पर लगाम लगी है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2007 से 2012 के मध्य 364 दंगे हुए, जिनमें 64 लोगों की जानें गईं। वहीं वर्ष 2012 से 2017 के मध्य लगभग 700 दंगे हुए, जिनमें 117 लोगों की जानें गईं। लूट व चोरी की घटनाओं में लगातार कमी आसानी से देखी जा सकती है। वहीं महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 6.2 प्रतिशत की कमी देखी गई। महिलाओं के विरुद्ध वर्ष 2017 में 59853 तथा वर्ष 2020 में 49385 अपराध दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2021 में इनकी संख्या 56083 रही। महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराधों का क्राइम रेट 50.5 रहा और उत्तर प्रदेश का 16वां स्थान रहा। वर्ष 2020 में कोरोना काल की वजह से अपराधों में कमी आई थी। ऐसे में वर्ष 2019 में दर्ज अपराधों से तुलना में वर्ष 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 6.2 प्रतिशत की कमी देखी गई। बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में वर्ष 2019 में 18943 मुकदमे व वर्ष 2020 में 15271 मामले दर्ज़ हुए थे, जबकि वर्ष 2021 में यह आंकड़ा 16838 पहुंचा। बच्चों के विरुद्ध अपराध का क्राइम रेट 19.7 रहा और यूपी का 28वां स्थान रहा। जबकि महिला अपराध में सबसे अधिक क्राइम रेट हरियाणा का 119.7, तेलंगाना का 112.2 तथा राजस्थान का 105.4 रहा। बच्चों के साथ अपराध में अधिक क्राइम रेट सिक्किम में 72.4, मध्य प्रदेश में 66.7 व हरियाणा में 62.5 रहा।

योगी सरकार ने ना सिर्फ अपराधियों को पकड़ जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है बल्कि अपराधों की द्रुतगति से विवेचना कर अपराधियों को सजा भी दिलायी है। सरकार की इच्छाशक्ति इसी बात से प्रदर्शित होती है कि उसने प्रदेश में बाकायदा 'ऑपरेशन कन्विक्शन' चलाया और बीते 40 दिनों में 471 मामलों में अभियुक्तों को सज़ा सुनायी गयी। इनमें चार मामले माफिया और उनके करीबियों से संबंधित हैं। वहीं पाक्सो और महिला अपराध के 242 मामले भी शामिल हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध हुई कार्रवाई के पीछे खड़ी ज़ीरो टालरेंस की नीति व मनोबल को साझा कर चुके हैं।

जाहिर है सरकार के मुखिया की प्रतिबद्धता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करने में कोई कमी नहीं रखी। योगी सरकार ने भी पुलिस कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए। सवा लाख से अधिक सिपाहियों की भर्ती ने सबसे बड़े पुलिस बल को न सिर्फ और बड़ा किया, बल्कि दशकों बाद सात महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने का रास्ता भी खोला। उप्र विशेष सुरक्षा बल (यूपी एसएसएफ) को आकार दिए जाने के साथ ही पीएसी की ताकत भी बढ़ी है। साल 2017 में भी यूपी पुलिस देश का सबसे बड़ा बल था। तब उसकी संख्या लगभग 1.92 लाख थी। वर्तमान में यूपी पुलिस की संख्या 3.52 लाख है। बीते वर्षों में यूपी पुलिस में दारोगा व सिपाही समेत अन्य पदों पर कुल एक लाख 53 हजार 737 नई भर्तियां हुई हैं। इनमें 22, 184 महिला पुलिसकर्मी भी हैं। नौ हजार पदों के लिए अब तक की सबसे बड़ी दारोगा भर्ती भी हुई। यानि पुलिस विभाग में अराजपत्रित संवर्ग में वर्ष 2017 में 9287, वर्ष 2018 में 37669, वर्ष 2019 में 3457, वर्ष 2020 में 26395, वर्ष 2021 में 5669, वर्ष 2022 में 35604 व वर्ष 2023 में 5126 कर्मियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। बढ़े पुलिस के साथ प्रोन्नति के अवसरों ने पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाया है, जो वास्तव में बदली कानून–व्यवस्था की आधारशिला है।

इतना ही नहीं कानून–व्यवस्था के मोर्चे पर चौबीस घंटे डटे रहने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मी पूरे मनोयोग से अपने ड्यूटी पर मुस्तैद रहें, इसके लिए योगी सरकार ने उनके आराम की भी चिंता की है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हो रही यूपी पुलिस की सेहत पर भी सरकार का फोकस है। लंबी ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मी वापस लौटें तो सुविधाजनक बैरक में आराम कर सकें, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में पुलिस विभाग को 2250 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इनसे पुलिस के आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण होगा। पुलिस विभाग का कुल बजट 37165.99 करोड़ रुपये है। पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की आवासीय सुविधाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालयों व अनावासीय भवनों के निर्माण के

लिए 850 रुपये व शहरों में पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। लखनऊ समेत सात महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, जहां अब तक किराये के भवनों में चल रहे पुलिस कार्यालयों के स्थान पर पुलिस विभाग के अपने भवनों का निर्माण तेजी से कराया जा सकेगा। प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) को भी और मजबूत बनाया जा रहा है। सरकार ने एसडीआरएफ को नये वाहन उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रबंध भी किया है। सरकार ने पुलिस विभाग के आवासीय अनावासीय भवनों के लिए निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिए गए 708.62 करोड़ रुपये के बजट को लगभग चार गुणा बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2021–22 में

की कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि प्रदेश में अपराधों की संख्या में गुणात्मक सुधार आया है। इसी तर्ज पर योगी सरकार साइबर क्राइम को लेकर भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्य कर रही है। प्रदेश में साइबर क्राइम को लेकर जहां भी सूचना मिलती है, वहां पर न सिर्फ केस रजिस्टर किया जाता है बल्कि प्रभावी कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाता है। साइबर क्राइम के प्रति योगी सरकार की सजगता की गवाही आंकड़े दे रहे हैं कि 2022 से मार्च 2023 तक साइबर क्राइम के 13155 केस दर्ज किए गए। इस दौरान 4372 में चार्जशीट दायर हुई है। 4606 में फाइनल रिपोर्ट लगाई जा चुकी है, 45 खारिज हुए, जबकि 7570 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसमें 89 करोड़ 45 लाख 67 हजार 617 रुपए की

2968.74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। वहीं पिछले बजट वर्ष 2022–23 में 2047.26 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। पुलिस आधुनिकीकरण के साथ–साथ सरकार ने पुलिस की आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस वर्ष भी पुलिस भवनों के निर्माण के लिए बड़े बजट की व्यवस्था की है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1582 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस भवनों के 437 कार्य पूर्ण कराये गए हैं। जबकि 250 से अधिक निर्माण कार्य अभी पूरे कराए जाने हैं। वर्तमान बजट में मिली राशि से इन कार्यों को जल्द पूर्ण कराया जा रहा है।

वहीं अब कानून–व्यवस्था के लिए साइबर क्राइम भी बड़ी चुनौती के रुप में उभरा है। लेकिन चूंकि योगी सरकार

रिकवरी भी की गई। ये उदाहरण है कि जहां कहीं भी साइबर क्राइम की सूचना मिलती है उसे रजिस्टर करके कार्रवाई की जा रही है। यानि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से अपराधों में कमी हुई है। जहां अपराध हुए हैं, वहां सख्त से सख्त सजा दी गई है। कुछ मामलों में ऐसी सजा दी गई है जो उदाहरण प्रस्तुत करती है। एनसीआरबी का आंकड़ा हो या लोकल आंकड़ा, अपराधों के प्रति सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है वो प्रशंसनीय है। आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बना है पब्लिक परसेप्शन भी यही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की सरकारों की तुलना में बहुत बेहतर है। •

मो. : 9415158902

महिलाओं का सर्वांगीण विकास

–डॉ. अजय कुमार मिश्रा

उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेने के तुरंत पश्चात् मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कई प्राथमिकताओं पर तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया था। उन्हीं प्राथमिकताओं में से अति महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और उनका विकास करना रहा है। आज से लगभग 75 माह पूर्व महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और अत्याचार की वजह से प्रदेश की नकारात्मक छवि तेजी से देश–विदेश में बन रही थी। मुख्यमंत्री अपने द्वारा किये गए कार्यों और बड़े निर्णयों से न केवल आज महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं बल्कि महिलाओं का विकास भी तेजी से हो रहा है। अब देश–विदेश में महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की छवि भी सकारात्मक स्वरुप ले चुकी है। योगी आदित्यनाथ की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रभाव अब तेजी से चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के 6 वर्षों के कार्यकाल में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ न केवल अपराध में काफी कमी आई है बल्कि महिला अपराध का निस्तारण भी त्वरित गति से हो रहा है। इसकी पुष्टि महिला और बाल सुरक्षा संगठन के 6 जुलाई, 2023 के आंकड़े बयां कर रहे हैं "उत्तर प्रदेश में महिला और अपराध सम्बन्धी मामलों में 97.80 प्रतिशत तक निस्तारित करके देश में दूसरें क्रम पर है।" इसी तरह लंबित इन मामलों के निस्तारण में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इन मामलों में पहले स्थान पर दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव हैं, जिनका अनुपात 98.30 प्रतिशत है। तीसरे स्थान पर पुडुचेरी है, जिसका अनुपात भी 97.50 है। अक्सर बिहार राज्य के साथ उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ेपन की तुलना होती थी वहीं इन मामलों में सबसे खराब प्रदर्शन पड़ोसी राज्य बिहार का रहा है, जिसका अनुपात 18.5 प्रतिशत है और वह उत्तर प्रदेश से काफी पीछे है। उत्तर प्रदेश की इस सफलता के पीछे कठिन श्रम और कई बड़े निर्णय अहम भूमिका अदा कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं के खिलाफ अपराध की मॉनीटरिंग स्वयं नियमित कर रहे हैं।

महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 487 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1016 अभियुक्तों को 10 वर्ष, 10 वर्ष से अधिक कारावास तथा 3076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम कारावास हुआ है। पॉक्सो अधिनियम तथा महिला अपराध के तहत 7,276 अपराधियों को सज़ा दिलाई गयी है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों और लगातार निगरानी रखने की ही देन है की पॉक्सो एवं महिला

सम्बन्धी अपराधों में ई–प्रॉसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के गठन से लेकर अब तक एंटी रोमियो दस्ता द्वारा 88,25,966 लोगों को चेतावनी दी गयी है और 25,127 के विरुद्ध कार्यवाही भी की गयी है। महिलाओं के लिए 6 नए महिला पुलिस थानों को मंजूरी भी मिली है तथा 03 महिला पी.ए.सी. बटालियन (लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं) का गठन भी किया गया है। विमेन पॉवर लाइन 1090 जी.आर.पी.फायर सर्विस और महिला हेल्प लाइन 181 सेवा का एकीकरण कर महिलाओं के लिए विशेष कार्य किया गया है। 1518 थानों में 15,130 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति कर महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। 10,378 महिला बीट भी आवंटित किया गया है। 74 जनपदों में 79 महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्र की स्थापना एवं थाने का दर्ज़ा प्रदान कर महिलाओं के लिए शिकायत करने का सुगम रास्ता सरकार ने प्रदान किया है। इन व्यवस्थाओं से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और प्रदेश की महिलाओं में योगी सरकार के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है।

महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ उनके विकास के लिए भी कार्य लगातार करके उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाकर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अब तक 14.86 लाख पात्रों को लाभान्वित कर चुके हैं। यदि बात निराश्रित महिलाओं के लिए की जाय तो उनके लिए पेंशन योजना में 32.86 लाख पात्रों को लाभ पहुंच रहा है। आत्मनिर्भर बनने के लिए दो लाख से अधिक महिलाएँ पी.एम. स्वनिधि योजना से लाभान्वित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 72.69 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 6,93,663 स्वयं सहायता समूहों, 42,060 ग्राम संगठनों एवं 2,356 संकुल स्तरीय संघों से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से 52,55,129 माताओं को लाभ प्रदान कर उनके जीवन को सरल बनाया गया है। 58,000 बी.सी.सखी पद स्थापित करने की प्रक्रिया गतिमान है। 48,018 बी.सी. सखी का प्रमाणीकरण हो चुका है। 35,183 बी.सी.सखी द्वारा रु 10,371 करोड़ का लेनदेन रु. 27.29 करोड़ अर्जित कर लाभांश लिया है। बी.सी.सखी के माध्यम से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्री–स्कूल किट (खिलौने एवं लर्निंग एड) एवं ई.सी.सी.ई. (एक्टिविटी बुक, पहल, गतिविधि कैलेंडर) सामग्री का वितरण किया गया है। 150 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र निर्मित कर प्रदेश की आबादी के हर तबके तक पहुँच कर सरकार की नीति को घर–घर पहुँचाना है। 199 आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति भी सरकार ने दी है। 189 निकायों में महिलाओं के लिए 1,100 पिंक शौचालय निर्माण कर उनके सम्मान में वृद्धि सरकार द्वारा की गयी है। 181–महिला हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत 5.31 लाख महिलाओं को

योगी आदित्यनाथ की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रभाव अब तेजी से चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के 6 वर्षों के कार्यकाल में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ न केवल अपराध में काफी कमी आई है बल्कि महिला अपराध का निस्तारण भी त्वरित गति से हो रहा है। इसकी पुष्टि महिला और बाल सुरक्षा संगठन के 6 जुलाई, 2023 के आकड़े बयां कर रहे हैं "उत्तर प्रदेश में महिला और अपराध सम्बन्धी मामलों में 97.80 प्रतिशत तक निस्तारित करके देश में दूसरे क्रम पर है।" इसी तरह लंबित इन मामलों के निस्तारण में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इन मामलों में पहले स्थान पर दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव हैं, जिनका अनुपात 98.30 प्रतिशत है। तीसरे स्थान पर पुडुचेरी है, जिसका अनुपात भी 97.50 है। अक्सर बिहार राज्य के साथ उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ेपन की तुलना होती थी वहीं इन मामलों में सबसे खराब प्रदर्शन पड़ोसी राज्य बिहार का रहा है, जिसका अनुपात 18.5 प्रतिशत है और वह उत्तर प्रदेश से काफी पीछे है। उत्तर प्रदेश की इस सफलता के पीछे कठिन श्रम और कई बड़े निर्णय अहम भूमिका अदा कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री लॉ एंड आर्डर और महिलाओं के खिलाफ अपराध की मॉनीटरिंग स्वयं नियमित कर रहे हैं।

सहायता प्रदान की गयी है। रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष योजना में 6,414 महिलाओं–बालिकाओं को क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी है।

इतिहास इस बात का गवाह रहा है की जब भी महिलाओं को अवसर प्रदान किया गया है उन्होंने अपने कार्यों से इतिहास रचा है और बात जब प्रदेश की आधी आबादी की हो तो उनकी सुरक्षा और विकास का मुद्दा अपने आप में स्वर बुलंद करता है। कुशल नेतृत्वकर्ता इस बात को भलीभांति जानता है की ये महज चारदीवारी के अन्दर कैद रहने वाली महिलाएं नहीं है बल्कि आधुनिक दौर की महिलाएँ हैं जिनको मुख्यधारा में जोड़े बिना विकास की परिकल्पना करना कोरी बात होगी और इन बातों का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज़ेहन में अपने कार्यकाल के पहले दिन से है तभी तो आज महिलाओं के सच्चे हितैषी के रूप में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त भी अपनी छाप स्थापित करने में सफल दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं के प्रति उनकी सुरक्षा और सम्मान के साथ–साथ उनके विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश का इतिहास उन्होंने बदल कर लगातार दूसरी बार सत्ता को प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश की कुल वर्तमान अनुमानित आबादी 23.15 करोड़ है जिनमें से महिलाओं की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत है। इन महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने से ही प्रदेश का विकास तेजी से संभव है और इनको मुख्यधारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री अपनी प्रतिबद्धता लगातार दिखा रहे हैं। इनके प्रयासों और कार्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश की महिलाओं के सच्चे हितैषी योगी जी हैं। इतिहास में अब तक हुए सभी मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा इनकी कार्यशैली न केवल प्रभावशाली है बल्कि प्रत्येक महिलाओं तक बिना किसी शर्त पहुँच भी रही है फिर बात प्रदेश के किसी भी क्षेत्र की ही क्यों न हो। विगत 6 वर्षों में जिस तरह महिलाएं सशक्त हुई हैं और उन्हें जीवन परिवर्तन के कई अवसर लगातार योगी आदित्यनाथ प्रदान कर रहे हैं और यही बात उन्हें महिलाओं के सच्चे हितैषी के रूप में एक नई और स्थाई पहचान दिला रही है। •

मो. : 9335226715

सांस्कृतिक पुनरुत्थान से समृद्ध विरासत को संरक्षण

–सुरेन्द्र अग्निहोत्री

प्रदेश में सरकार की पहल से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की गति में तीव्रता निःसंदेह योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता का परिणाम ही है। अमृत काल में उत्तर प्रदेश प्राचीन संस्कृति, उसके दर्शन एवं शिक्षाओं को समाज तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने– संवारने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आचार्य शंकर की शास्त्रार्थ स्थली काशी अपने समय में देश को जोड़ने और एकात्म स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक जीवन की महायात्रा की साक्षी है। काशी (वाराणसी) प्रदेश या देश के ही नहीं बल्कि संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। इसे वरूणा व अस्सी नामक दो नदियों के मध्य स्थित होने के कारण वाराणसी भी कहा जाता है। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। महाभारत तथा रामायण में भी काशी राज्य का उल्लेख है।

महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास नामक राजा ने की थी। यह शैव धर्म का प्रमुख केंद्र तथा हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी के रूप में सदैव प्रतिष्ठित रहा है। जैन धर्म के 6वें और 23वें तीर्थंकर (सुपार्श्वनाथ व पार्श्वनाथ) का जन्म यहीं हुआ था। अतः यह जैनियों का भी तीर्थ है। यहां के प्रमुख दर्शनीय मंदिर व स्थल हैं– विश्वनाथ (अहिल्याबाई होल्कर निर्मित), अन्नपूर्णा, संकटमोचन, दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मंदिर, आदि विश्वेश्वर, साक्षी विनायक और पांचरल आदि। कुंडों तथा वापियों में दुर्गा कुंड, पुष्कर कुंड, पिशाचमोचन, कपिलधारा, लोलार्क, मानसरोवर तथा मंदाकिनी उल्लेखनीय हैं। यहां गंगा पर कुल 88 घाट हैं, जिनमें से अस्सी, तुलसी, हरिश्चंद्र, अहिंल्याबाई, दशाश्वमेध तथा मणिकर्णिका आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। नमो घाट, रविदास घाट, शास्त्री घाट, आदि केशव घाट (निर्माणाधीन) नए घाट निर्मित हुए हैं को वर्तमान सरकार के आने बाद स्वरूप में आए हैं। काशी कॉरिडोर के कारण अतीत की अनुपम थाती के नव निर्माण के साथ एकाकार करके धर्मभक्ति के पथगामी अनुरागियों को एक नई भूमि दी है। लोकव्यापीकरण के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणालियों, परंपराओं और सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के कार्य को अत्यधिक महत्व के कारण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तथा वाराणसी में कई अन्य परियोजनाओं ने शहर की गलियों, घाटों और मंदिर परिसरों को बिलकुल बदल दिया है। विश्व में भारत की पहचान उसकी संस्कृति से रही है। यही संस्कृति भारत की आत्मा है। और यही एकता का मुख्य आधार भी है, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चिति कहा है। वह इस देश की संस्कृति है। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के ध्येय वाक्य के साथ प्रयाग का धार्मिक महत्व त्रिवेणी संगम को विस्तार तथा समानुकूल बनाने के लिए सार्थक प्रयास अपनी अनूठी गाथा

प्रदेश में सरकार की पहल से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की गति में तीव्रता निःसंदेह योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता का परिणाम ही है। अमृत काल में उत्तर प्रदेश प्राचीन संस्कृति, उसके दर्शन एवं शिक्षाओं को समाज तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने– संवारने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आचार्य शंकर की शास्त्रार्थ स्थली काशी अपने समय में देश को जोड़ने और एकात्म स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक जीवन की महायात्रा की साक्षी है। काशी (वाराणसी) प्रदेश या देश के ही नहीं बल्कि संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। इसे वरूणा व अस्सी नामक दो नदियों के मध्य स्थित होने के कारण वाराणसी भी कहा जाता है। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। महाभारत तथा रामायण में भी काशी राज्य का उल्लेख है।

लिख रहे हैं। गौरतलब है कि हर्षवर्धन प्रति पांचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। यहां हर बारहवें वर्ष महाकुंभ व महाकुंभ के 6वें वर्ष अर्ध कुंभ तथा महाकुंभ व कुंभ से इतर वर्षों में माघ मेला लगता है। संगम के किले के अंदर पौराणिक अक्षयवट को सर्वसुलभ कराने का प्रयास सराहनीय है। श्रृंगवेरपुर–नगर से लगभग 48 किमी दूर गंगा के बायें तट पर स्थित है। अपनी बनवास यात्रा के दौरान भगवान राम ने गंगा घाट पर नाविक निषाद की प्रार्थना स्वीकार की थी। रामचीरा घाट, हनुमान मंदिर, श्रृंगी मंदिर आदि यहां के दर्शनीय स्थलों का विकास हुआ है।

2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद सरकार ने अयोध्या पर विशेष ध्यान दिया और यही वजह है कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। 2020 में अयोध्या में ऐतिहासिक दीपावली भी मनाई गई। जिसमें 5,51,000 दीपक जलाए गये। अयोध्या दीपोत्सव लगातार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा में क्रूज सेवा भी शुरू की गई। अयोध्या में भव्य एवं दिव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर है। जल्द ही यह स्वप्न भी साकार होगा। श्रीराम ने जिस संघर्ष और धैर्य के मार्ग को चुना था, उनके भक्तों ने भी मंदिर निर्माण के लिए उसी का अनुसरण किया।

सरयू के तट पर दिव्य दीपावली मनायी जाती है। स्वतंत्रता के समय से ही भारत को अपने सांस्कृतिक मान–बिंदुओं को संवारने का जो काम शुरू कर देना चाहिए था, वह अब हो रहा है। मंदिरों के जीर्णोद्धार हमारे वर्तमान नेतृत्व को न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव है अपितु वह उसके संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध भी है। यह सुखद है कि प्रदेश की योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व की सरकार आनंद के साथ अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में नेपाल के लुंबिनी में तकनीकी रूप से उन्नत

भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी थी, जो बौद्ध विरासत और भारत की सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। प्राचीनकाल से ही भारतवर्ष में तीर्थाटन पर्यटन का अभिन्न अंग रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा, विंध्याचल, चित्रकूट, नैमिषारण्य इत्यादि धार्मिक स्थलों पर लोग तीर्थाटन के लिए निरंतर आते–जाते रहते हैं। चित्रकूट– प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित जिला है। वन जाते समय श्रीरामजी यहीं ठहरे थे। जनश्रुति के अनुसार यहां महर्षि वाल्मीकि भी रह रहे थे।

मंदाकिनी नदी जिसे मयस्विनी भी कहते हैं, चित्रकूट के सुरम्य जंगलों से होकर कहती है। इस नदी के बायें तट पर कामतानाथ से लगभग 2.4 किमी. दूरी पर स्थित सीतापुर में राघवप्रयाग, कैलाश घाट, रामघाट और घृतकल्प घाट आदि) 24 घाट तथा अनेक प्राचीन मंदिर हैं। सीतापुर से लगभग 3.0 किमी. की दूरी पर सती अनुसुइया और महर्षि अत्रि का आश्रम तथा यहां स्थित मन्दराचल पर्वत के अंचल में अनुसुइया अत्रि, दत्तात्रेय और हनुमान जी के मंदिर हैं। सीतापुर से 3.3 किमी पर जानकी कुंड तथा जानकी कुंड से 3.3 किमी. दूरी पर स्फटिक शिला है जहां राम, लक्ष्मण और सीता ने विश्राम किया था। अन्य दर्शनीय स्थलों में हनुमान धारा, भरतकूप व गुप्त गोदावरी मुख्य सीतापुर के पास स्थित कामदगिरि की लोग परिक्रमा करते हैं। राजापुर–गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर चित्रकूट से 38.1 किमी. की दूरी पर स्थित है। यहां तुलसी स्मारक समिति की ओर से एक सुंदर स्मारक का निर्माण हुआ है। चित्रकूट का इतिहास लगभग आठ हजार वर्ष पुराना है। धर्म में आस्था रखने वाले तमाम लोग चित्रकूट की यात्रा करते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में भी कार्य हुआ है। कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बरसाना, गोकुल, नन्दगाँव, वृंदावन, गोवर्धन, अयोध्या, काशी, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विन्ध्याचल, देवीपाटन, तुलसीपुर और राज्य में अन्य अविकसित पर्यटन स्थलों के नवीनीकरण एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

कासगंज जिले में स्थित सोरों क्षेत्र देश के प्रमुख तीर्थों में से एक है। पुराणों के अनुसार विश्व निर्माण की प्रक्रिया इसके निर्माण से प्रारंभ हुई थी। यहां एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें श्री वाराह भगवान की एक विशाल प्रतिमा है।मंदिर के पास ही बाराह घाट है, जिसे हरिवंदी भी कहते हैं। मंदिरों तथा दर्शनीय स्थलों में प्रमुख हैं श्री योगेश्वर श्री सीताराम और श्री बटुकेश्वर नाथ के मंदिर तथा इलाहाबाद जैसा अक्षयवट आदि। पृथ्वी पर गंगा को लाने के लिए राजा भागीरथ ने यहां तपस्या की थी।

गढ़मुक्तेश्वर–मेरठ से 12 किमी. दूर हापुड़ जिले में गंगा के दाहिने तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन कालीन गढ़मुक्तेश्वर शिव का मंदिर तथा सहारनपुर में 11 किमी. की दूरी पर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा शाकुम्भरी देवी का मंदिर लखीमपुर खीरी से लगभग 35 किमी. दूर स्थित गोला–गोकर्णनाथ में एक विशाल झील और उसके निकट भगवान गोकर्णनाथ महादेव के विशाल तथा प्राचीन मंदिर को दिव्यता और भव्यता प्रदान करते हुये उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के पथ को नए आयाम प्रदान किये जा रहे हैं। •

मो. : 9415508695

हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध

–राघवेन्द्र प्रताप सिंह

कहते हैं कि बालक किसी देश का भविष्य होते हैं। बालक विभिन्न चरणों में बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हुए समाज और शासन को बेशकीमती सोच देते हैं। अब योगी सरकार ने बालकों की शिक्षा या यूं कहें कि स्कूली शिक्षा में एक नई क्रांति के लिए कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के एक–एक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार काफी संवेदनशील दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्कूल चलो अभियान व संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया है। इसके तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। सीएम योगी का कहना है कि यूपी को शत प्रतिशत साक्षर प्रदेश बनाने का समय आ गया है और इसके लिए स्कूली शिक्षा में सक्रियता बढ़ाना जरूरी हो गया है। योगी आदित्यनाथ का दृष्टिकोण है कि एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए और कोई भी बच्चा किसी भी संचारी रोग की चपेट में न आए। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की है। बच्चों को स्कूल लाने, उसके अभिभावक को तैयार करने के मिशन को उत्तर प्रदेश में गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को

सीएम योगी का कहना है कि यूपी को शत प्रतिशत साक्षर प्रदेश बनाने का समय आ गया है और इसके लिए स्कूली शिक्षा में सक्रियता बढ़ाना जरूरी हो गया है। योगी आदित्यनाथ का दृष्टिकोण है कि एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए और कोई भी बच्चा किसी भी संचारी रोग की चपेट में न आए। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की है। बच्चों को स्कूल लाने, उसके अभिभावक को तैयार करने के मिशन को उत्तर प्रदेश में गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान कीं।

मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान कीं, साथ ही निपुण असेसमेंट में उत्तीर्ण छात्रों को रिपोर्ट कार्ड भी प्रदान किया। स्कूल रेडीनेस और शिक्षक संदर्शिका का भी विमोचन, मिशन शक्ति के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली जुलाई 2017 में कुकरैल में किया था। यह कार्यक्रम तब से अब तक पूरी तरह सफल रहा है। उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूलों में नामांकन की जो संख्या जुलाई 2017 में एक करोड़ 34 लाख थी, वो आज बढ़कर 1.92 करोड़ पहुंच गई है। पहले ड्रॉप आउट रेट के कारणों को देखें तो योगी सरकार के पहले की सरकारों में विद्यालय के भवन जर्जर थे, फर्श अच्छा नहीं था, विद्यालय भवन के ऊपर बड़े–बड़े पेड़ जमे हुए थे, बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की सुविधा भी ठीक से नहीं थी। आधे से अधिक बालिकाएं नंगे पैर स्कूल आती थीं, बालकों में भी यह संख्या 40 फीसदी के आसपास थी। यूनिफॉर्म अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते थे और जो यूनिफॉर्म मिलते भी थे वो भी सत्र समाप्त होने के बाद। इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

स्कूली शिक्षा से जुड़ी खामियों को दूर करने के लिए समर्पित योगी सरकार :

यूपी के स्कूली शिक्षा में कई कमियां सामने आई हैं। इसको दूर करने के लिए अब योजना तैयार की जा रही है। प्रदेश में कुल करीब 1,14,211 स्कूल हैं। यहां पर पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या करीब 1.20 करोड़ है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षकों के कुल पद 4.17 लाख हैं। करीब 2.74 लाख शिक्षकों की प्रदेश में नियुक्ति हुई है। वहीं, 1.43 लाख खाली पद हैं। ग्रामीण इलाकों में 1.31 लाख शिक्षकों की कमी देखी गई है। शहरी इलाकों में 13 हजार के करीब शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षकों के खाली पद ने सरकार के स्तर पर बड़ी परेशानी खड़ी की है। शिक्षकों के 40 से 45 हजार पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के आने से इसमें भी बदलाव देखने को मिला है।

निपुण और कायाकल्प जैसी स्कीमों से स्कूली शिक्षा में तेजी :

निपुण भारत अभियान के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक जनपद को निपुण घोषित करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में हम क्वालिटी देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में हमने 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और पूर्व छात्रों ने मिलकर एक–एक विद्यालय को गोद लिया है। यह एक अभिनव पहल है। कुल 1.56 लाख विद्यालयों में 1.36 लाख विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प में उत्तर प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ स्मार्ट

क्लास और अन्य सुविधाओं से आच्छादित कर चुकी हैं। शेष 20 हजार विद्यालय बचे हैं जिन्हें इस सत्र में इन कार्यक्रमों से जोड़ने का काम हो रहा है।

इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश में एनसीआरटी का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद अपना रहा है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति के साथ–साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज़ हो रही है।

उत्तर प्रदेश के पास 6 लाख शिक्षक हैं, अगर उन्हें स्कूलों के स्वच्छता कार्यक्रम, संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्कूल चलो अभियान, स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने हेतु जागरूकता को बढ़ाने का जिम्मेदार अंग बना दिया जाय तो बड़े परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

शिक्षकों का काम केवल स्कूल में पाठ्यक्रम पढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अभिभावक के साथ भी संवाद बनाना होगा।

स्कूली शिक्षकों की भूमिका को प्रभावी बनाने हेतु योगी आदित्यनाथ का दृष्टिकोण:

स्कूल चलो अभियान की शुरुआत के साथ ही योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमारा दायित्व बनता है कि हर शिक्षक, हर प्रधानाध्यापक जिस वार्ड या ग्राम पंचायत में स्कूल है वहां के सभी मानिंदों के साथ बैठक करें, उनका सहयोग भी लें, अभिभावकों के साथ बैठक करें। अच्छा होगा कि घर–घर जाकर एक–एक घर की स्क्रीनिंग करें। ग्राम पंचायत की स्टडी करें। किस–किस सामाजिक, आर्थिक स्थिति में निवास करने वाले लोग हैं। उनका एक डाटाबेस तैयार करें। विद्यालय के पास अपनी ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। हो सके तो बेसिक शिक्षा परिषद इसका एक पोर्टल तैयार करे और प्रत्येक विद्यालय से ये डाटाबेस ले। एक शिक्षक के लिए भी यह स्थानीय स्तर पर एक केस स्टडी होगी। इससे आप तय करेंगे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने वंचित हैं। जो स्कूल जाने से वंचित हैं वो किन कारणों से वंचित हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसी समय आधार ऑथेंटिकेशन की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें। सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि एक नोडल अधिकारी तैयार करें जो बीएसए के साथ मिलकर हर विकास खंड और हर ग्राम पंचायत में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डीबीटी के माध्यम से जिन अभिभावकों के खाते में पैसा जाना है उसे सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म, बैग मिल सके। सीएम ने कहा कि हम खेलकूद की प्रतिस्पर्द्धा भी कराते हैं। नवंबर–दिसंबर के दौरान छुट्टियों के आसपास स्कूली स्तर पर इनका आयोजन करें। सरकार ने तय किया है कि हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान होगा। साथ ही ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई है।

सरकारी स्कूलों को मॉर्डन बनाने के लिए यूपी अपना रहा पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना:

योगी सरकार इन दिनों प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है। योगी सरकार अब प्रदेश के स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। यूपी सरकार ने सरकारी स्कूलों को मार्डन बनाने के प्रयास में जुट गई है। इसी के तहत यूपी सरकार ने स्कूलों के लिए पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना अपनाने जा रही है। इस योजना से यूपी के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि पीएम श्री योजना मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में की गईं बजट घोषणाओं में इस योजना के लिए एक हजार करोड़ से अधिक राशि तय की गई है। इस योजना के मानकों के अनुरूप चुनिंदा स्कूलों को पीएम श्री का दर्जा दिया जाएगा और इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

बजट में इस योजना के लिए एक हजार करोड़ से अधिक राशि तय की गई है। घोषणा के अनुसार, केंद्र सरकार की मदद से बेसिक शिक्षा पर 510 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम श्री स्कूल न सिर्फ अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए, बल्कि आसपास के अन्य स्कूलों के लिए भी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से 1753 स्कूलों का डिस्ट्रिक्ट्र और स्टेट लेवल पर वेरिफिकेशन करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। केंद्र सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद इन स्कूलों को पीएम श्री के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने देशभर के 14500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड करने का निर्णय लिया था। पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की थी। पीएम की घोषणा के बाद योगी सरकार ने बजट 2023–24 में इसके लिए राशि का प्रावधान किया है।

योगी सरकार ने दी स्कूली शिक्षा महानिदेशक के पद को मंजूरी :

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल बड़ा फैसला लिया था। यूपी कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा महानिदेशक के पद को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही तय हो गया था कि यूपी सरकार अब स्कूली एजुकेशन को लेकर बड़े स्तर पर कार्रवाई करेगी। योगी सरकार ने बेसिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा विभाग को मिलाकर एक डीजी स्कूली शिक्षा रखने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक व्यवस्था लागू की गई थी। इनके माध्यम से स्कूली शिक्षा के स्तर की जांच की जा रही थी। कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले

महानिदेशक स्कूल शिक्षा को अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रण में करने का निर्णय लिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के तहत आने वाले सभी निदेशालय और कार्यालयों को माध्यमिक शिक्षा से जोड़े जाने से अब कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूलों पर नियंत्रण एक साथ किया जा सकेगा। योगी सरकार की ओर से अब स्कूल शिक्षा महानिदेशक के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। अगले 3 वर्षों में लगभग 4,000 अभ्युदय कम्पोजिट स्कूल विकसित किए जाएंगे, बजट में ₹2000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के इस बार के बजट में योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना इस बात का सूचक है कि सरकार बाल अधिकारों और बाल शिक्षा को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास के जरिए के रूप में देखती है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के प्रत्येक विकास खंड (कुल 880 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय) को विकसित करने पर कुल 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार बच्चों के समावेशी एवं कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। बाल वाटिका, पोषण उद्यान, वाई–फाई और ऑनलाइन सीसीटीवी निगरानी, खेल के मैदान के साथ बहु गतिविधि हॉल और आधुनिक अग्नि सुरक्षा उपकरणों के अलावा ओपन जिम की सुविधा के साथ स्कूली शिक्षा के एक नई क्रांति के लिए योगी सरकार तैयार है। •

मो. : 9415650340

ऐतिहासिक इमारतों व किलों के जीर्णोद्धार से खुले पर्यटन के नये द्वार

—केवलराम

पर्यटन उद्योग संभावनाओं से भरे हुए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इस सेक्टर में रोजगार के असीमित अवसर होने के साथ ही निवेश की अपार संभावनायें भी हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था में पर्यटन सेक्टर का अहम योगदान है। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार पर्यटन सेक्टर को लगातार आगे बढ़ाने पर फोकस कर रही है। उ.प्र. में पर्यटन के नये कान्सेप्ट पर कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में क्रूज संचालन से लेकर सोलर बोट के माध्यम से देशी—विदेशी पर्यटकों को लुभाने पर कार्य किया जा रहा है।

काशी, मथुरा, अयोध्या में पर्यटकों की बड़ी संख्या में आगमन को देखते हुए हाई—वे, एक्सप्रेस—वे, वाटर—वे की कनेक्टिविटी पर विशेष ज़ोर है। इसके अलावा पर्यटन विभाग विभिन्न जनपदों में स्थित पुरानी इमारतों, किलों तथा महलों का कायाकल्प करके देशी—विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की पूरी तैयारी की है। कोरोना की त्रासदी के बाद पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन संभावनाओं का दोहन करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बहुत सी प्राचीन इमारतें तथा किले जीर्ण–शीर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं। इन ऐतिहासिक धरोहरों को संवारने के लिए कार्ययोजना तैयार की गयी है। शीघ्र ही इसको अमली जामा पहनाते हुए इनको सजाया और संवारा जायेगा। इसके लिए नई पर्यटन नीति–2022 में विभिन्न प्राविधान किये गये हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इन किलों को नये लुक देकर पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। जिससे पर्यटकों को राजमहल में ठहरने जैसी अनुभूति हो सके। राज्य सरकार ने इनको पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की रणनीति बनाई है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मौजूद तमाम प्राचीन किले, इमारतें, बढ़ती आबादी, औद्योगीकरण एवं विकास की विभिन्न गतिविधियों एवं अतिक्रमण के कारण जीर्ण–शीर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं। ये सब किले एवं इमारतें हमारी प्राचीन धरोहर हैं और इतिहास के विभिन्न कालखण्ड की स्मृतियाँ समेटे हुए हैं। बहुत से किले स्थापत्य कला के बेहतरीन नमूने हैं। इनको भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करना जरूरी है। पर्यटन विभाग इन किलों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करके पर्यटकों के लिए खोलना चाहता है। इस कदम से जहां एक ओर इन प्राचीन इमारतों का मौलिक सौन्दर्य वापस लौटेगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों को ठहरने पर राजसी ठाटबाट की अनुभूति भी होगी।

पर्यटन विभाग सीईपीटी अहमदाबाद के सहयोग से इन किलों को संरक्षित करने की रणनीति बनाई है। बुन्देलखण्ड के अधिकांश किले दुर्गम एवं बीहड़ स्थलों पर स्थित हैं। यहां तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा। इमारतों के आसपास अवस्थापना सुविधाओं को विकास होने पर पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान की तर्ज़ पर पुरानी इमारतों को नया रूप देने का निर्णय लिया है।

इसके साथ ही इन ऐतिहासिक धरोहरों को हेरीटेज सेक्टर में शामिल करके बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जायेगा। इनकी मार्केटिंग एवं ब्राण्डिंग के साथ ही व्यापक प्रचार–प्रसार करके अधिक से अधिक पर्यटकों को उ.प्र. की ओर आकर्षित किया जायेगा। इससे होटल सेक्टर, टैक्सी, ट्रेवल एजेन्ट तथा टूर आपरेटर को भी रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा, कुशीनगर जैसे स्थल पर्यटकों के लिए पसंदीदा गन्तव्य के रूप में अपना स्थान बनाये हुए हैं। पुराने किले भी पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में उभरेंगे।

राज्य सरकार देश में उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ निवेशकों के साथ खड़ी है। फरवरी में सम्पन्न यूपीजीआईएस–2023 के दौरान देशी–विदेशी निवेशकों ने पर्यटन सेक्टर में निवेश के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किये हैं। उ.प्र. में पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए सभी प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। रेल, रोड, वायु, जल मार्ग तथा हेलीपोर्ट जैसी सुविधायें मौजूद हैं। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल विकसित होने के कारण पर्यटकों के आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाया गया है।

संकल्प, सुशासन एवं सुरक्षा को अपनाकर उ.प्र. लगातार विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में बदलाव महसूस किया जा सकता है और निवेशकों को भरोसा बढ़ा है। जिससे राज्य में 35 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जिन्हें सीधे ही ज़मीन पर उतारा जायेगा। देश की अर्थव्यवस्था में उ.प्र. 08 प्रतिशत योगदान है। राज्य सरकार देश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी बनाने के लिए कटिबद्ध है। भविष्य में पर्यटन सेक्टर का उ.प्र. की अर्थव्यवस्था में अहम् योगदान होगा। •

मो. : 9415080727

स्मार्ट सिटी के तेज प्रयास, नगरवासियों के लिए ख़ास

–अंजु अग्निहोत्री

स्थानीय निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों के मेयर पदों पर जीत हासिल करने के साथ "डबल–इंजन" सरकार में तीसरा पहिया या तीसरा इंजन जुड़ने के साथ योगी मैजिक की सफलता से गौरवान्वित उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग नगरी नागरिकों के लिए ख़ास प्रयास कर रहा है। नई संकल्प शक्ति के साथ विकास पथ पर प्रदेश के विकास की नवीन इबारत लिखने वाले दूर दृष्टा मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की नई पहल और नई परंपराओं का उदय शहरी विकास की आधारशिला के रुप में बुनियादी ढांचा विकसित करने वाला नगर विकास विभाग अहम योगदान की ओर अग्रसर है। अमृत 1.0, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पी.एम. स्वनिधि, सूडा, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि योजनाओं से नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए प्रयास करने का आहवान किया। अन्य प्रदेशों के सफल मॉडल का अध्ययन कर उसे प्रदेश में भी लागू कराने का सुझाव तथा वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि का शत–प्रतिशत सदुपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ करके लक्ष्य समय से पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। निर्माण कार्य पूर्ण होने वाली परियोजनाओं का जल्द से जल्द हैंडओवर करने तथा अमृत 2.0 के अंतर्गत हर जिले के कम से कम एक वार्ड कुल 75 वार्डों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के कार्य में तेजी लायी जाने के निर्देश कारगर हो रहे हैं। नगर निगम अयोध्या के लिए बॉन्ड जारी करने तथा मुम्बई में संचालित डब्बा सिस्टम का अध्ययन कर प्रदेश में एनयूएलएम के माध्यम से लागू कराने से प्रदेश में हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों व अन्य लोगों को शुद्ध एवं पौष्टिक खाना मिल सकेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये अन्य राज्यों में हो रहे अभिनव प्रयोगों का भी अध्ययन कर प्रदेश में लागू कराया जाये, साथ ही स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकतानुसार ट्रेनिंग करायी जायेगी। पी.एम. स्वनिधि के अन्तर्गत इनएक्टिव वेंडर्स एवं शून्य लेन–देन वाले वेंडर्स को प्राथमिकता पर एक्टिव कर बैंक से प्राप्त यू.पी.आई. आई.डी. से भिन्न आई.डी. का प्रयोग करने वाले वेंडर्स की यू.पी.आई.आई.डी. व मोबाइल नं0 को पोर्टल पर अपडेट करने के कदम तकनीकी रूप से लाभ दायक हो रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के शहर अच्छी रैंक प्राप्त करें, इसके लिये विशेष प्रयास जारी रखने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित कर एक–एक शहर को आच्छादित कराया जाने के मुख्यमंत्री जी के सुझावों तथा निरंतर समीक्षा के कारण अमृत 1.0 के अन्तर्गत स्वीकृत 169 पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं में से 155 का कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष 14 का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार सीवरेज की 110 परियोजनाओं के सापेक्ष 82 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 28 का कार्य प्रगति पर है। सेप्टेज मैनेजमेंट की 52 स्वीकृत परियोजनाओं में से 42 का

कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 52 निर्माणाधीन है। इस प्रकार अमृत 1.0 में कुल 331 परियोजनाओं में से 279 का कार्य पूर्ण हो चुका है और 52 निर्माणाधीन हैं। अमृत 1.0 के अन्तर्गत 9,19,142 के लक्ष्य के सापेक्ष 8,83,283 को वाटर सप्लाई कनेक्शन तथा 10,51,180 के सापेक्ष 7,63,082 को सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। अमृत 2.0 के अन्तर्गत स्टेट वाटर एक्शन प्लान (ट्रेंच–1) में 101 तथा स्टेट वाटर एक्शन प्लान (ट्रेंच–2) में 240 वाटर सप्लाई एवं सीवरेज की परियोजनाओं को अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अनुमोदन के उपरान्त ट्रेंच–1 में 90 परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार हो चुकी है और 68 का जी.ओ. भी जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार ट्रेंच–2 में 64 परियोजनाओं डी.पी.आर. तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत बीएलसी (लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण) घटक में 14,17,795 को अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसमें से 11,25,203 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और जियो टैग भी करा दिया गया है, शेष का कार्य प्रगति पर है। पी.एम. स्वनिधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रथम ऋण 9,53,320 लाभार्थियों को, द्वितीय ऋण 2,23,955 को, तृतीय ऋण 6,734 इस प्रकार कुल 11,84,009 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है। अप्रैल, 2023 तक सभी जनपदों में 4,90,240 डिजिटल एक्टिव वेण्डर्स हैं और 63,78,24,790 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। सर्वाधिक वेण्डर्स वाराणसी, फिरोजाबाद, प्रयागराज, झांसी व लखनऊ में सक्रिय हैं। एनयूएलएम के तहत स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2023 तक 9250 व्यक्तिगत ऋण के लक्ष्य के सापेक्ष 11,331 तथा समूह ऋण के लक्ष्य 230 के सापेक्ष 311 ऋण वितरित किये गये। शेल्टर्स फार अर्बन होमलेस (एसयूएच) के अन्तर्गत 154 परियोजनाओं को स्वीकृत प्रदान की गई थी, जिसमें 144 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 142 क्रियाशील है और शेष 10 निर्माणाधीन हैं। एनयूएलएम के तहत गठित महिला समूहों को समृद्ध बनाने के लिये सभी नगर निकायों के अलावा सरकारी कार्यालयों में दीदी रसोई खोली जाएगी। इनका संचालन भी महिला समूह करेंगे और इससे होने वाली आय से समूहों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण–2023 के बारे में बताया गया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के लिये यूएलबीज् का मॉक एसेसमेंट कराया जा रहा है। इस

मॉक एसेसमेंट का उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण–2023 के प्रोटोकॉल के अनुसार कमियों का पता लगाकर यूएलबीज को इस पर काम करने का सुझाव देना है। प्रदेश में 24 अप्रैल 2023 से मॉक असेसमेंट शुरू हो चुका है, जिसमें 18 मंडल पर्यवेक्षकों के साथ प्रत्येक जनपद के लिये एक मूल्यांकनकर्ता को नामित किया गया है। मॉक असेसमेंट के दौरान 85 डेडिकेटेड टीम मेंबर्स (नए ईओ) द्वारा 233 यूएलबीज् का मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैम्पेन, सिटी ब्यूटी कम्पटीशन और आईईसी एक्टिविटीज करायी जा रही हैं। स्टेट स्मार्ट सिटीज् मिशन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अयोध्या में आईटीएमएस का 90 प्रतिशत तथा मल्टी लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। फिरोजाबाद में आईटीएमस का कार्य 94 प्रतिशत, गोरखपुर व मेरठ में आईटीएमएस का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। मथुरा में आईटीएमएस कार्य व शाहजहांपुर में आईटीएमएस व एमएलसीपी का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। प्रत्येक नगर निगम में कम से कम एक जोनल सिटीजन फैसिलिटेशन सेण्टर स्थापित करने की नई पहल की जा रही है, जहां लोगों को हाउस टैक्स, सीवर टैक्स और वाटर टैक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान कराया जायेगा। इसके साथ ही वो टैक्स भी जमा कर सकेंगे। इसके अलावा पेंशन, बर्थ, व डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी आवेदन कर सकेंगे। प्रत्येक स्मार्ट सिटीज् के पार्क में सूर्य नमस्कार स्टैच्यू स्थापित किये जायेंगे। 8 शहरों–मेरठ, मथुरा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, गोरखपुर, सहारनपुर बे बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से 10 कम्पोजिट विद्यालय बनाये जायेंगे। प्रत्येक नगर निगम में हेल्थ एटीएम की स्थापना की जायेगी और अयोध्या व मथुरा में हेरिटेज स्मार्ट रोड स्थापित करने पहल की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में पहली बार बीजेपी एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इन 17 नगर निगमों में से 3 नये गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा–वृंदावन और शाहजहांपुर हैं। शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम के चुनाव हुए हैं। इन सभी 17 नगर निगमों में पांच लाख से लेकर 50 लाख की आबादी निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के विजन को डबल इंजन सरकार ने आगे बढ़ाया है, आज का ये जनादेश आप सबके सामने है। एवं डबल इंजन सरकार की जनपक्षीय, विकासपरक एवं सर्वसमावेशी नीतियों के प्रति प्रचंड जन विश्वास को प्रदर्शित करती है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर यूपी बीजेपी के सभी समर्पित व कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं सुशासन प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई। यह विराट विजय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन एवं डबल इंजन सरकार की जनपक्षीय, विकासपरक एवं सर्व समावेशी नीतियों के प्रति प्रचंड जन–विश्वास को प्रदर्शित करती है। राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए सभी प्रदेश वासियों का हृदयतल से अभिनंदन। भव्य उत्तर प्रदेश की संकल्पना के भरोसे को जन के स्वीकारता से सशक्त, समृद्ध उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम गर्व की भावना पैदा कर रहे हैं। •

मो. : 8787093085

ट्रांसफॉर्म हो रहा है उत्तर प्रदेश

–डॉ. ए.के. मिश्रा

यह सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान करते हुए, तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है अब इस बात को अत्यधिक विश्वसनीयता के साथ सभी को स्वीकार भी करने के पीछे मजबूत कारण 'विश्वबैंक' है। विश्वबैंक के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बीते छह साल में सब कुछ बदल गया है। अवस्थापना विकास, औद्योगिकरण, कूड़ा निस्तारण, गरीबी उन्मूलन, नियोजित शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण आदि सेक्टर में की गई कोशिशों ने उत्तर प्रदेश को नया कलेवर दिया है।" अब उत्तर प्रदेश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान होना भी शुरू हो गया है। सीएम योगी के लिए प्रदेश का विकास करना एक बड़ी चुनौती भी रहा है क्योंकि देश की 16 प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है और विभिन्न समस्याओं से प्रदेश घिरा हुआ था। आज योगी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार के रूप में देखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश जिस तरह सेक्टरवार जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार कर कार्य कर रहा है, वह देश के सबसे बड़े प्रदेश में व्यापक बदलाव लाने वाला है। विश्वबैंक द्वारा दिये गये इस बयान के पीछे क्या कारण है इसे भी जानना जरुरी है।

किसी भी उपलब्धि के पीछे कठिन श्रम और बनाये गए नियमों को अंतिम छोर तक समान रूप में लागू करना भी एक बड़ी चुनौती है ऐसे में बात जब उत्तर प्रदेश की हो तो स्वयं में चुनौती बृहद हो जाती है विश्वबैंक द्वारा दिए गए बयान के पीछे सरकार की एक दो नहीं बल्कि कई उपलब्धियां रही हैं जिसमें वह भारत में प्रथम राज्य रहा है जैसे–प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) में 52.20 लाख आवास

स्वीकृत/निर्माण में। उज्ज्वला योजना में 1.75 करोड़ पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में। स्वच्छ भारत मिशन में 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण करने में। सौभाग्य योजना में 1.58 करोड़ निःशुल्क विधुत कनेक्शन देने में। रु. 2 लाख 2 हजार करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान करने में। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 8. 56 करोड़ खाते खोलने में। मनरेगा के क्रियान्वयन में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10,33,132 स्ट्रीट वेंडर्स को रु. 1190 करोड़ का ऋण देने में। गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आलू, हरी मटर, आम, दुग्ध और तिलहन उत्पादन में। डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने में। 131 करोड़ पौधरोपण करने में। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की 96 लाख से अधिक इकाई की स्थापना करने में। रोजगार एवं सरकारी नौकरी देने में।

सीएम योगी के लिए प्रदेश का विकास करना एक बड़ी चुनौती भी रहा है क्योंकि देश की 16 प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है और विभिन्न समस्याओं से प्रदेश घिरा हुआ था। आज योगी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार के रूप में देखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश जिस तरह सेक्टरवार जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार कर कार्य कर रहा है, वह देश के सबसे बड़े प्रदेश में व्यापक बदलाव लाने वाला है। विश्वबैंक द्वारा दिये गये इस बयान के पीछे क्या कारण है इसे भी जानना जरुरी है।

सेनीटाइजर एवं मास्क उत्पादन में। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में (59.1 प्रतिशत की दर)। सभी थानों में महिला हेल्पडेस्क की स्थापना करने में। सर्वाधिक कोरोना जाँच और टीकाकरण में। 65 संचालित और 22 निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के साथ देश में सर्वाधिक मेडिकल कालेज में। अटल पेंशन योजना के तहत 75 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित करने में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 1.46 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने में। ई–टेंडरिंग प्रणाली की परफोर्मेस में। जेम पोर्टल में खरीदारी करने में। ई–संजीवनी पोर्टल में मरीजों के इलाज में। गोपालन एवं संरक्षण में। यह उपलब्धि इस लिए भी सराहनीय है क्योंकि 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम आने की होड़ गहराई से विद्यमान है। ऐसे में इस उपलब्धि का सीधा श्रेय योगी जी को जाता है जिनके नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश के लिए संभव हो पाया है।

देश में प्रथम होने के कई अन्य उपलब्धियों के साथ–साथ राज्य को कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं जैसे– गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में प्रदेश की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी को वर्ष 2021, 2022 में प्रथम एवं वर्ष 2023 में द्वितीय पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित। वन स्टॉप सेंटर, लखनऊ को नारी शक्ति पुरस्कार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट।

विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा योगीराज की प्रशंसा करने के पीछे एक या दो नहीं बल्कि अनेक ऐसे कारण हैं जो उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम बना रहे है। सरकार द्वारा लिए जा रहे प्रत्येक निर्णयों का केंद्र बिंदु आम आदमी है यह प्रदेश की जनता की समझ में भी आ गया है। हर परिस्थिति में योगीराज में सुरक्षा, सम्मान, रोज़गार, आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी और नवाचार से भी आम जनता को जोड़ा जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, यातायात, सड़कों का निर्माण, आम जनता की ज़मीनी आवश्यकताओं की जानकारी, आधारभूत संरचना, रोज़गार, उद्यमिता को बढ़ावा, आम जनता से जुड़े रहने की विद्या जिस तरह योगी आदित्यनाथ समझते हैं और उस पर तेजी से कार्य करते हैं वह अभूतपूर्व है।

एसोचेम द्वारा उत्तर प्रदेश को "बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट" की गोल्डमेडल ट्रॉफी। दिव्यांगजन के हितार्थकार्य हेतु लखनऊ को सर्वश्रेष्ठ जनपद का पुरस्कार। सहकारिता विभाग को स्काच आर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड। ग्राम्य विकास विभाग को कन्वर्जन में प्रथम पुरस्कार। यूपी 102 परियोजना–पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली के लिए विशेष जूरी पुरस्कार। नदियों के पुनरुद्धार हेतु जल संचयन में कई जनपदों को प्रथम/द्वितीय पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रदेश में हो रहे बदलाव के जीवंत साक्षी हैं। इनके अतिरिक्त अन्य बातों की चर्चा करें तो यह दिखाई देता है की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सफलता का इतिहास प्रतिदिन लिखा जा रहा है जैसे–नीति आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार विगत 06 वर्षों में उत्तर प्रदेश साढ़े पांच करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफल रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केन्द्र, प्रदेश इस दिशा में कार्य करते हुए अपनी विरासत और प्राचीन नगरों को भी सहेज रहा। उत्तर प्रदेश ने

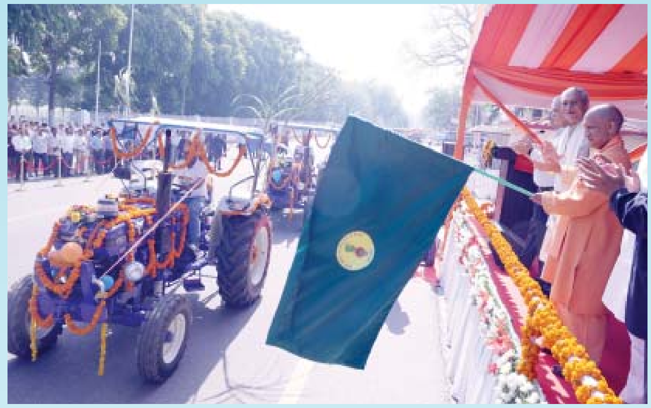

अपनी अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर बनाने का न केवल निर्णय लिया है बल्कि उस पर तेज़ी से कार्य भी हो रहा है। प्रदेश सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ही नहीं, बल्कि ईज ऑफ लिविंग में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा योगीराज की प्रशंसा करने के पीछे एक या दो नहीं बल्कि अनेक ऐसे कारण हैं जो उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम बना रहे हैं। सरकार द्वारा लिए जा रहे प्रत्येक निर्णयों का केंद्र बिंदु आम आदमी है यह प्रदेश की जनता की समझ में भी आ गया है। हर परिस्थिति में योगीराज में सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी और नवाचार से भी आम जनता को जोड़ा जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, यातायात, सड़कों का निर्माण, आम जनता की ज़मीनी आवश्यकताओं की जानकारी, आधारभूत संरचना, रोजगार, उद्यमिता को बढ़ावा, आम जनता से जुड़े रहने की विद्या जिस तरह योगी आदित्यनाथ समझते है और उस पर तेजी से कार्य करते हैं इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि बड़े और दूरगामी परिणाम हेतु कार्य इन्हीं के नेतृत्व में तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा विगत 06 वर्षों में प्रदेश के समग्र विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री जी की सराहना करना यह स्थापित करता है कि प्रदेश में विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पूर्ति के साथ हो रहा है। देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है और रामराज्य को सार्थक करते हुये सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव लोगों तक पहुंचा भी रहा है। विश्व बैंक द्वारा योगीराज की प्रशंसा करना प्रदेश के करोड़ों लोगों में विश्वास की नींव को और मजबूत करना है उनके द्वारा इतिहास बदल कर लगातार दूसरी बार चुनी गयी सरकार और नेतृत्वकर्ता योगी आदित्यनाथ जी सही मायने में लोगों के न केवल सच्चे हितैषी हैं बल्कि करोड़ों लोगों को अपेक्षित विकास बड़े आधुनिक बदलाव के साथ घर–घर पहुँचाने में सक्षम भी हैं। •

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सफलता का इतिहास प्रतिदिन लिखा जा रहा है जैसे–नीति आयोग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विगत 06 वर्षों में उत्तर प्रदेश साढ़े पांच करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफल रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केन्द्र, प्रदेश इस दिशा में कार्य करते हुए अपनी विरासत और प्राचीन नगरों को भी सहेज रहा। उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर बनाने का न केवल निर्णय लिया है बल्कि उस पर तेजी से कार्य भी हो रहा है। प्रदेश सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ही नहीं, बल्कि ईज ऑफ लिविंग में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

मो. : 9335226715

न्यायिक सुधार की अहम कड़ी ग्राम न्यायालय

—एस.आर. पांडेय

शहर और गांव दोनों ही उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की चिंता के केंद्र में हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा पर काम कर रही योगी सरकार शहर और गांव में सरल, सहज न्याय की प्रतिष्ठा की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। शहरों में सरकार की योजना जहां सभी न्यायालयों को एक छत के नीचे लाने की है, वहीं उत्तर प्रदेश के लिए अधिसूचित सर्वाधिक सभी 113 ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए वह हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में 51 ग्राम न्यायालय ही चल रहे हैं, शेष 62 ग्राम न्यायालयों की स्थापना जल्द हो जाए, इसके लिए सरकार केंद्र और उच्च न्यायालय के संपर्क में है। उसे यकीन है कि वह जल्द ही ग्राम न्यायालयों की स्थापना का लक्ष्य हासिल कर लेगी और इसके बाद ग्रामीण जन–जीवन न केवल आसान हो जाएगा, बल्कि सुदूर ग्राम्यांचल के गरीब आदमी के दरवाज़े पर न्याय खुद चलकर आ जाएगा।

न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए योगी सरकार सभी अदालतों को एक छत के नीचे लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट सहित 10 जिलों का चयन किया गया है। विधानसभा से पास अनुपूरक बजट में इस विशेष परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए योगी सरकार सभी अदालतों को एक

छत के नीचे लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट सहित 10 जिलों का चयन किया गया है। विधानसभा से पास अनुपूरक बजट में इस विशेष परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनुपूरक बजट पर चर्चा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की महत्वपूर्ण योजना का भी जिक्र करते हुए कहा था कि सुशासन में समय से न्याय मिलना जरूरी है। इसी भावना के साथ सरकार 10 जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसरों का निर्माण कराने जा रही है। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के संबंध में उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल गत दिनों गुजरात के बड़ौदा का अध्ययन करने गया था। वहां एकीकृत कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मॉडल सफलतापूर्वक लागू किया गया है। एक उच्चस्तरीय बैठक में कॉम्प्लेक्स की कार्ययोजना पर मुख्यमंत्री इस बात का भी संकेत दे चुके हैं कि अपराधों की अलग–अलग प्रकृति के अनुसार त्वरित न्याय के लिए अलग–अलग कानूनों से जुड़े अदालतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जिलों में यह अदालतें अलग–अलग जगहों से काम–काज संचालित करती हैं। कई जगह किराए के भवनों में अदालतें चल रही हैं। एक ही जिले में अलग–अलग दिशाओं में अदालतों के चलते न्यायिक अधिकारियों और फरियादियों दोनों को ही दिक्कत होती है। सुरक्षा इंतजाम और प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिक्कतें आती हैं। इसके मद्देनजर अदालतों के लिए एकीकृत कोर्ट भवन उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसे न्यायालय परिसरों के निर्माण का आदेश दिया जा चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री की यह योजना बेहद सुचिंतित भी है और दूरदर्शी भी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण, गृह तथा विधि एवं न्याय विभाग इस परियोजना पर काम कर रहे हैं।

एकीकृत भवन में कोर्ट, जजों के चैंबर, मीटिंग हॉल, वीडियो कोर्ट, पॉर्किंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाओं के लिए जगह होगी। न्यायालय भवन के साथ आवास भी होंगे। 10 जिलों में बनने जा रहे इस एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगे। न्यायालय भवनों और अधिवक्ता चैंबर तथा सभागार के साथ ही न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी, पार्किंग और फूड प्लाज़ा भी होगा।

यह तो शहरों की चिंता की बात हुई,

लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रामीणवादकारियों के हितों को लेकर भी गंभीरता से काम कर रहे हैं।

गौरतलब है कि शहर से दूर गांवों में न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम–2008 पारित किया था, लेकिन देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना अभी भी शत–प्रतिशत नहीं हो पाई है। आंध्रप्रदेश में 42, तेलंगाना में 55, गोवा में 2, जम्मू–कश्मीर में 20 और लद्दाख में 2 ग्राम न्यायालय स्थापित होने थे लेकिन वहां तो अभी इस मामले में शून्यता के ही हालात हैं। मतलब कि इन राज्यों में अब तक एक भी ग्राम न्यायालय वजूद में नहीं है।

इस समय देश में 15 राज्यों के लिए 478 ग्राम न्यायालय अधिसूचित हैं, अधिसूचित ग्राम न्यायालयों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में 113 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश भर में 2,500 ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव कर रखा है। पूर्व केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजीजू ने संसद में इस विषय पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कि ग्राम न्यायालय स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसमें केन्द्र सरकार की बहुत भूमिका नहीं है। हालांकि किसी भी राज्य में ग्राम न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य नहीं है। फिलहाल 15 राज्यों महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, लद्दाख, जम्मू–कश्मीर और हरियाणा में ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। इन 15 राज्यों में से 10 राज्यों में ही अभी यह न्यायालय कार्यरत हैं। पांच राज्यों आन्ध्रप्रदेश, गोवा, तेलंगाना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक भी ग्रामीण न्यायालय स्थापित नहीं हुए हैं। ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना के लिए अब तक 83 करोड़ 40 लाख रुपए केंद्र सरकार के स्तर पर जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में 36 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 23 कार्य कर रहे हैं। ग्राम न्यायालयों के गठन में मध्यप्रदेश, केरल और राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। इन तीनों राज्यों ने अधिसूचित किए गए सभी ग्राम न्यायालयों का गठन हो चुका है। मध्यप्रदेश में 89 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं और सभी 89 काम भी कर रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान में अधिसूचित किए गए सभी 45 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं तो केरल के लिए अधिसूचित सभी 30 ग्राम न्यायालय भी काम कर रहे हैं। गांवों में रहने वाले गरीब और वंचित लोगों को उनकी दहलीज पर न्याय दिलाने के लिए ग्राम न्यायालय बनाए जाते हैं। देश में पहली ग्राम न्यायालय का गठन 11 दिसंबर, 2001 को मध्यप्रदेश के नीमच जिले के झांतला गाँव में हुआ था। यह स्थापना मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनयम, 1996 के तहत की गई थी।

भारत में वर्ष 2008 में ग्राम न्यायालयों के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया। उच्च न्यायालय की अनुमति से राज्य सरकार ग्राम न्यायालय की स्थापना करती है तथा ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है। ग्राम न्यायालय एक भ्रमणशील न्यायालय है। ग्राम न्यायालय आपराधिक व

दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमें सुनता है। अपील दाख़िल होने के 6 माह के भीतर मामले की सुनवाई तथा निस्तारण किया जाता है। ग्राम न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष में एकमाह में उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। फौज़दारी मामले में निर्णय के विरुद्ध सत्र न्यायालय में तथा दीवानी मामलों में निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है।

नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय उपलब्ध करवाना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी नागरिक अपनी सामाजिक, आर्थिक व अन्य अशक्तताओं, विवशताओं की वजह से न्याय से वंचित न रहे, ग्राम पंचायत स्तर तक न्यायालय को पहुँचाना, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक की भागदौड़ को कम करना ही ग्राम न्यायालयों की स्थापना का मूल उद्देश्य है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे की नौ तहसीलों में स्थापित किए गए ग्राम न्यायालयों के लिए 72 पदों के सृजन को मंजूरी कई साल पहले ही दे दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालय की स्थापना से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना न किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना के संबंध में जवाब न देने वाले राज्यों (असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल) की सरकारों पर 1–1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्यों को एक माह के भीतर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और इस संबंध में अधिसूचना जारी कर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया था।

विकथ्य है कि इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को स्थानीय स्तर पर संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय उपलब्ध

कराना था। भारतीय संविधान के भाग–4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य का विधि तंत्र इस तरह से काम करे जिससे सभी नागरिकों के लिए न्याय प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध हो सके।

इसके साथ ही राज्यों को उपयुक्त विधानों, योजनाओं या किसी अन्य माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे।

ग्राम पंचायत स्तर पर न्यायालयों की तक पहुंच से लोगों के लिये समय और धन की बचत होगी। लंबित मामलों में एक बड़ी संख्या उन मामलों की भी है जिनका आपसी सुलह या मध्यस्थता से निस्तारण किया जा सकता है, ग्राम न्यायालयों के गठन से ऐसे मामलों में भारी कमी आएगी। न्याय प्रक्रिया में आसानी और इसके तीव्र निस्तारण से जनता में विधि व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा सो अलग।

ग्राम न्यायालय की रूपरेखा तैयार करने के लिये गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक ग्राम न्यायालय के व्यवस्थित संचालन के लिये विभिन्न स्तरों पर 21 सदस्यों को आवश्यक बताया था। ऐसे में पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना करना और उसका सुव्यवस्थित संचालन करना राज्यों के लिये एक बड़ी चुनौती है। यह जानते हुए भी योगी सरकार शत–प्रतिशत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ रही है। उस पर विचार कर रही है। योजना की रूपरेखा में केंद्रीय समिति ने ऐसे न्यायालयों की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया था। इसमें संदेह नहीं कि पिछले 10 वर्षों में यह लागत और बढ़ी है। इसे देखते हुए ज्यादातर राज्यों ने केंद्र सरकार की सहायता के बगैर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों के संचालन में असमर्थता जताई है। इस योजना के क्रियान्वयन में एक बड़ी चुनौती विधि तंत्र से जुड़े अन्य विभागों के सहयोग में कमी रही है। जिला स्तर पर कार्यरत वकील, पुलिस और विधि विभाग के अनेक शीर्ष अधिकारी नगरों या शहरों को छोड़कर गांवों में नहीं जाना चाहते, जिसके कारण योजना को समय–समय पर विभिन्न समूहों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन योगी सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत इन सब बाधाओं को पार करते हुए जनता प्रथम, जनता सर्वोपरि के सिद्धांत पर काम कर रही है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे की नौ तहसीलों में स्थापित किए गए ग्राम न्यायालयों के लिए 72 पदों के सृजन को मंजूरी कई साल पहले ही दे दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालय की स्थापना से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना न किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना के संबंध में जवाब न देने वाले राज्यों (असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल) की सरकारों पर 1–1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्यों को एक माह के भीतर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और इस संबंध में अधिसूचना जारी कर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया था।

उसे पता है कि ग्राम न्यायालय न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे नागरिकों को आसानी से न्याय उपलब्ध कराने में सहायक हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में सुधारों के परिणामस्वरूप न्याय तंत्र पर दबाव को कम करने व आम जनता के बीच विधि व्यवस्था के प्रति उनके नज़रिये को पुनः परिभाषित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उम्मीद है, सरकार का यह दृष्टिकोण न्यायिक सुधारों की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। •

मो. : 7459998968

वर्ल्ड क्लास सड़कों से सुरक्षित हुआ सफर

सतत मेंटीनेस प्रक्रिया से बढ़ेगी सड़कों की लाइफ
यूपी में 97 प्रतिशत चिह्नित सड़कें गड्ढामुक्त हुईं

–सुयश मिश्रा

सड़क मजबूत होगी तो उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। यूपी में वर्ल्ड क्लास सड़कों का जाल हो ताकि सुरक्षित सफर के साथ–साथ व्यापार में भी गति आ सके। योगी सरकार 2.0 नित नए आयाम हासिल कर रही है। चाहे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हो, माफियाओं पर बुल्डोजर हो या फिर कोई भी नई चुनौती। जनता के हित के लिए सरकार हर मुद्दे पर कमर कसे हुए है। उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारों के लिए गड्ढामुक्त सड़क बड़ा मुद्दा रहा है। सड़कें कैसे गड्ढामुक्त हों, उनकी लाइफ और ज्यादा कैसे बढ़ाई जाये। इसको लेकर यूपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है।

साल 2017 में जब पहली बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तभी से यूपी में सड़कों को गड्ढामुक्त करने की कवायद तेज हो गई। अभियान चलाए गए और ग्राउंड पर काम किया गया। साल 2022 में एक बार फिर सीएम योगी ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं उन्होंने पहले 15 नवंबर तक का समय दिया फिर इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया। लोकनिर्माण विभाग ने साल 2022 में प्रदेश की 60,497,03 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य तय किया था। जिसे समय सीमा 30 नवंबर तक पूरा कर लिया गया। इसमें विभागीय मंत्री के लेकर अधिकारी तक लगे हुए थे। खुद सीएम योगी काम पूरा होने तक अधिकारियों से जायज़ा लेते रहे। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित तथागत सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में भी प्रदेश की सड़कों की लंबी लाइफ और रख रखाव को लेकर हाल ही में बैठक भी हुई थी। लोक निर्माण मंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा था कि लोक निर्माण विभाग में अवश्यकता के हिसाब से पुनर्गठन किए जाने की जरूरत है। विभाग में कार्य दक्षता एवं क्षमता बढ़ाए जाने के लिए लघु अवधि, मध्यम अवधि एवं दीर्घ अवधि के लक्ष्य को ध्यान में रखकर रणनीति पर काम किया जाय। उन्होंने कहा था कि विभाग की कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए विभागीय अभियंताओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है। विभाग का पुनर्गठन इस तरह से किया जाय कि विभाग की उपलब्ध दक्षता का भरपूर उपयोग करते हुए आम

जनमानस के लिए गुणवत्ता परक सड़कें मित्तव्ययिता एवं समयबद्धता के साथ निर्मित की जा सकें, जिससे लोक निर्माण विभाग को देश का सबसे अच्छा विभाग बनाया जा सके। विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में समय बद्धता के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना है, जिससे हम विश्व स्तरीय सड़कें दे सकें। इस बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय सिंह चौहान समेत कई अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के तहत कुल 1,14,475 सड़कें आती हैं। इनकी कुल लंबाई 2 लाख 76 हजार 42 किमी है। विभाग ने इस बार 59,572 किमी का लक्ष्य रखा था। विभाग ने 97 फीसदी काम समय सीमा के अंदर पूरा कर दिया। इतना ही नहीं नए साल की शुरुआत हो चुकी है ऐसे में लोक निर्माण विभाग नई योजना ला रहा है। शासन स्तर पर इसको लेकर कवायद और तेज़ हो गई है। उच्च अधिकारियों की मानें तो वह इस कोशिश में हैं कि सड़कों की लाइफ और लंबी व गड्ढामुक्त हो। अब ट्राफिक के हिसाब से सड़कों के चौड़ीकरण की योजना बन रही है। इसके साथ ही सतत मेंटिनेंस प्रक्रिया शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में शायद यह पहली बार होगा। इस योजना में अब मेंटिनेंस की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी। सड़क की निर्धारित आयु तक ठेकेदार द्वारा उसे गड्ढामुक्त रखना होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभी तक कोई सतत मेंटिनेंस प्रक्रिया नहीं आई है। अभी तक सिर्फ एक साल तक ठेकेदार की सड़क रिपेयरिंग की जिम्मेदारी होती थी। सतत प्रक्रिया में जब ठेकेदार को सड़क का जिम्मा दिया जाएगा तो उसे मेंटिनेंस का खर्च पहले ही दे दिया जाएगा ताकि उसकी जिम्मेदारी रहे, वह सड़क की निश्चित आयु तक सतत मेंटिनेंस करवाता रहे। इतना ही नहीं लोक निर्माण विभाग तकनीकी सुधार भी करेगा जिससे सड़कों की लाइफ बढ़ सके। फॉरेन कंट्री में सड़कें लंबे समय पर कैसे चलती हैं, जबकि समय–समय पर भारत से इंजीनियरों और अधिकारियों का डेलीगेशन विदेशी टेक्नोलॉजी को समझने जाता रहता है।

प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है लगभग कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी वहां भी है। फर्क दूसरे जरूर हैं जैसे भारत का मौसम अलग है यहां जाड़ा गर्मी बरसात साल में तीन मौसम होते हैं विदेशों का मौसम अलग है। विदेशों में साल भर सड़कों की रिपेयरिंग का कार्य करने का मौका मिल जाता है, लेकिन हमारे यहां बरसात में भारी बारिश के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाता। सड़क निर्माण में अनियमितता के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा विभाग भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है। फिर भी यदि कहीं किसी भी स्तर पर अनियमितता होती है तो उस पर सख़्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि विभाग ने तमाम कार्यों को ऑनलाइन जोड़कर पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। विभाग में पारदर्शिता

लाने के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर निर्माण कार्यों की मांप तक ऑनलाइन हो रही है। निर्माणाधीन कार्यों की क्वालिटी को फील्ड पर मौजूद विभाग के अधिकारी 'चाणक्य' साफ्टवेयर पर कार्य प्रगति से जुड़ा डाटा अपलोड करते हैं ताकि गुणवत्ता में कोई कमी न आए। 'सृष्टि वेबसाइट पर जिला एवं राज्य मार्गों का समस्त डाटा अपलोड किया जा चुका है। नवीन तकनीक के प्रयोग से लोक निर्माण विभाग द्वारा साल 2018–19 में लगभग 30.42 लाख घनमीटर एग्रीगेट की बचत की गई है। इससे निर्माण लागत में भी लगभग 941.80 करोड़ की बचत हुई है। एनर्जी एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत का प्रतिवर्ष कुल कार्बन उत्सर्जन लगभग 1500 मिलियन टन है। विभाग द्वारा 1.2 मिलियन टन की बचत की गई है। मार्ग निर्माण में नवीनतम तकनीक के प्रयोग एवं प्रशिक्षण के लिए विभाग द्वारा इंजीनिर्स को सीआरआरआई दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी वाराणसी और दिल्ली से विभाग के इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। ताकि सड़कों को और मजबूत व टिकाऊ बनाया जा सके।

अब ठेकेदार की भी तय होगी जिम्मेदारी

लोक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण के बाद अभी दो वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि होती है। इसका आशय यह है कि सड़क बनाने के बाद यदि दो वर्ष तक उसमें कोई कमी या दोष पैदा होता है तो सड़क का निर्माण करने वाले ठेकेदार को उसे ठीक करना होता है। इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है। इसके बाद ही लोक निर्माण विभाग ठेकेदार की ओर से जमा की गई सेक्योरिटी राशि को उसके पक्ष में जारी करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि पांच वर्ष है लेकिन इसमें ठेकेदारों को सड़क के रखरखाव और मरम्मत के लिए अलग से एक निश्चित दर से धनराशि के भुगतान की व्यवस्था हैं। लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज़ पर सड़क का निर्माण करने वाले ठेकेदार को पांच साल तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपने की व्यवस्था को अपनाना चाहता है। इसके पीछे उद्देश्य है कि जब ठेकेदार पर ही पांच साल तक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी होगी तो वह निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा। सड़कों का निर्माण कार्य अच्छा होगा तो वह जल्दी टूटेंगी नहीं और जनता को असुविधा नहीं होगी। रखरखाव का खर्च भी सीमित होगा। फिलहाल इस व्यवस्था को प्रदेश के हर मंडल के एक ब्लाक में पायलट परियोजना के तौर पर लागू करने का इरादा है। •

मो. : 8924856004

सशक्त और आत्मनिर्भर बनती महिलाएं

–मुकुल मिश्र

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की दूसरी पारी और भी सधी व सशक्त है। योगी सरकार के कामकाज और उनकी नीतियों से जहां समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है, वहीं प्रदेश की आधी आबादी यानि महिलाओं और बेटियों के लिए योगी सरकार बहुत काम कर रही है। वैसे तो योगी सरकार द्वारा लिये गये जनहित के फैसलों पर सरकार की हर ओर खूब तारीफ हो रही है, लेकिन योगी सरकार ने महिलाओं के हित में जो फैसले लिये हैं वे उनकी सरकार की उपलब्धियों में खूब सराहे जा रहे हैं। बात चाहे महिला शिक्षा की हो, उनकी चिकित्सा की, सुरक्षा की, नौकरी की अथवा उनके मौलिक अधिकारों की। किसी भी राष्ट्र में महिला सशक्तीकरण तब होता है, जब उस राष्ट्र की महिलाएं व बेटियां आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध होती हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण ही उस देश व प्रदेश के विकास को गति देता है। इस तथ्य पर अमल करते हुए राज्य की योगी सरकार महिलाओं और बेटियों को हर क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध करा रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से समृद्ध बनें।

महिला सशक्तीकरण कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने में पूरी व्यापकता समेटे महिलाओं को गांव से लेकर शहर तक हर क्षेत्र में समृद्ध करने का नाम है। हर परिवार की धुरी महिला ही है। उसकी समझदारी, त्याग और तपस्या से ही परिवार की उन्नति जुड़ी है। कहा भी जाता रहा है कि हर सफल पुरूष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन यहां तो महिलाओं की सफलता के पीछे पूरी सरकार ही खड़ी है। महिलाओं के लिए घर से लेकर बाहर तक सुरक्षित माहौल बनाया गया। उन्हें पढ़ने–लिखने की सुविधा उनके घर के आस–पास ही उपलब्ध करायी गयी। सरकार का नारा है: बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ। इस योजना के तहत एक करोड़ 90 लाख बेटियों को जागरूक किया गया। प्रदेश के थानों में पन्द्रह हजार से अधिक महिला पुलिकर्मियों को नियुक्त करते हुए दस हजार से अधिक महिला बीटों का आवंटन हुआ। राज्य में 79 महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र बनाये गये। निराश्रित महिला, वृद्धावस्था तथा दिव्यांगजन महिलाओं को पेंशन मिल रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब परिवार अपनी बेटियों के हाथ पीले कर रहे हैं।

महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बनाये गये। उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की योजना में महिला उद्यमी भी लाभान्वित हो रही हैं। कभी गांवों में चिकित्सा सुविधा के अभाव में महिलाओं की रास्ते में ही मौत हो जाती थी। आज गांव तक बेहतर रास्ते और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। जिससे महिला एवं शिशु मृत्यु दर में ख़ासी कमी आयी है। योगी सरकार का मानना है कि जब हर क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी होगी तो स्वतः ही माहौल उनके अनुकूल होता जायेगा। पहले बालिका शिक्षा का आंकड़ा शहरों में अधिक था और ग्रामीण क्षेत्र में अपेक्षाकृत बालिकाओं की शिक्षा का आंकड़ा कम था, लेकिन योगी सरकार ने इसे विस्तार देते हुए बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया। कम पारिवारिक आय और स्कूलों के दूर होने के चलते लड़कियां शिक्षा से वंचित हो जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सच कहा जाये तो योगी सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं से ना सिर्फ महिलाएं सशक्त हुयी हैं बल्कि उन्हें सुरक्षा के साथ ही शक्ति, सम्मान व गौरव प्राप्त हुआ है। आज महिलाएं व बेटियां आत्मनिर्भर यूपी की पहचान बन रही हैं।

यूपी की महिलाओं और बेटियों के कदम सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश के साथ कदमताल कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ग्रामीण व शहरी परिवेश से जुड़ी हुई महिलाओं और बेटियों को एक ओर आत्मनिर्भर बना रही है तो वहीं उनको सीधे तौर पर आर्थिक सहायता भी मुहैय्या करा रही है। जबसे किसी योजना का पैसा सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में जाने लगा भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो गया। योगी सरकार की नीति भी जीरो टालरेन्स की ही है। राशन कार्ड में महिलाओं को परिवार का मुख्यिा माना गया और उनके नाम पर राशन कार्ड बने। जिससे परिवारों को खासी मजबूती मिली। सरकार की–हर घर नल–योजना से सबसे ज्यादा महिलाओं को ही लाभ हुआ। बुन्देलखण्ड जैसे इलाके में उन्हें पूरा दिन पानी के लिए ही संघर्ष करना पड़ता था।

राज्य की योगी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2023–24 का अपना बजट पेश किया, उसमें भी महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजनाओं में अधिक धन आवंटित किया। वैसे तो महिला एवं बाल विकास विभाग अलग से कार्यरत है जो महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए काम करता है। बावजूद इसके राज्य की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा व उनके भविष्य के प्रति सकारात्मक फैसले लिए जा रहे हैं। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलम्बन को मिशन शक्ति का नाम देकर उनके समग्र विकास की परिकल्पना की गयी है। योगी के सशक्त नारी–सशक्त प्रदेश के नारे को साकार करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है–वह है महिलाओं की सुरक्षा। जब वे घर से बाहर निकलें तो खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकें और उनके घर–परिवार के

लोग भी पूरी तरह से निश्चिन्त हों। सरकार ने इसके लिए पुलिस बल में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की। इसके साथ ही सरकार ने लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में पीएसी की तीन बटालियनों के गठन का भी निर्णय लिया है। महिला थाने बनाये गये हैं। वीमेन पावर लाइन 1090 की स्थापना की गयी। महिला हेल्पलाइन बनायी गयी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, पुलिस की आपातकालीन सेवा तो पहले से ही काम कर रही है।

योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की, जिसमें अब तक 16 लाख बेटियां लाभान्वित हुयीं। निराश्रित महिला पेंशन योजना में 32 लाख से अधिक को पेंशन मिली है, जिससे उनके जीवन में आशा की किरण का संचार हुआ। दो लाख से अधिक महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित हुयी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों एवं नैफेड के माध्यम से टेक होम राशन के रूप में छह माह से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग एक करोड़ 85 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। इसी तरह से छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और रक्त की कमी को कम करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन में इन्हें आच्छादित किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम योगी सरकार संचालित कर रही है। जिससे बालक–बालिका अनुपात सही हो सके। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की स्थिति में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं एक हजार रूपये चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरूष कामगारों की पत्नियों को छह हजार रूपये एकमुश्त दिये जाने का प्रावधान सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं व बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सकीय सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में 56 करोड़ रूपये की बजट में व्यवस्था की गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को संगठित करके उन्हें सशक्त व स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों एवं संकुल स्तरीय संघों से जोड़ा गया है। इन महिला स्वयं सहायता समूहों को उनकी जरूरत के अनुसार कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दूकानों का आवंटन किया गया। जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। सशक्त नारी और समृद्ध प्रदेश के लिए योगी सरकार ने बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की। महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए 2.61

करोड़ इज्ज़तघर बनाये गये। जिससे लगभग दस करोड़ लोग लाभान्वित हुए। इज्ज़तघर–शौचालयों के बनने से सबसे ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हुयीं, क्योंकि गांवों में खुले में और वो भी दिन में शौच के लिए जाना उनके लिए बड़ा अपमानजनक होता था। आज इज्ज़तघर बन जाने से महिलाएं–बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसी तरह ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण करना योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अकेले एमएसएमई इकाइयों में दो करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसी तरह विभिन्न निवेश परियोजनाओं के शुरू होने से पांच लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्टार्ट अप नीति के अन्तर्गत पांच लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 3.50 लाख युवाओं को संविदा पर सरकारी नियुक्ति मिलेगी। इन स्वरोजगार से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। दस लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक करोड़ महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जिसमें 58,758 महिलाएं बैंकिंग कारेस्पोंन्डेन्ट यानि बीसी सखी के रूप में चयनित की गयी हैं। ये प्रदेश की सभी 58000 ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से बीसी सखी के रूप में उन्हें प्रति माह चार हजार रूपये दिये जायेंगे। समूह से जुड़ी महिलाओं को स्टाइपेंड भी दिया जायेगा जिससे प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।

शहरी क्षेत्रों के साथ ही दूरस्थ ग्रामीण इलाकों की बेटियों–महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच ने प्रदेश भर में मिशन शक्ति के अंतर्गत अनकों कार्यक्रमों की शुरुआत की। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में 487 अभियुक्तों को आजीवन कारावास मिला। इसी तरह 4092 अभियुक्तों को कारावास हुआ। पाक्सो अधिनियम एवं महिला अपराधों के मामलों में सजा दिलाने में देश में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। महिला सुरक्षा के लिए बीट स्तर पर महिला कॉन्स्टेबल की तैनाती हो, जिससे कि महिला तथा बच्चियों की सुरक्षा पर गहन निगरानी हो सके।

बेटियों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल, कॉलेजों में एंटी रोमियो स्क्वॉड को सक्रिय करना, शाम को पुलिस की एक टीम बाजारों और भीड़ वाले इलाकों में जाकर फुट पेट्रोलिंग भी शामिल है। जिससे ना सिर्फ प्रदेश की कानून–व्यवस्था को और चुस्त–दुरुस्त रखा जा सके बल्कि महिला अपराधों पर रोक लग सके। सच कहा जाये तो योगी सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं से ना सिर्फ नारी सशक्त हुयी हैं बल्कि उन्हें सुरक्षा के साथ ही शक्ति, सम्मान, गौरव प्राप्त हुआ है। •

मो. : 9415464591

योगी सरकार ने महिलाओं के हित में जो फैसले लिये हैं वे उनकी सरकार की उपलब्धियों में खूब सराहे जा रहे हैं। बात चाहे महिला शिक्षा की हो, उनकी चिकित्सा की, सुरक्षा की, नौकरी की अथवा उनके मौलिक अधिकारों की। किसी भी राष्ट्र में महिला सशक्तीकरण तब होता है, जब उस राष्ट्र की महिलाएं व बेटियां आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध होती हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण ही उस देश व प्रदेश के विकास को गति देता है। इस तथ्य पर अमल करते हुए राज्य की योगी सरकार महिलाओं और बेटियों को हर क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध करा रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से समृद्ध बनें।

शिक्षा से बदली यूपी की सूरत

–विमल किशोर पाठक

उत्तर प्रदेश संभवतः देश का पहला राज्य है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले आत्मसात किया। इस नीति के राज्य में अमलीजामा पहनने के साथ ही इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को भी समानान्तर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, थ्री डी प्रिंटिंग या फिर इससे संबंधित सर्टिफिकेट कोर्सेज से छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहले से ही व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीते साढ़े छह वर्ष में नकल विहीन परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई है। नकल माफिया पर लगाम कसी गई है। पहली बार हुआ है जब माध्यमिक शिक्षा जिसमें हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा जो पहले दो से तीन महीने तक चलती रहती थी वो मात्र 15 दिन में संपन्न हुई है और मात्र 14 दिन में परिणाम भी आए हैं। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन (परीक्षा से लेकर परिणाम जारी होने तक) में आए हैं। यह भी उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा के क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है। वहीं

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया। आयोग के माध्यम से उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा, अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती की जानी सुनिश्चित की गयी है। आयोग प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षकों, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल व संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, अनुदेशकों का चयन करेगा।

जहां तक शिक्षकों की भर्ती का विषय है तो कोई भी मामला न्यायालय में लंबित नहीं है। 1.64 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में इस सरकार ने की है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर किया जा रहा है। यदि कहीं वेकेंसी है चाहे वो माध्यमिक में हो, बेसिक में हो, उच्च शिक्षा में हो, प्राविधिक में हो, व्यवसायिक शिक्षा में हो या फिर संस्कृत विद्यालयों में हो, इन सबकी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने एक नए शिक्षा आयोग का गठन भी कर दिया है। साफ है कि शिक्षा के माध्यम से जहां राज्य की योगी सरकार ने देश और प्रदेश के भविष्य को नयी दिशा देने की तैयारी कर ली है वहीं इसी आधार पर सूरत और सीरत भी बदलने के लिए कमर कस ली गयी है।

अपनी सोच और प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया। आयोग के माध्यम से उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा, अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती की जानी सुनिश्चित की गयी है। आयोग प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षकों, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल व संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, अनुदेशकों का चयन करेगा। साथ ही विश्वविद्यालयों से संबद्ध, सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन भी आयोग से किया जाएगा। यह एक निगमित निकाय होगा और इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रभावी होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समाप्त हो गए। अभी तक विभिन्न विभागों में शिक्षकों के चयन के लिए संस्था स्तर की चयन समिति, चयन बोर्ड, चयन आयोग की ओर से अलग–अलग चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसको एकरूपता देने, योग्य शिक्षकों व अनुदेशकों के चयन के लिए इस आयोग का गठन किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार की ओर से गठित नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य पद संभालने के दिन से तीन साल के लिए या 65 वर्ष की आयु तक के लिए तैनात होंगे। कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकेगा। माना जा रहा है कि नए आयोग के अध्यक्ष पद पर कोई वरिष्ठ आईएएस या प्रमुख शिक्षाविद की तैनाती शासन करेगा। वहीं सदस्यों में न्यायिक सेवा व अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाएगा।

वास्तव में आज से सात साल पहले उप्र में स्कूलों की स्थिति ऐसी थी कि बच्चे यहां आने से डरते थे। स्कूलों में पेड़

प्रदेश सरकार की ओर से गठित नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य पद संभालने के दिन से तीन साल के लिए या 65 वर्ष की आयु तक के लिए तैनात होंगे। कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकेगा। माना जा रहा है कि नए आयोग के अध्यक्ष पद पर कोई वरिष्ठ आईएएस या प्रमुख शिक्षाविद की तैनाती शासन करेगा। वहीं सदस्यों में न्यायिक सेवा व अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाएगा।

और झाड़ियां उगी रहती थीं। बच्चों के नामांकन में गिरावट थी, आज उन्हीं विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है। आज वहां बच्चों की संख्या 60 लाख बढ़ी है। बेसिक शिक्षा में परिवर्तन दिखता है, अब बारी माध्यमिक शिक्षा की है। यही वजह है कि सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प फेज 2 चलाने का निर्णय लिया। सरकार की सोच और नीतियों का ही परिणाम है कि परिषदीय विद्यालयों में पहले की अपेक्षा बच्चों की संख्या 1.30 करोड़ से बढ़कर 1.91 करोड़ हो गई है। ज़ाहिर इस संख्या को बढ़ाने के साथ, बच्चों की पढ़ाई जारी रखना भी महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षक ड्राप आउट रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ख़ासकर बच्चियों के लिए, जिनके अभिभावक कक्षा पांच के बाद स्कूल नहीं भेजते। इसीलिए सरकार ने निर्देशित किया है कि यदि एक बच्चा स्कूल नहीं आता है तो उसके अभिभावक से बात करें, उसके घर जाकर जानकारी लें। शिक्षकों की जिम्मेदारी है, ऑपरेशन कायाकल्प की तरह डीबीटी की सफलता के लिए काम करने की। डीबीटी से जो पैसा भेजा गया, उसका सही प्रयोग हो और बच्चे ड्रेस में ही स्कूल आएं। इसके लिए शिक्षक, अभिभावकों के साथ बैठक करें। वास्तव में मुख्यमंत्री योगी की सोच है कि यदि शिक्षक अपडेट होगा तो पूरी पीढ़ी अपडेट होगी। इसीलिए उन्होंने शिक्षकों को अपडेट करने के लिए समय–समय पर शिक्षण, प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कार्यक्रम आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

वहीं दूसरी ओर नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि छह साल में 5.50 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त होकर सक्षम बने हैं। इसमें जो पैरामीटर तय किया है, वह था शिक्षा। योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल–चूल परिवर्तन किए हैं, वह आगे पांच–दस साल में और बेहतर बदलाव दिखेंगे। आकांक्षात्मक जिलों में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। पिछले 6 वर्ष में एक लाख 64 हजार शिक्षकों की भर्ती बेसिक

और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

इससे इतर मुख्यमंत्री योगी ने देश के प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थान समूहों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए खुला आमंत्रण दे रखा है। उनका मानना है कि शिक्षा में किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि यह देश और समाज का भविष्य संवारने का माध्यम है। वास्तव में उत्तर प्रदेश जैसी युवा आबादी वाले राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना ही चाहिए। सरकार ने भी तय कर रखा है कि असेवित जिलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाले संस्थानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्यमंत्री योगी का स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। पुरातन काल से यह प्रदेश, शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। काशी इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। काशी, अयोध्या, मथुरा संस्कृति और सभ्यता के प्राचीन नगर रहे हैं। हालांकि बीते दशकों में शिक्षा के प्रति विमुखता का भाव देखा गया किंतु आज देश व प्रदेश में शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक भाव जाग्रत हुआ है। 2017 से पूर्व प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे, विगत 06 वर्षों के प्रयास के बाद आज 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कालेज संचालित हैं, जबकि 16 निर्माणाधीन हैं और पीपीपी मोड पर 16 और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। आज प्रदेश में 22 राज्य व 03 केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित हैं, 03 राज्य विश्वविद्यालय निर्माणाधीन हैं जबकि 36 निजी विश्वविद्यालय, 02 एम्स, 02 आईआईटी व आईआईएम संचालित हैं। 2000 से अधिक पॉलिटेक्निक व वोकेशनल इंस्टिट्यूट भी संचालित हैं, इनकी लंबी श्रृंखला है, जो यहां के शैक्षिक परिदृश्य को मज़बूत बनाते हैं। बावजूद इसके, अभी बहुत से जनपद ऐसे हैं, जहां कोई विश्वविद्यालय क्रियाशील नहीं हैं। स्थानीय युवाओं की आकांक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए एक नई नीति लागू की, जिसके आशातीत परिणाम भी मिले हैं। •

मो. : 9984905555

गन्ना किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्य

–रजनीश वैश्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खेती–बाड़ी की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे राज्य की धरती फिर से सोना उगलने लगी है। डबल इंजन की सरकार अन्नदाताओं के हित में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, जिससे खेतों में उपज व आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। गन्ना किसानों की खुशहाली के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे फलस्वरूप उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य के साथ ही सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राज्य तथा खांडसारी की सर्वाधिक यूनिट वाला राज्य भी है। उत्तर प्रदेश की जी.डी.पी. में गन्ना और चीनी का लगभग 9 प्रतिशत का योगदान है।

योगी सरकार के प्रयासों से बंद चीनी मिलों में नयी जान फूंकी गयी है। यह चीनी मिलें किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने तथा विकास का प्रतीक बनी है। गुणवत्तायुक्त चीनी के लिए पिपराइच, गोरखपुर व मुंडेरवा, बस्ती में 5,000 टीसीडी की सल्फरलेस चीनी मिल स्थापित की गयी है। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत में रमाला चीनी मिल का पुनरोद्धार कर, पेराई क्षमता बढ़कर 5,000 टीसीडी किया गया। चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना भी की जा रही है।

विगत 06 वर्षों में चीनी मिलों द्वारा रिकॉर्ड 6,403 लाख टन गन्ने की पेराई एवं 683.07 लाख टन चीनी का रिकार्ड उत्पादन किया गया। चीनी के रिकार्ड उत्पादन से किसानों की आय में 40,380 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। प्रदेश में गन्ना खेती का रकबा 20 लाख से बढ़कर 27 लाख हेक्टेयर हुआ है। वहीं, गन्ने की उत्पादकता 70 टन से बढ़कर 80 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।

एथनॉल उत्पादन में भी प्रदेश ने लम्बी छलांग लगायी है। वर्ष 2016–17 में जहां 42.07 करोड़ ली. एथनॉल का उत्पादन हुआ था, वहीं वर्ष 2022–23 में बढ़कर यह आंकड़ा 160 करोड़

ली. पर पहुंच गया। आज राज्य की अधिकतर चीनी मिलों में चीनी के साथ ही एथेनॉल भी बनाया जा रहा है। एथेनॉल द्वारा प्रदेश ग्रीन एनर्जी का केंद्र भी बन रहा है। प्रदेश में ऑनलाइन खांडसारी लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की गयी है। पहली बार 284 नई खांडसारी इकाइयों हेतु लाईसेंस निर्गत किए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1238.25 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश तथा 41,800 लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

औसत गन्ना उत्पादकता

वर्ष 2016–17 : 72.38 मी. टन प्रति हेक्टेयर

वर्ष 2022–23 : 83.95 मी. टन प्रति हेक्टेयर

(प्रति हेक्टेयर 11.57 मी. टन अतिरिक्त गन्ने का उत्पादन)

औसत चीनी परता

वर्ष 2016–17 : 10.61 प्रतिशत

वर्ष 2022–23 : 11.43 प्रतिशत

(बी–हेवी शीरे एवं सीधे गन्ने से एथेनॉल उत्पादन के साथ 9.60 प्रतिशत)

देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राज्य

उत्पादन

वर्ष 2016–17 : 42.07 करोड़ ली.

वर्ष 2022–23 : 160 करोड़ ली.

रिकॉर्ड भुगतान, गन्ना किसान खुशहाल

आज से करीब 6 वर्ष पूर्व गन्ना किसानों को पर्ची की चोरी और घटतौली जैसी समस्याओं से परेशान रहना पड़ता था। समय से गन्ना मूल्य का भुगतान भी नहीं होता था। योगी सरकार ने गन्ना किसानों से जुड़ी इन विसंगतियों को दूर किया। मिशन मोड में कार्य करते हुए गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 2.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से करवाया गया। यह राशि वर्ष 1995 से मार्च 2017 तक 22 वर्षों में हुए कुल भुगतान से भी अधिक है।

अन्नदाताओं की पाई–पाई चुकाने का संकल्प दोहराने के साथ विगत 06 वर्ष में कराए गए गन्ना मूल्य भुगतान में वर्ष 2007–2012 की अवशेष 13.62 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2012–2017 की.10,648.48 करोड़ रुपये की धनराशि का भी भुगतान किया गया। विगत 06 पेराई सत्र 2016–17 (19 मार्च 2017 से) 2017–18, 2018–19,

2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के देय गन्ना मूल्य का भुगतान पूर्ण हो चुका है। वर्तमान पेराई सत्र 2022–23 का भी लगभग 84 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है।

बंद चीनी मिलों में जान

योगी सरकार के प्रयासों से बंद चीनी मिलों में नयी जान फूंकी गयी है। यह चीनी मिलें किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने तथा विकास का प्रतीक बनी है। गुणवत्तायुक्त चीनी के लिए पिपराइच, गोरखपुर व मुंडेरवा, बस्ती में 5,000 टीसीडी की सल्फरलेस चीनी मिल स्थापित की गयी है। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत में रमाला चीनी मिल का पुनरोद्धार कर, पेराई क्षमता बढ़कर 5,000 टीसीडी किया गया। चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना भी की जा रही हैं।

संचालित चीनी मिल : 118

2 नई चीनी मिलों की स्थापना
4 चीनी मिलों का पुर्नसंचालन
30 चीनी मिलों में क्षमता विस्तार
चीनी मिलों में कुल 78,900 टी.सी.डी. की अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन

गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति से छोटे किसानों को बड़ा फायदा

गन्ना कृषकों की सुगमता के लिए पेराई सत्र 2023–24 के लिए गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। जारी नीति में छोटे गन्ना कृषकों को गन्ना आपूर्ति में प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है। गन्ना कृषकों की बढ़ रही उपज के दृष्टिगत सट्टे की सीमा में 50 कु./हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी की गयी है।

छोटे कृषक अब 60 कुं. की जगह अब 72 कुं.वाले पट्टाधारक माने जाएंगे। उन्हें प्राथमिकता पर गन्ना पर्ची मिलेगी। सीमान्त कृषक 01 हेक्टेयर (अधिकतम 900 कुं. अथवा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में अधिकतम 1400 कुं. तक), लघु कृषक 02 हेक्टेयर (अधिकतम 1800 कुंतल अथवा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में अधिकतम 2800 कुं. तक) तथा सामान्य कृषक 05 हेक्टेयर (अधिकतम 4500 कुंतल अथवा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में अधिकतम 7000 कुं. तक) माने जा रहे हैं। जारी नीति में किसी कृषक का अधिकतम सट्टा निर्धारण, गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टेयर) गुणा 900 कुं. अथवा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में 7000 कुं. में से जो भी कम हो, किया जा रहा है। नीति में यह व्यवस्था की गयी है कि सट्टा धारक सदस्य कृषक की पेराई सत्र के दौरान आकस्मिक मृत्यु की दशा में सट्टा बंद नहीं होगा। सैनिकों,

अर्द्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके विधिक उत्तराधिकारियों को गन्ना आपूर्ति में 20 प्रतिशत की प्राथमिकता दी जा रही है। नीति में ट्रेंच विधि से बुआई, सहफसली खेती एवं ड्रिप सिंचाई के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने वाले कृषकों को सट्टे में प्राथमिकता मिल रही है।

आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं

गन्ना बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर आय अर्जन के अवसर सुलभ हो रहे हैं। इस कार्य के लिए 3,196 महिला स्वयं सहायता समूह क्रियाशील हैं। इन समूहों से जुड़कर करीब 60,000 ग्रामीण महिला उद्यमी बल आत्मनिर्भर की राह पर आगे बढ़ रही हैं।

समूहों द्वारा अब तक 38 करोड़ गन्ना पौध का उत्पादन कर 102 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी की गयी है। प्रत्येक समूह की औसत आमदनी 75,000 रुपये से 27 लाख रुपये के बीच हो रही है। समूह से जुड़ी महिलाओं को 7,500 रुपये से 2 लाख रुपये तक की आय हो रही है।

गन्ना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से 20 वर्षों बाद कृषि स्नातकों की गन्ना पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति की गयी। इस नियुक्ति से गन्ना विकास एवं विपणन के कार्य में गति आयी। गन्ना पर्यवेक्षक गन्ना किसानों के सीधे संपर्क में रहते हैं, इससे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना आसान रहता है। उनके माध्यम से गन्ना किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ भी मिल रहा है।

लॉकडाउन में भी चीनी मिलों का निर्बाध संचालन

उत्तर प्रदेश में करीब 60 लाख गन्ना किसान हैं। प्रत्येक मिल में 25 से 40 हजार किसान जुड़े हुए हैं। एक–एक मिल 8 से 10 हजार लोगों को रोजगार देती है। इनके हितों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में चीनी मिलों का संचालन जारी रहा। लॉकडाउन के दौरान भी इन मिलों के चलते रहने से कोई परेशानी नहीं आयी। इसका नतीजा रहा कि इस विषम समय में भी उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर रहा। कोरोना काल में जब सैनिटाइजर की मांग बढ़ी तब प्रदेश की चीनी मिलों के सहयोग से इसका रिकॉर्ड उत्पादन कर देश के 28 राज्यों के अलावा विदेश में भी इसे मुहैया कराया गया। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समस्त चीनी मिलों का निर्बाध संचालन कराने के साथ 5,954 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। •

मो. : 8840973541

विकास के नए सोपान रचती यूपी सरकार

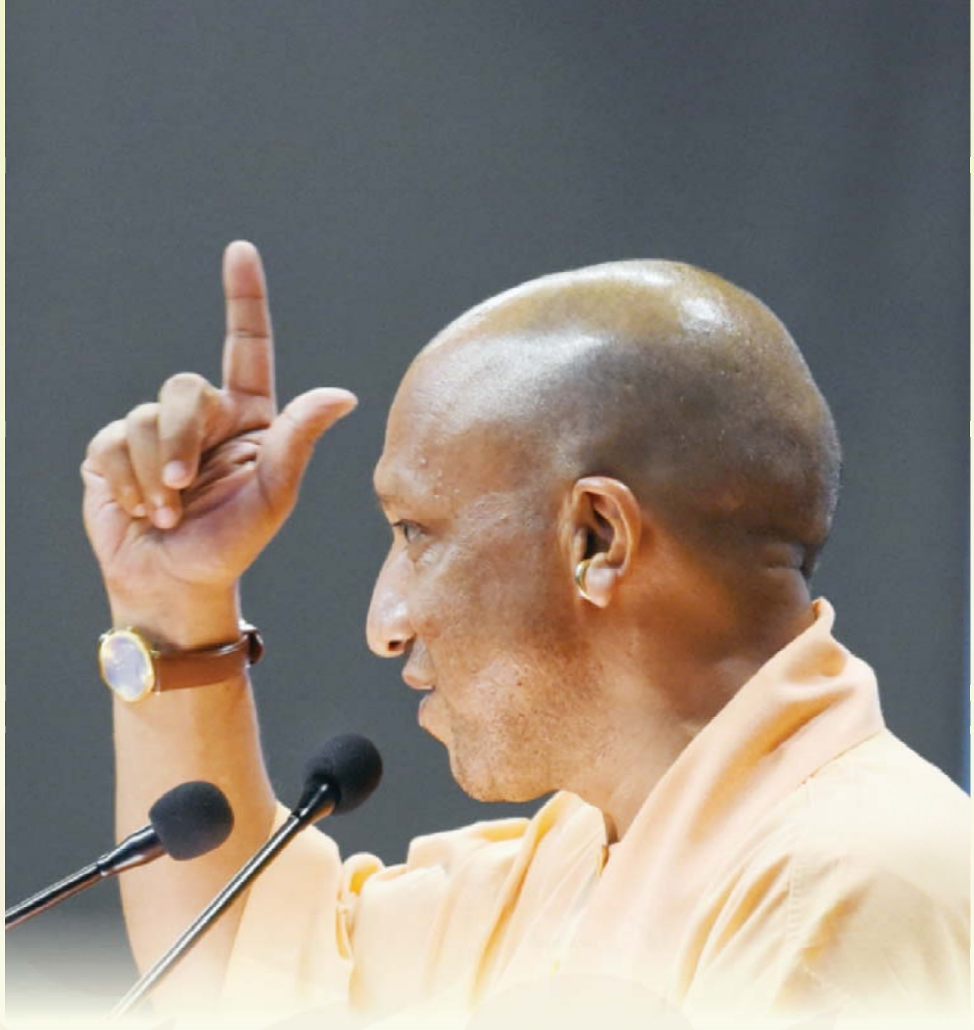

—एम. मिश्रा

कनेक्टिविटी के मामले में यूपी देश का ऐसा पहला पांच इन्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बनने वाला है। फिलवक्त उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर तो ऑपरेशनल हैं और अयोध्या व जेवर एयरपोर्ट पर तेज़ी से काम जारी है। उम्मीद है कि ये निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अगले वर्ष तक बनकर तैयार हो जायेंगे। नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसे अब जेवर एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। माना जा रहा है कि इसके पूरा हो जाने से यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विकल्प होगा। इसे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की योजना है। यह उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और उत्तर प्रदेश को एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण कराने वाले राज्य का दर्ज़ा हासिल हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य कनेक्टिविटी का हब बन रहा है। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के साथ ही साथ उसके विकास की रफ्तार को भी तय करती है कनेक्टिविटी। चाहे वह सड़कें हो, एयरपोर्ट हो या फिर एक्सप्रेस–वे। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यह सभी ज़रूरी है और इनके जरिये ही होगा राज्य का विकास। यूपी देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पांच इन्टरनेशनल एयरपोर्ट होंगे और भारत, दुनियां के उन चार बड़े देशों में शामिल हो जायेगा जहां सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं। फिलवक्त उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर तो ऑपरेशनल हैं और अयोध्या व जेवर एयरपोर्ट पर तेजी से काम जारी है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या का राममंदिर, मथुरा का कृष्णजन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में विश्वभर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इसी तरह आगरा में ताजमहल और पूर्वांचल में बौद्ध तीर्थस्थलों में श्रद्धालु–पर्यटक आते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्य के विभिन्न शहरों और देशों के लिए बहुत अच्छी कनेक्टीविटी है। जिससे उत्तर प्रदेश के पर्यटन को गति मिल रही है। किसानों के उत्पादों को बाज़ार मिलेगा। निवेश के नये अवसर खुल रहे

हैं। इससे व्यापार बढ़ेगा और लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की योगी सरकार में दोगुनी रफ्तार से विकास हो रहा है। कनेक्टिविटी के मामले में यूपी देश का ऐसा पहला पांच इन्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बनने वाला है। फिलवक्त उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर तो ऑपरेशनल हैं और अयोध्या व जेवर एयरपोर्ट पर तेज़ी से काम जारी है। उम्मीद है कि ये निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अगले वर्ष तक बनकर तैयार हो जायेंगे। नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसे अब जेवर एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। माना जा रहा है कि इसके पूरा हो जाने से यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विकल्प होगा। इसे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की योजना है। यह उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और उत्तर प्रदेश को एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण कराने वाले राज्य का दर्ज़ा हासिल हो जायेगा। जिससे आने वाले आने वाले समय में राज्य की सूरत बदल जायेगी। इस एयरपोर्ट की परिकल्पना तकरीबन बीस वर्ष पहले की गयी थी, लेकिन दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से काफी कम दूरी होने के कारण इसको केन्द्र सरकार से अनुमति नहीं मिली थी। वर्ष 2017 में योगी सरकार बनने के बाद केन्द्र की मोदी सरकार ने इसे बनाने की अनुमति दे दी।

योगी सरकार राज्य के कई शहरों को सस्ती हवाई सेवाओं से भी जोड़ रही है। कनेक्टिविटी बढ़ने से उद्यमी राज्य का रूख़ करेंगे और निवेश का माहौल बननेगा। समय में पर्यटक और तीर्थयात्री अपने गन्तव्य तक पहुंच सकेंगे। अयोध्या में राममंदिर का निर्माण हो रहा है। अगले वर्ष तक भव्य श्रीराम मंदिर तैयार होने के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में एकाएक वृद्धि होगी। एयरपोर्ट बन जाने से विश्वभर से आने वालों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल भी दुनियां में एक महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। दुनियां के अलग–अलग हिस्से से बौद्ध धर्म के अनुयायी यहां आते हैं, हालांकि पहले कुशीनगर के लिए कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी लेकिन वर्ष 2021 में कुशीनगर का एयरपोर्ट शुरू चुका है। बौद्ध धर्म के अनुयाइयों को की संख्या में भी वद्धि होगी और पर्यटन को भी गति मिली है। जहां–जहां भी पर्यटन बढ़ता हैं, वहां स्थानीय रोजगार के अवसर खुलते हैं।

कभी यही उत्तर प्रदेश खराब सड़कों के लिए जाना जाता था लेकिन आज सड़कों का ज़बरदस्त नेटवर्क बनाया जा रहा है। योगी सरकार ने राज्य की अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस–वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस–वे की नई परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 235 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के

योगी सरकार की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करने के संकल्प ने गांव–गांव तक उद्योग–धन्धों के जाल तो फैला दिये हैं, लेकिन वहां बने उत्पाद को बाजार देने के लिए सड़कों का होना आवश्यक था। आज बेहतर सड़कें होने से चाहे सब्जियां हों, फल अथवा दूध, आसानी से कम समय में शहरों तक पहुंच रहे हैं और एक्सप्रेस–वे होने से यही उत्पाद आसानी से मण्डी व दूसरे शहरों और आसपास के राज्यों में भी समय से पहुंच जाते हैं। जिससे किसानों–उत्पादकों को उनके उत्पाद का वाजिब मूल्य मिल रहा है।

साथ ही डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रूपये की व्यवस्था, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों से लेकर शहर के मुख्य मार्ग की सड़कों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का काम करवाया गया। आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां सड़कें न हों। इसी तरह आवागमन को और सरल बनाने के लिए एक्सप्रेस–वे का निर्माण कराया गया। इससे ना सिर्फ दूरियां कम हुयीं बल्कि मीलों का सफर आसान हुआ। सच कहा जाये तो एक्सप्रेसवेज ने पूरे उत्तर प्रदेश को सड़क नेटवर्क से जोड़ रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देना और सभी धार्मिक–सांस्कृतिक शहरों को आपस में जोड़ना है। चन्द्रिकादेवी, नैमिषारण्य, विन्ध्यवासिनी देवी जैसे तीर्थस्थलों के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए भी सुगम मार्गों की व्यवस्था की जा रही है। कन्नौज के इत्र, वाराणसी की बनारसी साड़ियां, भदोही कालीन उद्योग, मुरादाबाद के पीतल उद्योग, अलीगढ़ के ताला उद्योग, सहारनपुर के लकड़ी उद्योग तथा राजधानी लखनऊ के चिकन उद्योग को निर्यात के लिए बेहतर बाज़ार दिलवाना सरकार की शीर्ष प्राथमिताओं में शामिल है।

उत्तर प्रदेश में पिछले छह वर्षों में ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनीं बल्कि उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस–वे वाला देश का पहला राज्य बन गया। जहां छह एक्सप्रेस–वे संचालित हैं और सात पर काम चल रहा है। इनकी लम्बाई कुल 32 सौ किलोमीटर की है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल यमुना एक्सप्रेस–वे–165 किलोमीटर, नोएडा–ग्रेटरनोएडा एक्सप्रेस–वे–25 किलोमीटर, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे–302 किलोमीटर, दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे जिसकी लम्बाई 96 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे 296 किलोमीटर

का है। यह सभी छह एक्सप्रेस–वे 1225 किलोमीटर के है। अभी सात एक्सप्रेस–वे निर्माणाधीन हैं जिसमें–गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे–91 किमी, गंगा एक्सप्रेस–वे–594 किमी, लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस–वे 63 किमी, गाज़ियाबाद–कानपुर एक्सप्रेस–वे 380 किमी, गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेस–वे 519 किमी, दिल्ली–सहारनपुर–देहरादून एक्सप्रेस–वे 210 किमी, गाज़ीपुर–बलिया–मांझीघाट एक्सप्रेस–वे–117 किमी का है। ये सभी एक्सप्रेस–वे की कुल 1974 किमी के हैं। इनके निर्माण से दूरियां कम होंगी और समय भी बचेगा। एक्सप्रेस–वे से सामाजिक और आर्थिक विकास तो होगा ही साथ ही कृषि, पर्यटन, वाणिज्य और उद्योगों की आय को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जलमार्ग से परिवहन, वायुमार्ग से परिवहन की सुविधाओं पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। योगी सरकार के जन–जन तक विकास पहुंचाने के संकल्प को इससे पंख लगेंगे। इतिहास गवाह हैं कि विकास की किरण से कोई भी अछूता नहीं बचता।

योगी सरकार की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करने के संकल्प ने गांव–गांव तक उद्योग–धन्धों के जाल तो फैला दिये हैं, लेकिन वहां बने उत्पाद को बाज़ार देने के लिए सड़कों का होना आवश्यक था। आज बेहतर सड़कें होने से चाहे सब्ज़ियां हों, फल अथवा दूध, आसानी से कम समय में शहरों तक पहुंच रहे हैं और एक्सप्रेस–वे होने से यही उत्पाद आसानी से मण्डी व दूसरे शहरों और आसपास के राज्यों में भी समय से पहुंच जाते हैं। जिससे किसानों–उत्पादकों को उनके उत्पाद का वाजिब मूल्य मिल रहा है।

योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते ही नौकरशाही को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स की नीति से उनकी सरकार काम करेगी। जिसका नतीज़ा रहा कि जो भी योजनाएं बनीं उन पर बिना हीला–हवाली के काम हुआ और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। विकास की रफ्तार बढ़ी और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर बिना रूके दौड़ता चला जा रहा है। •

मो. : 9415464591

ग्रामीण पर्यटन : मनोरंजन के साथ रोज़गार भी

–प्रदीप श्रीवास्तव

देश व राज्यों की अर्थव्यवस्था के विकास में पर्यटन उद्योग एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो पिछले छह दशक में भारत में पर्यटन में काफी तेज़ी से वृद्धि हुई है।सन 1951 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या मात्र 17 हजार थी, वहीं आज 7 मिलियन से कहीं अधिक है। जबकि दूसरी तरफ विदेश घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों की अनुमानित संख्या 14 मिलियन को पार कर रही है। मज़े की बात तो यह है कि इन पर्यटकों में हिंदी भाषी ही सर्वाधिक हैं।

ग्रामीण पर्यटन, पर्यटन का वह रूप जो ग्रामीण स्थलों पर ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता है जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभ होता है और साथ ही, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच अधिक समृद्ध पर्यटन अनुभव के लिए बातचीत को सक्षम बनाता है, इसे 'ग्रामीण पर्यटन' कहा जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन बहुआयामी है और इसमें कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्रकृति पर्यटन, साहसिक और पारिस्थितिकी पर्यटन शामिल हैं, जो सभी निकटता से जुड़े हुए हैं। साढ़े छह लाख से अधिक गाँवों में से प्रत्येक के पास अपनी अनूठी कहानी, विरासत और संस्कृति है जिसे पर्यटकों के साथ साझा किया जा सकता है।

भारतीय सभ्यता के विकास में विविधतापूर्ण और मिश्रित संस्कृति का योगदान हमारे देश की 68.84 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है वर्ष 2011 की जनगणना के

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन को प्रगति के पंख लगाने के लिए कई कदम उठा रही सरकार की नज़र अब परंपरा और संस्कृति की धरोहर सहेजे गांवों पर है। प्रदेश में पहली बार ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने की कई योजनाएं पर्यटन विभाग ने बनाई हैं। मूलभूत सुविधाओं के विकास से गांवों शहरों का फासला बढ़ता जा रहा है, पर्यटन विभाग ने इसे पाटने के लिए ग्रामीण पर्यटन की पहल की है। इस पहल के ज़रिए जहां गांव का रहन–सहन पहनावा आदि से लोग पूरी तरह से परिचित होंगे वहीं गोपालन जैसे व्यवसाय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे।

आंकड़ों के अनुसार लगभग 45 करोड़ भारतीय देश के अंदर ही एक स्थान से जाकर दूसरी जगह पर बसे हैं। स्वदेश में ही प्रवास करने वालों का 156 प्रतिशत हिस्सा यानी 7.8 करोड़ भारतीय गाँवों से जाकर शहरी क्षेत्रों में बस गए। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत में देश के अंदर ही प्रवास करने वालों की संख्या विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश अमेरिका की आबादी से अधिक है। सन् 2008 के बाद देश में ग्रामीण पर्यटन का प्रचलन तेजी बड़ा, जिसके लिए केंद्र के साथ–साथ राज्य सरकारों का भी बहुत योगदान है। ग्रामीण पर्यटन के प्रति लोगों में रुझान पैदा होने का मुख्य कारण यह हो सकता है कि सन् 2000 के बाद लोग अपने गांवों से कटने लगे। जब कि देश की आधी आबादी से अधिक लोग वहीं से आते हैं। आधुनिकता की चकाचौंध में लोगों ने गांवों को छोड़ कर कंक्रीट के जंगलों की ओर रुख़ कर लिया। जबकि भारत का बड़ा हिस्सा ग्रामीण है और एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत में गाँव का जीवन वह है जहाँ आप वास्तविक भारत से मिलते हैं। इसलिए, ग्रामीण पर्यटन में ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की एक उच्च क्षमता है, क्योंकि यह अन्य गतिविधियों जैसे नौकरियों के सृजन और प्रतिधारण, नए व्यवसाय के अवसरों का निर्माण, स्थानीय कला और शिल्प के पुनरोद्धार के साथ जुड़ा हुआ है। ''आत्मनिर्भर भारत'' की दृष्टि और ''लोकल के लिए वोकल'' के मंत्र के साथ भी।

ग्रामीण पर्यटन एक ऐसी गतिविधि है जो गैर–शहरी क्षेत्रों में होती है जो ग्रामीण स्थानों पर कला, संस्कृति, विरासत और मूल जीवन को प्रदर्शित करती है। ऐसी गतिविधियां जिनमें आगंतुक प्रकृति और कृषि से जुड़े उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करते हैं जैसे कि खेती, मत्स्य पालन, शिल्प और ग्रामीण जीवन शैली के विभिन्न पहलू।

एक पुरानी कहावत है 'कोस–कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी।' भारतीय संस्कृति की ऐसी विविधता को अब भुनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन को प्रगति के पंख लगाने के लिए कई कदम उठा रही सरकार की नजर अब परंपरा और

संस्कृति की धरोहर सहेजे गांवों पर है। प्रदेश में पहली बार ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने की कई योजना पर्यटन विभाग ने बनाई हैं। मूलभूत सुविधाओं के विकास से गांवों शहरों का फासला बढ़ता जा रहा है पर्यटन विभाग ने इसे पाटने के लिए ग्रामीण पर्यटन की पहल की है। इस पहल के जरिए जहां गांव का रहन—सहन पहनावा आदि से लोग पूरी तरह से परिचित होंगे वहीं गोपालन जैसे व्यवसाय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम के मुताबिक देश में सर्वाधिक गांवों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में कृषि और ग्राम्य पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हम गांवों में उन्नत कृषि, गो—पालन, शिल्पकारी, हथकरघा, हस्तशिल्प, विशिष्ट शुद्ध भोजन, जैव एवं कृषि विविधता आदि के साथ—साथ अपनी समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और उसके प्रचार— प्रसार का काम शुरू कर रहे हैं।

पर्यटन सचिव के मुताबिक पहले चरण में 18 जिलों के लिए कार्यदायी संस्थाओं का चयन कर लिया गया है। इन संस्थाओं की ओर से प्रत्येक जिले से दो गांवों का चयन करके सर्वेक्षण किया जाएगा। उन गांवों में ग्राम्य पर्यटन की अवधारणा को साकार करने के लिए योजना तैयार की जाएगी। सरकार का मानना है कि ग्राम्य पर्यटन के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी ग्रामीण परंपरा और संस्कृति से परिचित हो सकेगी। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और गांवों का चहुंमुखी विकास भी होगा।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 75 ग्रामों को दो वर्ष की अवधि में ग्राम्य पर्यटन के लिए चयनित कर विकास किया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा कृषि एवं ग्राम्य पर्यटन की अवधारणा को साकार करने के लिए 18 मण्डलों से क्लस्टर के रूप में विकसित करने के लिए 229 गांव चयनित किये गए हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित गांवों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पर्यटकों को गांवों की तरफ आकर्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को चिन्हित किया गया है।

उन्होंने बताया कि हमारा प्रदेश सांस्कृतिक विविधता, खान—पान, वेशभूषा, स्थानीय क्राफ्ट, हस्तशिल्प तथा विभिन्न विशेषताओं से भरा हुआ है। इस योजना से पर्यटकों को ग्रामीण जीवन को करीब से देखने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत एवं प्राकृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। ग्रामीण पर्यटन को लोकप्रिय बनाने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों का आर्थिक विकास और स्थानीय रोजगार सृजन के साथ ग्रामीणों की आमदनी को बढ़ाना है।

देश के युवाओं को ग्रामीण संस्कृति से रूबरू कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अभियान शुरू किया हुआ है जिसके चलते पहले चरण में जिन 18 गांवों का चयन किया गया है, वहां ग्रामीण पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आप इन गांवों में जाकर ग्रामीण संस्कृति और गांवों की मिट्टी की सोंधी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। आप ग्रामीण परिदृश्य में अपना कुछ समय आराम से व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश के ऐसे गांवों का चयन किया गया है जहां पर खेती के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता भी मौजूद है। यहां के ग्रामीण, शिल्पकला बुनाई जैसे कार्यों में पारंगत हैं। इसके साथ ही इन्हीं गांवों में महापुरूषों और संतों की जन्म स्थली भी हैं।

प्रदेश के युवाओं को ग्रामीण संस्कृति से रूबरू कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अभियान शुरू किया हुआ है जिसके चलते पहले चरण में जिन 18 गांवों का चयन किया गया है, वहां ग्रामीण पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आप इन गांवों में जाकर ग्रामीण संस्कृति और गांवों की मिट्टी की सोंधी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप ग्रामीण परिदृश्य में अपना कुछ समय आराम से व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश के ऐसे गांवों का चयन किया गया है जहां पर खेती के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता भी मौजूद है। यहां के ग्रामीण, शिल्पकला बुनाई जैसे कार्यों में पारंगत हैं। इसके साथ ही इन्हीं गांवों में महापुरूषों और संतों की जन्म स्थली भी हैं।

आज गांवों और शहरों के बीच फासला बढ़ता जा रहा है, जिसे पाटने के लिए ही पर्यटन विभाग ने ग्रामीण पर्यटन की पहल की है। जिसके चलते गांव का रहन–सहन पहनावा आदि से लोग पूरी तरह से परिचित होंगे वहीं गोपालन जैसे व्यवसाय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। जब गांवों में बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो उससे गांवों में रहने वाले लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।

जिन 18 गांवों का चयन हुआ है उनमें प्रमुख हैं आगरा का आवल खेड़ा गांव गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक आचार्य श्री रामचंद्र शर्मा का जन्म स्थान है, फिरोजाबाद का अकबरपुर हनुमान भक्त बाबा नीम करोली महाराज की जन्मस्थली मालपुआ, मथुरा का परसौनी गांव सूरदास की तपोस्थली, वाराणसी का लीला स्थल मुक्त काशी मंच, अलीगढ़ का नया बांस हस्तनिर्मित दरियों के बुनकरों का गांव, वाराणसी का तारापुर गांव लकड़ी के खिलौने व टेराकोटा की शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध, बस्ती का काशीपुर अयोध्या का नंदीग्राम कोटवा धाम बाराबंकी का एवं बटवारा लखनऊ का गांव सहित 18 गांवों को शामिल किया गया है। सरकार की इस इस मुहिम का मकसद गांवों में पर्यटन के साथ ही रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है जिसके चलते गांवों से होने वाले पलायन को भी रोका जा सके।

ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा 2002 में शुरू हुई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने योजना आयोग के जरिये भारत में ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने के लिये एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण पर्यटन मुख्य प्राथमिकताओं में से एक रहा। इस काल में 69 ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। पर्यटन पर कार्य समूह (2011) की रिपोर्ट के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में ₹770 करोड़ के सालाना व्यय से देश भर में 70 ग्रामीण पर्यटन स्थल समूहों के विकास का कार्यक्रम बनाया गया।

भारतीय ग्रामीण पर्यटन के लिए भारत सरकार की पहल पर पर्यटन मंत्रालय ने स्थानीय निवासियों को विदेशी आगंतुकों के साथ किये जाने वाले उचित बर्ताव और शिष्टाचार के बारे में बताने के लिए 2008 में 'अतिथि देवो भव' अभियान चलाया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 21 फरवरी, 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की शुरुआत की। रुर्बन मिशन आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके चयनित ग्रामीण क्षेत्रों को समूह (क्लस्टर) के रूप में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ बनाने के प्रयास में लॉन्च किया गया ताकि देश सतत और संतुलित क्षेत्रीय विकास की ओर अग्रसर हो सके।

संस्कृति मंत्रालय ने 2017 में सांस्कृतिक मानचित्र पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया। इसके तहत राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम 'हमारी संस्कृति, हमारी पहचान' अभियान के जरिये भारत का सांस्कृतिक मानचित्रण किया जा रहा है। सरकार ने 2020 में 'देखो अपना देश' योजना शुरू की। इसका उद्देश्य भारतीयों को अपने देश के हर कोने की यात्रा के लिये प्रोत्साहित करना है। इस योजना को बढ़ावा देने और 'सबके लिये पर्यटन' के संदेश के प्रसार के मकसद से 'पर्यटन पर्व' आयोजित किया गया।

भारत में प्राकृतिक सौंदर्य की अनमोल विरासत है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार देश में 97 संरक्षण रिजर्व, 214 सामुदायिक रिजर्व, 566 वन्यजीव अभयारण्य, 52 टाइगर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 32 हाथी रिजर्व, 467 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन्हें पर्यटन के हिसाब से विकसित और संरक्षित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पर्यटन विभाग ने ग्राम्य पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पर्यटन विभाग ने ग्राम्य पर्यटन को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। पहले चरण के लिए 18 जिले चिन्हित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए 'योगी सरकार' लगातार प्रयासरत है। धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन को प्रगति के पंख लगाने के लिए कई कदम उठा रही सरकार की नज़र अब परंपरा और संस्कृति की धरोहर सहेजे गांवों पर है। प्रदेश में पहली बार ग्राम्य पर्यटन को प्रोत्साहित करने की योजना उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बनाई है। पहले चरण के लिए 18 जिले चिन्हित भी किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि जब गांवों में बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो उससे गांवों में रहने वाले लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड के कैंची धाम एवं लखनऊ के हनुमान सेतु के दर्शन के लिए पहुंचते हैं लेकिन पर्यटन विभाग की इस पहल से लोग बाबा नीम करोली का जन्म स्थान भी देख सकेंगे, ऐसे ही गायत्री पीठ हरिद्वार के संस्थापक आचार्य श्रीराम शर्मा की जन्मस्थली की देख पाएंगे। थारो कला के लिए चर्चित गांव को भी संवारा जाएगा। पर्यटकों के लिए ग्रामीणों के घर पर ही आवास की व्यवस्था करेंगी, ग्रामीणों के घरों को व्यवस्थित किया जाएगा साथ ही बिजली पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। पता हो कि पहले चरण में 18 जिलों के लिए कार्यदायी संस्थाओं का चयन कर लिया गया है। इन संस्थाओं की ओर से प्रत्येक जिले से दो गांवों का चयन करके सर्वेक्षण किया जाएगा। उन गांवों में ग्राम्य पर्यटन की अवधारणा को साकार करने के लिए योजना तैयार की जाएगी। सरकार का मानना है कि ग्राम्य पर्यटन के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी ग्रामीण परंपरा और संस्कृति से परिचित हो सकेगी। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और गांवों का चहुंमुखी विकास भी होगा। •

मो. : 8707211135

हर घर जल योजना से स्वच्छ जल की सौगात

—विदर्भ कुमार

देश की ग्रामीण आबादी के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ऐसा वरदान है जो इनकी पेयजल की कठिनाइयों को पूरी तरह दूर कर रहा है। आजादी के बाद मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ग्रामीण परिवारों की पेयजल व्यवस्था की बड़ी कठिनाई को समझा, उस पर गंभीरता से चिंतन किया और निदान के लिये जल–जीवन मिशन को मूर्तरूप दिया। लक्ष्य प्राप्ति की तीव्र गति से गतिमान योगी सरकार 50 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है।

समय साक्षी है संकल्प की प्रत्यंचा से बुन्देलखण्ड के सूदूर पठारी गांव में जीवन को अनमोल जल नल से मिलना आनंदित कर देने बाला क्षण बना है। देश की ग्रामीण आबादी के लिए राष्ट्रीय जल–जीवन मिशन ऐसा वरदान है जो इनकी पेयजल की कठिनाइयों को पूरी तरह दूर कर रहा है। आजादी के बाद मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ग्रामीण परिवारों की पेयजल व्यवस्था की बड़ी कठिनाई को समझा, उस पर गंभीरता से चिंतन किया और निदान के लिये जल जीवन मिशन को मूर्तरूप दिया। लक्ष्य प्राप्ति की तीव्र गति से गतिमान योगी सरकार 50 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है। जल जीवन के लिए जरूरी है सर्दी, गर्मी अथवा वर्षा का प्रभाव झेलकर भी पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण परिवारों में पेयजल की व्यवस्था की जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर रहती है। नदी, तालाब, कुआँ, पोखर, हैण्डपंप जैसे पानी के स्त्रोत कितनी भी दूर हों लेकिन पानी लाने का काम माँ, बहन और बेटियों को ही करना होता है। इन्हें अब राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के माध्यम से घर पर ही नल से जल मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार द्वारा प्राप्त की गयी उपलब्धि में बुंदेलखंड और विन्ध्य के 9 जिलों के दुरूह इलाके भी शामिल हैं। बुंदेलखंड के सात जिलों में 'हर घर जल योजना' से करीब 11,78,927 ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल की धार पहुंच रही है। नल कनेक्शन देने के मामले में बुंदेलखंड का महोबा जिला नम्बर एक पर है। महोबा में 91.88 फीसदी ग्रामीण परिवारों तक हर घर जल पहुंचा दिया गया है। विन्ध्य में भी योजना से 4,74,244 ग्रामीण परिवारों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। पूर्वांचल के 27 जिलों में 80,26,883 ग्रामीण परिवारों के कुल 4 करोड़ 81 लाख से अधिक ग्रामीणों तक हर घर नल से जल पहुंच रहा है। इसी प्रकार से पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में योजना से 63,28,887 ग्रामीण परिवारों को जीवन मिशन की हर घर जल योजना से स्वच्छ जल की सौगात मिल गई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने योजना की इस उपलब्धि

पर अधिकारियों से उम्मीद जताई है और साथ में आह्वान भी किया है कि निर्धारित समय से पहले यूपी में हर घर जल योजना के लक्ष्य को पूरा कर देश के सामने एक मिसाल कायम करें।नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ओर से राज्य में ''एक नल–एक पेड़'' अभियान का शुभारंभ किया। वृक्षारोपण कर जल समिति की महिलाओं व नल कनेक्शन दिए जाने वाली ग्रामीण महिलाओं को उपहार स्वरूप पौधे भेंट किये। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा यूपी में 50 फीसदी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने और एक पेड़–एक नल अभियान हरित क्रान्ति में सहभागी बन रहा है। जल है तो कल है। भागीरथी प्रयास से नित्य स्नान, ध्यान, पूजन में सुखद अनुभूति कराने वाला जीवन अमृत जल के प्रति संवेदनशील पहल को देखने आयी भारत सरकार की टीम ने बांदा में ग्राम पंचायत लुकतरा में तालाब के निरीक्षण के साथ परंपरागत जल स्रोतों के प्रोत्साहन के लिए किये जा रहे कुआं पूजन कार्यक्रम की सराहना की। महोबा की किडारी, काली पहाड़ी और अंतरार माफ ग्राम पंचायतों में नवनिर्मित अमृत सरोवर तालाबों को देखा। यहां सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के लाभार्थियों से बातचीत की। पपरेन्दा ग्राम पंचायत में रुफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सोकपिट और मवई बुजुर्ग ग्राम पंचायत में गोसाई तालाब का स्थलीय निरीक्षण किया। हमीरपुर में गुन्देला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से जन–संवाद किया और यहां निर्मित अमृत सरोवर भी देखा। उल्लेखनीय है अटल जलशक्ति यात्रा के प्रथम चरण का आयोजन 24 मई, 2023 से 25 मई, 2023 तक सर्वप्रथम बुदेलखण्ड क्षेत्र के चयनित जनपदों से प्रारम्भ कि गयी थी जिसके द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आच्छादित 350 ग्राम पंचायतों में से लगभग 108 ग्राम पंचायतों में अटल जलशक्ति यात्रा के माध्यम से जल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों को कार्यक्रम से जोड़ते हुये ग्राम पंचायत में पानी मेरा जिम्मेदारी मेरी को संयोजन के लिये प्रेरित किया गया है। अटल भूजल

योजना का मुख्य स्त्रोत चयनित क्षेत्रों में गिरते भूगर्भ जल को घटने से रोकने और संवर्धन के लिये कार्य करना है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में भूजल के स्तर को राज्य एवं केन्द्र सरकार को विभिन्न योजनाओं के अभिचरण के माध्यम से समुदाय के नेतृत्व में उचित निवेश/प्रबन्धन कार्यों में लागू कर उद्देश्यों को प्राप्त करना है। भूजल की समस्या को दूर करने के लिये अटल भूजल योजना प्रदेश के 10 जनपदों को 26 विकास खण्डों की 550 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है। योजना के प्रमुख पहलुओं में से मुख्य है, समुदाय में जल उपयोग एवं प्रबंधन के प्रति व्यावहारिक बदलाव लाना, प्रचार–प्रसार तथा दृष्टिकोण परिवर्तन से जनमानस में भूगर्भ जल के प्रति महत्वपूर्ण सोच विकसित होगी जिससे वो भूगर्भ जल प्रबंधन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। द्वितीय चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों बागपत, मुजफ्फरनगर तथा मेरठ में संचालित किया गया।

यात्रा में जनपद स्तर में प्रभात–फेरी, गोष्ठी का आयोजन, जल स्रोतों पर श्रमदान व वृक्षारोपण तथा जनपद में जल संरक्षण के प्रति कार्य कर रहे व्यक्तियों से सम्पर्क कर ''पानी मेरा जिम्मेदारी मेरी'' को बढ़ाने के लिये प्रेरित किया।

मो. : 7807354095

खेलो इंडिया से खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

–सरिता त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स–2022 देश के युवाओं में टीम स्प्रिट तथा एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने का उत्तम माध्यम बना है।

यही नहीं, उत्तर प्रदेश देश भर की युवा खेल प्रतिभाओं का संगम भी बना। विगत 09 वर्षों में भारत में खेलों का नया युग शुरू हुआ। यह विश्व में भारत को एक बड़ी खेल शक्ति बनाने के साथ ही, समाज के सशक्तीकरण के नये युग की शुरुआत भी है।

मई 23 और तीन जून....ये दोनों दिन राज्य के खेल इतिहास में दर्ज़ हो गए। बारह दिनों तक लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर और दिल्ली में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का मेला लगा रहा। पूरा राज्य खेलों में डूबा रहा। राज्य के इतिहास में पहली दफा खेलों का इतना भव्य आयोजन आयोजित हुआ। पूरे देश की रिकार्ड 207 यूनिवर्सिटी के रिकार्ड 4700 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों की अलग–अलग स्पर्धाओं में दमखम दिखाया। एक से एक अत्याधुनिक सुविधाओं वाले खेल स्थल, खेलने के लिए बढ़िया उपकरण, रहने की होटलों जैसी सुविधा, आवागमन के लिए लक्जरी बसें और कारें, बढ़िया भोजन...जो भी खेलने आया वह उत्तर प्रदेश की मेजबानी देखकर वाह...वाह कर उठा।

राज्य में यूं तो इससे पहले भी राष्ट्रीय खेल जैसे आयोजन हो चुके हैं पर वह उतने भव्य नहीं थे। इसके बाद साल 2016 में हॉकी का जूनियर विश्वकप आयोजित किया गया। पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात ही कुछ अलग थी। करीब पांच माह की लम्बी तैयारी के बाद इन खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन इतिहास रच गया। हर आयोजन स्थल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य लुक दिया गया। गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में रग्बी का नया मैदान तैयार किया गया। फुटबाल के लिए भी घास का बेहतरीन मैदान मुहैया कराया गया। एथलेटिक्स के लिए स्पोर्ट्स

कॉलेज का सिंथेटिक ट्रैक स्टेडियम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का आभास दे रहा था। वहीं स्पोर्ट्स कॉलेज के ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम ने खूब वाह–वाही लूटी। यहां महिला और पुरुषों की हॉकी के मुकाबले हुए। हॉकी स्टेडियम में बैठकर मैच देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय मैच के गवाह बन रहे हों।

इकाना स्पोर्ट्स सिटी में पहली दफा हुईं कई खेल प्रतियोगिताएं

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में इकाना स्टेडियम की खास पहचान है। क्रिकेट के अलावा महिला फुटबॉल, तलवारबाजी, बॉलीबॉल, टेनिस जैसे खेलों के पहली दफा मुकाबले हुए। इकाना स्पोर्ट्स सिटी के इण्डोर हाल में तलवारबाजी और वॉलीबाल की प्रतियोगिताएं हुईं। यही नहीं टेनिस के भी मुकाबले भी यहीं हुए। इकाना स्टेडियम की सुविधाओं को जिसने भी देखा वह हैरत में पड़ गया। वुडेन फ्लोरिंग पर बिछी सिंथेटिक मैट पर वॉलीबाल मुकाबलों में खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव हासिल हुआ। वहीं तलवारबाज़ी की सुविधाओं के कहने ही क्या थे।

नौकायन के नक्शे पर छाया गोरखपुर

गोरखपुर देश के नौकायन नक्शे पर आ गया। यहां के रामगढ़ ताल में नौकायन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। यह नौकायन का बड़ा सेंटर बनकर उभरा है। नौकायन संघ और अन्य राज्यों से आए तकनीकी अधिकारियों ने रामगढ़ ताल की सुविधाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बताया। यहां नौकायन का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र बनने की पूरी संभावनाएं हैं।

रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष एवं भारतीय ओलंपिक संघ की उपाध्यक्ष राजलक्ष्मी सिंह देव को रामगढ़ ताल को देखकर इतनी गदगद हो गईं कि उन्होंने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश को नौकायन की एक बड़ी मेजबानी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी देश में पुणे, हैदराबाद और भोपाल में ही रोइंग कोचिंग सेंटर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल को जिस तरीके से संवारा है, भव्य वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, उसे हम उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे उत्तर भारत में रोइंग की ट्रेनिंग के लिए बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। यहां और भी नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल प्रतियोगिता हो सकती है।

वाराणसी की मेजबानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी ने भी बास्केटबॉल, योगासन, कुश्ती जैसे खेलों की मेजबानी की। इसके अलावा वाराणसी में ही इन खेलों का समापन हुआ। वाराणसी में समापन समारोह का भव्य आयोजन होना था। ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना के कारण समापन समारोह को भव्यता नहीं प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सम्पूर्ण आयोजन समिति कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इन खेलों के सफल आयोजन के लिए बेहद खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही है। राज्य में खेलों का इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा आयोजन इससे पहले कभी नहीं हुआ था। समापन समारोह शाम 7 बजे गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन समारोह के ख़ास मेहमान थे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीत प्रमाणिक भी मौजूद रहे। विजेता विश्वविद्यालयों को ट्रॉफियां भी वाराणसी में ही दी गईं।

खिलाड़ियों को मिली उनकी पसंद की खुराक

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बहाने राज्य के लोगों को ख़ासा रोजगार भी मिला। खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों को लगाया गया। चाहे वह वालेंटियर हों या विभिन्न कार्यों के वेण्डर। चाहे फूल वाला हो या ब्राडिंग वाला। इसके अलावा खिलाड़ी जहां एक ओर मैदान पर पसीना बहा रहे हैं तो दूसरी ओर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान दी जा रही खुराक काबिले तारीफ है। खिलाड़ियों ने एक से एक लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। खिलाड़ियों को बायो डिग्रेडेबल प्लेट्स में खाना परोसा गया। खिलाड़ियों को तरोताज़ा रखने और पौष्टिक व्यंजन परोसे गए। परोसे जाने वाले खाने में खिलाड़ियों की पसंद और नापसंद का भी ख़ास ख़्याल रखा गया है। इस आयोजन में मुंबई की कंपनी खिलाड़ियों से लेकर खेल प्रशासकों, खेल अधिकारी एवं खेलों का संचालन कर रहे लोगों के अलावा स्थानीय सहयोगी संस्था खासकर पुलिस और मेडिकल स्टाफ के लिए भी भोजन की सारी व्यवस्था की गई। हर दिन करीब 6500 लोगों को दिन–रात का भोजन, नाश्ता परोसा गया।

अगले साल फिर मिलेंगे वायदे के साथ ख़त्म हुए गेम्स

खिलाड़ियों ने 'अगले साल फिर मिलेंगे' वायदे के साथ लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर से विदा ली। लखनऊ में जहां जूडो, तलवारबाजी की प्रतियोगिताएं समाप्त हुईं वहीं गौतमबुद्धनगर में वेटलिफ्टिंग और वाराणसी में योगासन खत्म हुआ। इसी के साथ वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी मे खेलों का भव्य रंगारंग समापन समारोह हुआ। इन खेलों में पिछली दफा पदक तालिका में पहले पांच स्थानों से बाहर रही पंजाब यूनिवर्सिटी इस बार 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक जीतकर सबसे आगे रही। वहीं गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य पदक जीतकर दूसरे नम्बर पर रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय सिर्फ एक कांस्य पदक ही जीत सका। जैन विश्वविद्यालय, बैंगलुरू ने 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इस सूची में पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला ने 12 गोल्ड, 14 सिल्वर और 8 कांस्य के साथ चौथा जबकि गुरु काशी विश्वविद्यालय–पंजाब ने 9 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जैन यूनिवर्सिटी को छोड़कर ओवरआल तालिका में शामिल शीर्ष–5 विश्वविद्यालयों में से चार उत्तर भारत के हैं। जैन विश्वविद्यालय ने केआईयूजी के 2021 संस्करण में 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य के साथ पहला स्थान हासिल किया था जबकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी–जालंधर को 17 स्वर्ण, 15 रजत और 19 कांस्य के साथ दूसरा स्थान मिला था।

पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ने 15 स्वर्ण, 9 रजत और 24 कांस्य के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था लेकिन इस बार उसने अपने प्रदर्शन को काफी ऊंचा उठाया और तीसरे से पहले स्थान पर पहुंच गया। इसी तरह पिछले संस्करण में जीएनडीयू, अमृतसर 14 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य के साथ चौथे स्थान पर रहा था लेकिन इस बार उसने दो स्थान की छलांग लगाई है। बीते संस्करण में एमडीयू, रोहतक (14 स्वर्ण, 14 रजत, 13 कांस्य) पांचवें स्थान पर था लेकिन इस बार वह इस फेहरिस्त से गायब है।

भीषण गर्मी के बावजूद मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने दिया उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय : योगी

25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश के चार शहरों में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का वाराणसी में समापन हो गया। इस अवसर पर सीएम योगी स्वयं उपस्थित रहे। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के कारण सीएम के निर्देश पर समापन समारोह को सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि खिलाड़ियों ने गर्मी की परवाह किए बगैर जिस तरह पूरी तत्परता से इस आयोजन में हिस्सा लिया और मेडल जीते, उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिन्होंने यहां खेल की उत्कृष्ट भावना का परिचय दिया, उनका हृदय

से अभिनंदन करना हूं। विश्वास करता हूं कि अगली प्रतियोगिता में और उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से ये खिलाड़ी मेडल प्राप्त करेंगे। समापन समारोह के दौरान सीएम योगी के सामने कुछ चुनिंदा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के सार के तौर पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। समापन समारोह के अंत में सीएम योगी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व अन्य अतिथियों ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की विजेता टीम पंजाब यूनिवर्सिटी (कुल 69 पदक,26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य), दूसरे स्थान पर रही गुरुनानकदेव यूनिवर्सिटी अमृतसर (कुल 68 पदक, 24 स्वर्ण, 27 रजत, 17 कांस्य) एवं तीसरे स्थान पर रही जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक (कुल 32 पदक, 16 स्वर्ण, 10 रजत,6 कांस्य) को ट्रॉफी प्रदान की।

सीएम ने प्रतिभागी खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह

सीएम योगी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर देश के 108 विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपने कौशल से, अपने सामर्थ्य से प्रधानमंत्री के संकल्पों को एक भारत, श्रेष्ठ भारत के साथ ही खेलो इंडिया अभियान को जो गति दी है वह अत्यंत ही अभिनंदनीय है। सीएम ने कहा कि 25 मई को इस आयोजन का शुभारंभ हुआ था और इस दौरान जो अनेक प्रतियोगिताएं हुईं, हर एक जगह का समाचार मिलता था। जानकर प्रसन्नता हुई कि युवाओं के मन में, आम नागरिकों के मन के मन में प्रतियोगिताओं के प्रति अपार सकारात्मक रुख था। यह हम सभी के लिए एक अविस्मरणीय क्षण था और इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता और इसकी सफलता, इन युवाओं के उत्साह, खेल के प्रति उनके समर्पण, प्रधानमंत्री के संकल्पों को मजबूती प्रदान करने में दिख रहा था। इस अवसर पर जिन भी खिलाड़ियों ने इस पूरे आयोजन में भाग लिया है, जिन्होंने मेडल जीता है, उन सभी को धन्यवाद देता हूं। सीएम योगी ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि भीषण गर्मी में इन खेलों का आयोजन हो रहा था तो एक चिंता भी थी। यद्यपि हमारी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम को फरवरी या मार्च में करें, लेकिन उस समय नगर निकाय इलेक्शन की तैयारी चल रही थी। जब चुनाव संपन्न हुए उसके बाद यह खेल यहां पर एक बहुत शॉर्ट नोटिस में बेहतरीन तरीके से संपन्न हुए हैं।

यूपी के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है बड़ा बदलाव

सीएम योगी ने कहा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा एक नई ऊंचाइयों को छूती हुई दिखाई दे रही है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स,या फिर कोई राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, पिछले 9 वर्षों के अंदर भारत के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करने और मेडल प्राप्त करने का रेट बढ़ा है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य इस दौरान हुए हैं वह हर एक व्यक्ति के लिए उत्साहजनक है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से डबल इंजन की सरकार लगातार इस पर कार्य कर रही है। आज सभी ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान बनाया जा रहा है। हर विकासखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर स्टेडियम के निर्माण की कार्यवाही चल रही है। गांव में खेल के मैदान के पास और शहरी क्षेत्र में किसी पार्क में ओपन जिम के निर्माण की कार्यवाही हो रही है तो ग्रामीण क्षेत्र में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने के कार्य भी हो रहे हैं। अब तक 65000 से अधिक स्पोर्ट्स किट उत्तर प्रदेश के युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। हम सब प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़कर खेल के माध्यम से भारत के सामर्थ्य को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उसका एक उदाहरण है। •

मो. : 9415650340

डीबीटी से मिला
अभिभावकों को सम्मान
बच्चों के चेहरों पर आयी मुस्कान
1200/-
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोज़ा, कॉपी एवं स्टेशनरी क्रय हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए शिशिर, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा
प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित, सम्पादक– **कुमकुम शर्मा**